प्रकाशन तिथि : 20 मई, 2021 ❋ वर्ष-30, पृष्ठ संख्या 60, अंक-5

राजस्थान सुजस

#राजस्थान_सतर्क_है

'नो मास्क, नो मूवमेंट'

रहट

आलेख व छाया : डॉ. कमलेश शर्मा
उपनिदेशक, जनसम्पर्क

कृषि प्रधान देश में समाज का बड़ा तबका खेती–किसानी से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में किसान अपने खेतों में फसल उगाने के लिए मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। फसल के लिए सबसे जरूरी है सिंचाई। पुराने समय में तो रहट, चड़स तथा ढेंकुली ही सिंचाई के साधन थे। अब तो इनके दर्शन ही दुर्लभ हैं। रहट चडस पद्धति, जिसे पर्शियन विल के नाम से भी जाना जाता है। तक़रीबन 5 हज़ार साल पुरानी है। बताया जाता है कि लकड़ी से भी रहट बनाए जाते थे, डिब्बों के विकल्प के तौर पर मिट्टी की गेड़ों का इस्तेमाल भी होता था। मिट्टी के यह चड़स अभी भी हमें दिखाई देते हैं। चित्र उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र का है जहां पर आज भी सैकड़ों खेतों में इसी प्रकार के रहट से सिंचाई होती है।•

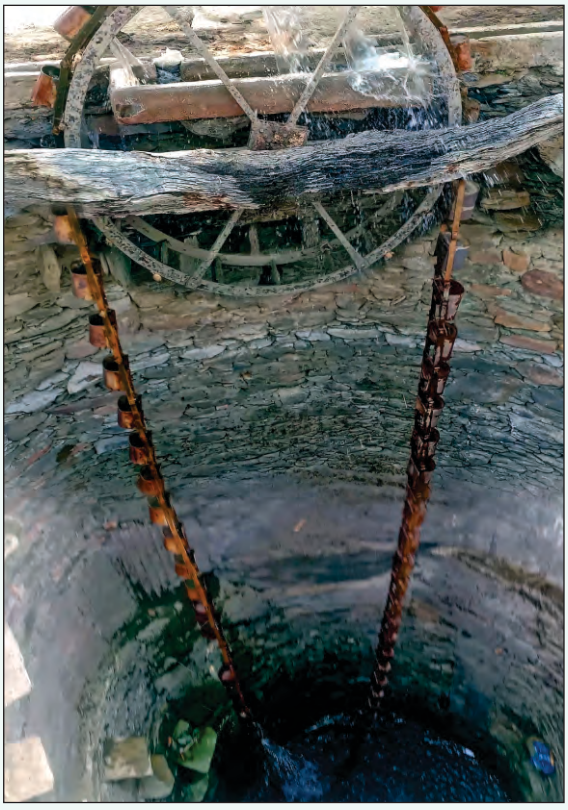

प्रधान सम्पादक
पुरुषोत्तम शर्मा

सम्पादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप सम्पादक
आशाराम खटीक

कला
विनोद कुमार शर्मा

आवरण छाया
पदम सैनी

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

मुद्रण
प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय परिसर
जयपुर - 302 005
e-mail :
publication.dipr@rajasthan.gov.in
editorsujas@gmail.com
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 30 अंक : 05 **मई, 2021**

इस अंक में

आवरण कथा

05

बातचीत

28

लोक रंग

42

लोक जीवन	02
सम्पादकीय	04
कल्याणकारी योजनाएं	20
नगर विकास	24
कोरोना प्रबन्धन	27
स्मृति-शेष	29
स्वास्थ्य	32
खेत-खलिहान	34
लोकतंत्र	35
चिरंजीवी बीमा योजना	36
इतिहास पुरुष	38
खेल-खिलाड़ी	40
पेयजल	41
ग्राम्य विकास	44
चिकित्सा शिक्षा	45
कायाकल्प	46
नवाचार	47
सामयिकी	48
विद्यालय शिक्षा	52
वन जीवन	54
प्राकृतिक सम्पदा	56
धरोहर	60

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

साक्षात्कार

22

फोटो फीचर

30

राज्य विश्वविद्यालय

50

कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार के संवेदनशील कदम

वैश्विक महामारी कोविड-19 की पहली लहर को झेल चुके राजस्थान में दूसरी लहर का प्रभाव दिखाई दे रहा है। साथ ही तीसरी लहर के संभावित खतरे भी चिंतित कर रहे हैं। इससे बचाव के लिए राज्य की संवेदनशील सरकार द्वारा संवेदनशीलता के साथ सधे हुए कदम उठाये जा रहे हैं। जनहित में अनेक महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। निर्णयों में उच्च कोटि का कुशल प्रबंधन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है।

कोरोना वायरस जांच दरों में कमी, ऑक्सीजन उत्पादन के लिए उद्यमियों, स्थानीय निकायों और किसानों को रियायतें, ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी व जमाखोरी पर नियन्त्रण के लिए कठोर कदम, सरकारी खर्च पर मृत व्यक्तियों का ससम्मान अंतिम संस्कार, अस्थि विसर्जन के लिए परिजनों को रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयों से आमजन को इस विपदा काल में राहत मिली है। 18 से 44 वर्ष के आयुवर्ग के युवाओं को कोरोना का टीकाकरण नि:शुल्क कराने के मुख्यमंत्री के निर्णय ने लोगों में टीका लगाने के प्रति उत्साह को बढ़ा दिया है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेशवासियों के इलाज के लिए बेहतर कदम साबित हो रही है। लॉकडाउन के दौरान आमजन के लिए आवश्यक वस्तुओं की दुकानें एक निश्चित समय में प्रतिदिन खोलने का निर्णय भी आमजन के लिए राहत देने वाला है।

'राजस्थान सुजस' राज्य सरकार की पत्रिका है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा यह पत्रिका गत तीस वर्षों से प्रकाशित की जा रही है। लोकजीवन, धरोहर, इतिहास पुरूष के साथ खेत-खलिहान, लोकरंग, खेल-खिलाड़ी और फोटो फीचर के स्थायी स्तम्भ इस बार के अंक से पुन: शुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। आशा है यह सभी रचनात्मक प्रयास उपयोगी साबित होंगे।

सभी सुधी पाठकों से विनम्र आग्रह है कि इस पत्रिका को अधिक रोचक व ज्ञानोपयोगी बनाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। मई, 2021 के अंक को आपके हाथों में सौंपते हुए मेरा आप सभी से सुझाव देने के लिए भी विनम्र अनुरोध है।

सादर अभिवादन के साथ

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान संपादक

राज्य में 'नो मास्क, नो मूवमेंट' लागू, रिकवरी में हुई बढ़ोतरी

– महेश चंद्र शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार

पिछले साल वैश्विक महामारी कोविड-19 की मार झेल चुके राजस्थान में, एक बार फिर से इसकी दूसरी लहर ने इन दिनों भीषण कहर बरपा रखा है। उस पर तीसरी लहर के संभावित संकट का खतरा अलग चिंतित कर रहा है। ऐसे खतरों को भांपते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में तत्काल ऐसे प्रभावी कदम उठाए जिनके बूते अब संक्रमण की तीव्रता में गिरावट आने लगी है।

ऐसे संकटपूर्ण माहौल में, विधानसभा के बजट-सत्र के दौरान राज्य का वार्षिक बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा सुनाए गए शेर की वह पंक्तियां अचानक स्मरण-पटल पर गूंजने लगती हैं, जिसमें प्रदेश के सामने आने वाले हर संकट की चुनौती देने के साहस का संचार होता है। वह पंक्तियां थीं-'पलट देते हैं हम मौजे-हवादिस अपनी जुर्रत से, कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं।'

यह पंक्तियां सिर्फ कहने या सुनाने भर तक सीमित नहीं है बल्कि इस महामारी की पहली लहर के दौरान पिछले साल किए गए प्रयासों को अमलीजामा देकर पूरी दुनिया के सामने एक मिशाल के रूप में पेश कर दिखाया है। इसका सीधा श्रेय मुख्यमंत्री के शासकीय नेतृत्व और उच्च कोटि के कुशल प्रबंधन को जाता है। इनके द्वारा लिए गए तमाम फैसलों में सुशासन के बुनियादी तत्वों-संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। पिछले साल कोरोना की शुरुआत से ही निरंतर मॉनिटरिंग व माइक्रोप्लानिंग पर जोर दिया गया। 'राजस्थान सतर्क है' की पहल के साथ कोविड-19 की चुनौतियों का सामना किया गया। भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल को अनुकरणीय माना गया था।

इस साल फिर कोविड-19 की दूसरी लहर ने प्रदेश के सामने नई चुनौती पेश की है। इससे निपटने के साथ ही मुख्यमंत्री का इरादा है कि कोरोना-प्रबंधन के लिए पूरे देश में एक बार फिर राजस्थान, मॉडल राज्य के रूप में उभरे। इस क्रम में प्रदेश ने टीकाकरण अभियान में बड़े राज्यों में पहला और देश भर में दूसरा स्थान अर्जित कर लिया है। मुख्यमंत्री की नजर में प्रदेश के हर व्यक्ति की जान कीमती है, जिनकी सुरक्षा का दायित्व शासन का है।

जन –अनुशासन पखवाड़ा और सख्त लॉकडाउन

संक्रमण की दूसरी लहर का कहर अब सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इस बार इसने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी दस्तक दी है। ऐसी भीषण स्थिति में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पहले 'नो मास्क, नो मूवमेंट', फिर रात्रिकालीन कर्फ्यू इसके बाद वीक एण्ड कर्फ्यू तथा जन अनुशासन पखवाड़े के फैसलों के बाद 10 से 24 मई तक प्रदेश में सख्त लॉकडाउन लगाने के सख्त कदम उठाए गये। जिसमें 31 मई तक विवाह समारोह के सार्वजनिक आयोजनों तथा

शहरों से दूसरे शहरों, गांवों से दूसरे गांवों में, गांवों से शहरों और शहरों से गांवों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। बैंड-बाजा-बारात के बिना शादियों का घरों में ही सिर्फ 11 लोगों की मौजूदगी में आयोजन एवं कोर्ट मैरिज की इजाजत दी गई है।

संवेदनशील कदम

कोरोना वायरस की जांच दरों को घटाने, सरकारी खर्च पर मृत व्यक्तियों के ससम्मान अंतिम संस्कार के लिए धनराशि मंजूर की गई। अस्थि-विसर्जन के लिए रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा जैसे संवेदनशील फैसले लिए गए। और तो और प्रदेश में ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए उद्यमियों, स्थानीय निकायों और किसानों को कई रियायतें दी गई हैं। आवश्यक साधन जैसे ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी, जमाखोरी और निर्धारित दरों से अधिक दरों पर बिक्री को रोकने के लिए प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए।

इसके अलावा चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्साकर्मियों, साधनों, उपकरणों को मुहैया कराने के राज्य, संभाग और जिला स्तर पर समुचित प्रबंधन से जुड़े तमाम मसलों पर तत्काल फैसले जवाबदेहिता की मिसाल है। इस क्रम में राज्य के सात नए चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसरों व चिकित्सकों के 105 पदों पर शीघ्र नियुक्ति के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए। 48 नए न्यायालयों में विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। इसके अलावा इस विषम परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कनिष्ठ लिपिक 2018 की प्रतीक्षा सूची से 689 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की घोषणा भी की है। यही नहीं, संविदा सीएचओ भर्ती-2020 की चयन सूची जारी कर दी गई। 7,353 चयनितों को कोरोना नियंत्रण के लिए गृह जिलों या समीपवर्ती जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित किया जा रहा है।

मंत्री-समूहों का गठन

समय-समय पर प्रदेश में वैक्सीन, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने और राज्य की वस्तु स्थिति से केंद्र को अवगत कराने के लिए तीन मंत्रियों एवं सख्त जन अनुशासन पखवाड़ा लागू करने के लिए पांच मंत्रियों का समूह गठित किया गया। जिसमें स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री डॉ. बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा एवं चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग शामिल किए गए। उनसे आवश्यक सुझाव लेकर इस क्रम में सख्त लॉकडाउन लगाने एवं अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े महत्त्वपूर्ण और पारदर्शी फैसले लिए गए।

इसका नतीजा जल्द सामने भी आने लगा है। संक्रमित व्यक्तियों के ठीक होने और संक्रमण की रफ्तार में आ रही कमी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। महामारी की दोनों लहरों की गिरफ्त में राज्य में 15 मई 2021 तक 8 लाख 49 हजार 379 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। इनमें से 6 लाख 34 हजार 70 ठीक हुए। ठीक होने की यह रफ्तार 74.65 फीसदी रही। अब तक प्रदेश में कुल मौतें 6 हजार 621 हुई हैं। 15 मई को नए मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट का दौर रिकॉर्ड किया गया। वहीं ठीक होने वालों की दर में भी बढ़ोतरी हुई है। पहली बार नए संक्रिमतों की संख्या में भी चार हजार से अधिक की गिरावट आई है।

रिकवरी दर बढ़ने लगी

ताजा आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मामलों में 5 मई से निरंतर कमी आने लगी है। नए संक्रमित भी लगातार तीसरे दिन माइनस एक फीसदी की रफ्तार से घटे हैं। विशेषज्ञों की राय है कि पिछले दिनों से चल रहे प्रतिबंधों की वजह से लोग कुछ दिन और सजग रहें तो संक्रमण की चेन टूट सकती है। 8 मई को प्रदेश में पहली बार 15 जिलों-अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, झालावाड़, जोधपुर, करौली, पाली, राजसमंद, सिरोही, टोंक और उदयपुर जिलों में नए रोगियों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक रही। इन जिलों में नए रोगी 7 हजार 4 सौ 38 आए जबकि ठीक होने वालों की

संख्या 10 हजार 8 सौ 92 रही। यानी नए रोगियों की तुलना में रिकवरी 145 फीसदी रही। हालांकि बीते एक दिन में प्रदेश में 17 हजार 9 सौ 87 नए रोगी आए और 17 हजार 667 ठीक भी हुए। यही नहीं पिछले दिनों से प्रदेश में सक्रिय रोगियों की संख्या दो लाख से कम रही है। सक्रिय रोगियों की कुल संख्या 1 लाख 99 हजार 307 पर पहुंची जो 2 लाख से 693 कम है।

चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा के अनुसार 5 मई को कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,815 रही जबकि रिकवरी 17,022 तक जा पहुंची। एक मार्च को संक्रमित मरीजों की संख्या 119 थी जबकि पॉजिटिव से नेगेटिव होने वालों की संख्या 123 थी।

टीकाकरण में राजस्थान अव्वल

मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 18 से 44 आयुवर्ग के नि:शुल्क टीकाकरण की घोषणा से युवा वर्ग में टीका लगाने के प्रति उत्साह बना हुआ है। राज्य में इस आयु वर्ग के करीब 3 करोड़ 75 लाख व्यक्ति हैं। राज्य सरकार टीकाकरण पर करीब 3 हजार करोड़ रुपए व्यय करेगी। 15 मई तक 1 करोड़ 50 लाख 3 हजार 347 डोज लगाई जा चुकी हैं। देश में राजस्थान टीकाकरण में प्रथम स्थान पर है।

मदद की ओर बढ़े हाथ

युवाओं को नि:शुल्क टीकाकरण अभियान के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने मुख्यमंत्री कोष में एक करोड़ रुपये, आईएएस-आरएएस ने दो दिन, वन सेवा के अधिकारियों ने तीन दिन और महिला-बाल विकास सेवा के अधिकारियों ने दो दिन का वेतन देने की घोषणा की है। महामारी से निपटने के लिए विभिन्न कार्यों के निमित्त विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, नगरीय एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल, सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना सहित अनेक मंत्रियों और विधायकों ने विधायक निधि कोष से तथा अनेक सामाजिक संगठनों ने अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि और अन्य साधनों और सुविधाओं को जुटाने की घोषणाएं की हैं।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू

इस दौरान राज्य सरकार का दूसरा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रदेश में आम जन के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करना रहा। पूर्व में पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रेल रखी गई थी, इस दौरान बाईस लाख पिचासी लाख परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। इस योजना को मिले रेस्पांस को देखकर अब इसके पंजीकरण की अवधि 31 मई कर दी गई है। राज्य सरकार निरोगी राजस्थान के संकल्प के साथ राज्य को जीरो कॉस्ट हेल्थ सिस्टम वाले प्रदेश के रूप में विकसित कर रही है। इस योजना को कोविड प्रभावित लोगों की उपचार सुविधा से भी जोड़ा गया है।

नो मास्क, नो मूवमेंट

मुख्यमंत्री ने पिछले साल राज्य में मास्क पहनने की अनिवार्यता वाला कानून बनाया था। जो देश में अन्य राज्यों के लिए नजीर बना था। इस साल अप्रेल माह में फिर से बढ़ते संक्रमण के खतरे को भांपकर, प्रदेश के हर व्यक्ति की जान को कीमती मानते हुए, नागरिकों से बिना मास्क पहने घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। बिना वजह घर से बाहर ना निकलने का सुझाव भी दिया गया। इसकी पुलिस व प्रशासन को कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में बिना वजह घरों से बाहर घूम रहे 19 सौ लोगों को पकड़कर संस्थागत क्वारेंटाइन में भेजा गया है। कोविड अनुशासन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर 47 हजार चालान किए गए हैं।

कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद प्रशासन को मुस्तैद रखा

प्रदेश में संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने समय-समय पर न केवल मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई बल्कि हर दूसरे-तीसरे दिन समीक्षा बैठकों का आयोजन कर शासन और प्रशासन तंत्र को मुस्तैद बने रहने के लिए समय रहते पुख्ता कदम उठाने के आवश्यक निर्देश दिये। वह भी ऐसे वक्त पर जबकि उनकी पत्नी श्रीमती सुनिता गहलोत और मुख्यमंत्री स्वयं कोरोना पॉजिटिव थे। उन्होंने इस संकटकाल में सभी राजनीतिक दलों, के प्रतिनिधियों नगरीय और पंचायतीराज के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, धर्म गुरुओं से भी निरंतर संवाद बनाए रखा। गांवों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान को स्थगित किया।

संकट की घड़ी में एकजुटता के साथ काम करें

प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से बिना राजनीतिक भेदभाव बरते राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के तहत पर्याप्त जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन और टीकों को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया था। संकट की इस घड़ी में राजनीतिक भेदभाव को भुलाकर एकजुटता के साथ काम करने की जरूरत है।

कार्मिकों की कमी, आवश्यक वस्तुओं, दवा और साधनों के बंदोबस्त पर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद् की बैठकों के आयोजन के साथ शासन और प्रशासन से जुड़े सभी वर्गों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस संक्रमण से बचाव के तरीकों, अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्साकर्मियों, दवा और उपचार के साधन-सुविधाओं की उपलब्धता एवं प्रबंधन के भी निर्देश दिए। कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर से लेकर एवं जिला स्तर पर चिकित्सकों के दल भेजे गए।

कालाबाजारी, जमाखोरी, अनियमितताओं के प्रति उठाये सख्त कदम

ऑक्सीजन, रेमडेसिविर एवं टोसिलीजुमेब जैसी जीवन रक्षक दवाओं की बंदोबस्तगी, ऑक्सीमीटर आदि उपकरणों की कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने के कई कदम उठाए गए। स्वास्थ्य मंत्री

डॉ. रघु शर्मा के अनुसार राजस्थान को प्रतिदिन 15 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है। अप्रेल में 67 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन किया गया था लेकिन प्रदेश को केवल 40 हजार इंजेक्शन ही उपलब्ध हो सके। राजस्थान को एक्टिव केसों की संख्या के अनुपात में साढ़े सत्ताईस फीसदी इंजेक्शन ही मिले हैं। इन इंजेक्शनों के दुरुपयोग और कालाबाजारी की मिल रही शिकायतों के निवारण के लिए अब इंजेक्शन पर संबंधित मरीज का नाम, आईपीडी नंबर एवं तिथि अंकित कर नर्सिंग स्टाफ को दिए जाने के प्रबंध हुए हैं। इसके कार्टन समेत खाली वायल को अस्पताल में नियुक्त नोडल ऑफिसर से वेरिफिकेशन के बाद पूर्णतः नष्ट करवाया जा रहा है ताकि इनकी चोरी या दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। इसकी कालाबाजारी के क्रम में जयपुर में एक व्यक्ति को तथा बीकानेर में चार लोगों को पकड़ा गया है।

यही नहीं इस महामारी के शिकार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं को एमआरपी से अधिक मनमानी दरों पर बेचने से जुड़े लोगों, व्यापारियों, कारोबारियों एवं चिकित्साकर्मियों को पकड़ने के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों की ओर से कार्रवाई भी हो रही है। हाल ही जयपुर में एक निजी अस्पताल में बेड मुहैया कराने की आड़ में रिश्वत लेने के आरोप में एक चिकित्साकर्मी को 8 मई को भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस के दस्ते ने पकड़ा है।

ऑक्सीजन संकट दूर करने के जतन

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के अनुसार राजस्थान में ऑक्सीजन का संकट है। तीन माह पूर्व ऑक्सीजन की खपत 6500 सिलेंडर प्रतिदिन थी, जो 27 अप्रेल तक बढ़कर 31 हजार 425 सिलेंडर प्रतिदिन हो गई। इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, जिसका 795 एमटी तक हो जाने का अनुमान है। एक दिन की मांग 615 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। केंद्र से केवल 270 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है। इनमें से 100 मीट्रिक टन भिवाड़ी, 70 जामनगर, 60 कलिंगनगर और 40 मीट्रिक टन बुरहानपुर से मिल रही है। इन जगहों से ऑक्सीजन लाने में कई दिन लग जाते हैं। बेहतर योजना बनाकर रेल और एयरफोर्स के जरिए लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उद्योगों आदि से 315 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही है। विभिन्न स्तरों पर 50 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता के प्रयास किए जा रहे हैं। करीब 47 हजार कंसंट्रेटर्स खरीद के आदेश जारी किए जा चुके हैं। कई जिलों में स्थानीय स्तर पर 1 हजार कंसंट्रेटर मिल भी गए हैं। कुछ दिनों में विभिन्न देशों से कंसंट्रेटर की आपूर्ति होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन बर्बादी रोकने के लिए निजी चिकित्सालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग भी की गई। मॉनिटरिंग से 5 दिन में 15 फीसदी तक ऑक्सीजन बचाई जा रही है।

ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगों को विशेष पैकेज

राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने उद्योगों को विशेष पैकेज की घोषणा की। इसके तहत नया निवेश करने वाले उद्यमों को विभिन्न परिलाभ एवं सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए उद्यमी को कम से कम एक करोड़ रुपये का निवेश और 30 सितंबर 2021 तक उत्पादन आरंभ करना आवश्यक होगा। पैकेज के तहत इन उद्यमियों को राजस्थान एमएसएमई एक्ट-2019 के प्रावधानों के अनुसार उद्यम स्थापना के प्रारंभिक तीन वर्षों में राज्य सरकार के संबंधित नियामक स्वीकृतियों और निरीक्षणों में छूट प्रदान की जाएगी। संबंधित विभागों से भी जरूरी स्वीकृतियां दिलवाने, बिजली तथा पानी कनेक्शन की व्यवस्थाएं शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए विशेष सहयोग दिलाया जायेगा। प्लांट मशीनरी एवं अन्य उपकरणों पर किए गए व्यय पर अधिकतम 50 लाख रुपये के 25 प्रतिशत तक की राशि पूंजीगत अनुदान के रूप में दो किश्तों में दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। अनुदान की पहली किश्त प्लांट, मशीनरी या उपकरण खरीद के लिए जारी किए गए आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर तथा दूसरी किश्त उत्पादन के प्रारंभ करने के बाद निवेश के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उपलब्ध कराई जाएगी। उद्योग विभाग को इस पैकेज का कार्यान्वयन करने के निर्देश दिए गए हैं।

59 निकाय क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट

प्रदेश के नगरीय विकास तथा स्वायत्त शासन विभाग की ओर से राज्य में 59 निकाय क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की महत्त्वपूर्ण योजना तैयार की गई है। इस पर करीब 125 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का अनुमान है। यह संयंत्र दो माह में स्थापित हो जाएंगे। इनसे ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार आएगा।

कृषि भूमि पर ऑक्सीजन प्लांट

राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए लीज राशि में सौ फीसदी छूट देकर नि:शुल्क भू-उपयोग रूपांतरण करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है।

रूस, चीन और दुबई से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर

ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के राज्य सरकार के प्रयासों ने रंग तब दिखाया जब रूस से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप पहुंची है। 1250 कंसंट्रेटर और शीघ्र पहुंचेंगे। शेष रूस से आनी वाली फ्लाइट्स से शीघ्र मंगाये जाएंगे। मई के अंत में 28 हजार से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल जाने के बाद आवश्यकतानुसार इन्हें जिलों को भेजा जायेगा। चीन से पांच हजार कंसंट्रेटर और दुबई से एक हजार कंसंट्रेटर शीघ्र मिलने की उम्मीद है।

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

उसे टोको

जिसने मास्क नहीं पहना है

वो ही फैलाएगा कोरोना सबको

कोरोना की दूसरी लहर बहुत घातक है, तेजी से फैल रही है। इस बार गांवों तक पहुंच गई है। युवा, बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं भी संक्रमित हो रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें, घर में ही रहें। दूसरों को भी यही सलाह दें तभी संक्रमण की चेन टूटेगी। जो लापरवाह हैं उन्हें टोकें - उन्हें रोकें।

- चिंताजनक तथ्य -
- कोरोना जानलेवा भी है • तेजी से फैल रहा है
- इस बार मृत्युदर अधिक है
- 3-4 दिनों में फेफड़े काम करना बंद कर सकते हैं
- इस बार गांवों तक भी पहुंच गया है

अपील

सरकार, प्रशासन, पुलिस सफल तभी होंगे, जब आप सभी नागरिक जिम्मेदारी से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन की गाइडलाइंस की स्वयं पालना करेंगे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राजस्थान संवाद

चिकित्सालयों में ऑक्सीजन संयंत्र

वर्तमान में प्रदेश के 429 चिकित्सा संस्थानों में कोविड संक्रमितों का उपचार हो रहा है। 25 जगहों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित हो चुके। वर्तमान में 1749 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। सभी उपजिला एवं जिला अस्पतालों में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइपलाइन स्थापित की जा चुकी हैं। 43 स्थानों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 25 स्थापित हो चुके हैं और शेष 18 प्रक्रियाधीन हैं।

जांचों का दायरा बढ़ाया और दर घटाई

कोरोना वायरस की निजी प्रयोगशालाओं में जांच कराने की दर घटाकर 350 रुपये की गई है। जो पूरे देश में सबसे कम दरें हैं। सरकारी प्रयोगशालाओं में नि:शुल्क जांच की व्यवस्था के साथ राज्य में प्रतिदिन साठ से सत्तर हजार जांच हो रही हैं, इसका दायरा एक लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकारी खर्च पर मृतकों का ससम्मान अंतिम संस्कार, अस्थि-विसर्जन के लिए रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा

मरीजों के लिए एंबुलेंस और मृत व्यक्तियों के शवों को ले जाने के वाहनों की दरें निश्चित करने के साथ, मृतकों का ससम्मान दाह संस्कार के लिए सरकार की ओर से 34.56 करोड़ की धनराशि मुहैया कराने का निर्णय लिया गया। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन को जाने के लिए रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है।

मजदूर वर्ग के रोजगार के प्रति संवेदनशील फैसले

यही नहीं मजदूरों के कामकाज, उनकी दिहाड़ी के बंदोबस्त, छोटे कारोबारियों की रोजी-रोटी जारी रहे, जैसे कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस क्रम में उद्योगपतियों एवं फैक्ट्री मालिकों से श्रमिकों के साथ मानवीय व्यवहार रखने का सरकार की ओर से आग्रह किया गया।

आइसोलेशन सेंटर बढ़ाए

संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश में व्यापक स्तर पर क्वारेंटाइन या आइसोलनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। अब तक 1 लाख 14 हजार 288 क्वारेंटाइन बेड एवं 42 हजार 886 आइसोलेशन बेड चिह्नित किए जा चुके हैं। 24 अप्रैल तक प्रदेश में 81 लाख 11 हजार 760 व्यक्तियों की जांचें हो चुकी थीं। जांचों के लिए राजकीय संस्थानों पर 134 आरटी-पीसीआर मशीन तथा 69 आरएनए एक्सट्रेक्टर मशीनें उपलब्ध हैं।

कोविड जांच दर अब मात्र 350 रुपये

राजकीय प्रयोगशालाओं में कोविड जांच नि:शुल्क और निजी प्रयोगशालाओं में इस जांच के लिए अधिकतम 350 रुपए लिए जा रहे हैं। जांच कार्यों में विलंब होने पर संबंधित कमर्चारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला भी लिया गया। रेण्डम सैंपलिंग जैसे घरेलू नौकर, किराने की दुकान, हेयर ड्रेसर, ब्यूटी पॉर्लर, धोबी आदि के सैंपल लिए गए। कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के लिए गांवों में 272 मेडिकल वैन भी संचालित हो रही हैं।

ई-चिकित्सकीय परामर्श, बेड के लिए ऑनलाइन पोर्टल लाइव

प्रदेश में ई-संजीवनी द्वारा भी दूरदराज के व्यक्ति को मोबाइल के माध्यम से चिकित्सकों से चिकित्सकीय उपचार और परामर्श लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मेडिकल कॉलेज या जिला स्तर पर रैपिड रेस्पांस टीमों का गठन किया गया। अस्पतालों में बेड संख्या के संबंध में जानकारी के लिए लाइव ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई।

हेल्प लाइन एवं उचित दर पर मास्क

कोरोना से जुड़ी जानकारी एवं शिकायत के लिए राज्यस्तरीय हेल्पलाइन की स्थापना की गई जिसका फोन नम्बर 181 है। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ ने एन-95 मास्क मात्र बीस रुपये में तथा

तीन लेयर मास्क मात्र तीन रुपये की दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

कंट्रोल रूम और जिला स्तर पर कमेटियां और नोडल अधिकारी

जिला व प्रदेश स्तर पर राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। चिकित्सा सुविधाओं के समुचित प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया। जो अस्पतालों में बेड संख्या सुनिश्चित करने, निजी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं के वितरण में भूमिका अदा कर रहा है। बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। मरीजों का घर-घर सर्वे और कोविड से बचाव के संदेश दिये जा रहे हैं।

शादी समारोह अब 31 मई के बाद

कोरोना का गांवों और युवाओं में संक्रमण का खतरा बढ़ा है। उपचार के लिए शहर आते-आते रोगियों की स्थिति गंभीर हो रही है। ऐसे में बैठक में आम राय यह थी कि संक्रमण की इस चिंताजनक स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए कुछ समय तक विवाह आयोजनों को स्थगित कर दिया जाए। बहुत आवश्यकता हुई तो कुल ग्यारह व्यक्तियों के साथ घर पर या कोर्ट मैरिज ही की जाए।

आयुष 64 फॉर्मूला

मंत्रिपरिषद् ने राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम-1966 में संशोधन के प्रस्तावों का अनुमोदन किया। इससे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा राज्य में चलाए जा रहे आयुष प्रोजेक्टों एवं एनएचएम आदि में संविदा पर कार्यरत नर्स एवं कंपाउंडर कार्मिकों को बोनस अंक दिए जाकर सीधी भर्ती में वरीयता दी जा सकेगी। आयुर्वेद नर्स एवं कंपाउंडर जूनियर ग्रेड की सीधी भर्ती में निर्धारित योग्यता रखने वाले विभागीय कार्मिकों को उच्च पद का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से 5 फीसदी के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर 10 फीसदी के प्रावधान को मंजूरी दी है। इससे विभाग में कार्यरत परिचारकों को लाभ मिलेगा और अनुभवी कार्मिकों की सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही आयुष नर्स एवं कंपाउंडर जूनियर ग्रेड की सीधी भर्ती के लिए डॉ. राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा दी जाने वाली बीएससी डिग्री को भी निर्धारित योग्यता में शामिल करने की मंजूरी दी है।

सीएचसी-पीएचसी स्तर पर कोविड उपचार के लिए मास्टर प्लानिंग

कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों एवं युवाओं में भी काफी तेजी से फैल रहा है। मृत्यु की दर भी पहली लहर के मुकाबले बहुत अधिक है। विशेषज्ञ तीसरी लहर की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। इसे देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सीएचसी एवं पीएचसी स्तर तक बेड, ऑक्सीजन एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता के लिए मास्टर प्लानिंग

- **संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जन-अनुशासन पखवाड़ा**
- **सख्त लॉकडाउन**
- **राज्य को फिर से कोरोना-प्रबंधन का रोल मॉडल बनाने की पहल**

कर रहें है। इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही उपचार मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 7 मई की रात को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड संक्रमण, लॉकडाउन तथा संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस गति से संक्रमण फैल रहा है, उसमें बेहद जरूरी है कि सभी लोग स्व-अनुशासन में रहकर राज्य सरकार के जीवनरक्षा के संकल्प में सहयोग दें। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपनी और अपनों की जीवनरक्षा के लिए लागू लॉकडाउन की गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करें। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि निजी अस्पताल कोविड रोगियों से उपचार के लिए तय की गई दरों से अधिक नहीं वसूलें। अस्पतालों में लगाए गए नोडल अधिकारी इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करें कि रोगियों को निर्धारित दरों पर समुचित उपचार मिले। साथ ही वे रेमडेसिविर एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता तथा जांच दरों आदि के संबंध में आने वाली शिकायतों का भी त्वरित समाधान करने का प्रयास करें। श्री गहलोत ने कहा कि युवाओं को संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान को और गति दी जाए। केन्द्र सरकार से समन्वय कर वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समारोह से अधिक जरूरी लोगों का जीवन बचाना है। ऐसे में उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि विवाह आदि समारोह को अभी स्थगित कर दें, क्योंकि संक्रमण के बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण ऐसे कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ एकत्रित होना भी रहा है। शहरों के साथ-साथ गांवों में भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए जागरूकता अभियान को और मजबूत किया जाए। माइक, लाउडस्पीकर आदि के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक किया जाए।

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार कोविड के प्रबंधन में संसाधनों को लेकर किसी तरह की कमी नहीं रख रही है। ऑक्सीजन का आवश्यकता के अनुरूप आवंटन नहीं होने, दूरस्थ स्थानों से उठाव में लगने वाले समय के साथ ही टैंकरों की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार दिन-रात ऑक्सीजन के माकूल प्रबंधन के लिए जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए तमाम उपलब्ध विकल्पों पर काम हो रहा है। विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए विभिन्न स्तरों पर तेजी से प्रयास चल रहे हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि तीसरी और चौथी लहर की आशंका को देखते हुए हमें एक व्यापक रणनीति पर

काम करने की जरूरत है। इसके लिए अल्पकालीन और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करना उचित होगा। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल सीएचसी स्तर पर ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित करने से इस महामारी से लड़ाई में बड़ी मदद मिलेगी।

चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगातार काम कर सकें, इसके लिए कोविड केयर सेंटरों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन के प्लांट विकसित किए जाने पर जोर दिया।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने बताया कि जिला कलक्टरों ने भामाशाहों आदि के माध्यम से करीब 1000 कंसंट्रेटर प्राप्त किए हैं। उन्होंने प्रदेश में ऑक्सीजन एवं वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुबोध अग्रवाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री अखिल अरोरा तथा राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रूस से पहली खेप दिल्ली पहुंच गई है। प्रवासी राजस्थानियों, भामाशाहों, विभिन्न संगठनों आदि का भी हमें इस कार्य में सहयोग मिल रहा है।

जीवनरक्षा को सर्वोपरि रख संसाधनों का हो न्यायसंगत आवंटन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद राज्यों से संसाधनों की कमी की शिकायतें आ रही हैं। संकट की इस घड़ी में राजनीति से परे होकर पूरा मुल्क एकजुटता की मिसाल पेश करे। कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार जीवन रक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ऑक्सीजन, दवाओं एवं अन्य संसाधनों की योजनाबद्ध एवं न्यायसंगत आपूर्ति सुनिश्चित करे।

श्री गहलोत ने 23 अप्रेल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक में कहा कि कोविड की वर्तमान परिस्थितियों में कई हृदयविदारक दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आमजन का आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे प्रयास किए जाएं कि ऑक्सीजन व दवाओं की कमी से किसी व्यक्ति की जान न जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को एक्टिव केसेज के आधार पर ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर दवा का आवंटन किया जाना चाहिए। राजस्थान को 21 अप्रेल को तात्कालिक आवंटन में मात्र 26 हजार 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किए गए। इसी प्रकार ऑक्सीजन के आवंटन में भी एक्टिव केसेज के अनुपात का ध्यान नहीं रखा गया। भविष्य में इनकी आपूर्ति तर्कसंगत हो ताकि किसी भी राज्य को कोविड रोगियों के उपचार को लेकर परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

श्री गहलोत ने कहा कि कोविड रोगियों के उपचार के दौरान की जाने वाली सहायक जांचें यथा आईएल-6, डी-डाइमर, फेरिटिन टेस्ट आदि की किट की भी धीरे-धीरे कमी होने लगी है। केंद्र सरकार इन किट्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में भी योजना बनाए, ताकि समय रहते राज्यों को इनकी सुचारू आपूर्ति हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में कोरोना की वैक्सीन तैयार कर मिसाल पेश की है। हमें उन पर गर्व है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का भी केंद्र सरकार निःशुल्क टीकाकरण करवाए। केंद्र सरकार को 60 वर्ष, 45 वर्ष एवं अब 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए एक ही

नीति अपनानी चाहिये। राज्यों में सभी आयु वर्ग के लोगों को एक ही मेडिकल स्टाफ वैक्सीन लगाएगा। यह उचित नहीं होगा कि युवाओं से पैसे लिए जाएं और बाकी को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाए।

श्री गहलोत ने कहा कि भारत सरकार ने मुफ्त वैक्सीन के लिए बजट में 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है, इसे देखते हुए राज्यों ने बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है। अब अगर राज्यों को वैक्सीन का वित्तीय भार वहन करना पड़ता है तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा तथा विकास कार्यों के लिए निर्धारित बजट में कटौती करनी पडेग़ी। एक ही देश में वैक्सीन की अलग-अलग दरें भी उचित नहीं हैं। केंद्र सरकार को इस पर विचार कर निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराते हुए बताया कि लॉकडाउन को आखिरी हथियार मानते हुए प्रदेश में नवाचार के रूप में जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया गया है। इसके तहत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करने तथा लोगों को कोविड प्रोटोकॉल एवं लॉकडाउन जैसे व्यवहार की पालना के लिए निरंतर प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की छीजत रोकने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इससे करीब 10 प्रतिशत छीजत कम करने में मदद मिली है। अस्पतालों पर दबाव कम करने के लिए कोविड रोगियों को होम केयर तथा डे-केयर सुविधा दी जा रही है। प्रदेश भर में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। दवाओं के प्रोटोकॉल तथा उचित उपयोग के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है। वीसी के माध्यम से डॉक्टर्स को दवाओं के उपयोग के संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है। सेवानिवृत्त कार्मिकों की अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर सेवाएं ली जा रही हैं।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजनेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से आहवान किया है कि वे अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में एकजुट हों। उन्होंने कहा कि मानव सेवा सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का धर्म है और आज इसे निभाने का समय है। समाज के सभी वर्ग इस संकटकाल में यथासंभव मदद कर रहे हैं। राजनेताओं का भी यह दायित्व है कि महामारी के दौर में एक-दूसरे का संबल बनें और इस जंग को जीतने के लिए लोगों को प्रेरित करें।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के विषय पर सर्वदलीय संवाद किया। प्रदेश और देश में कोरोना की दूसरी लहर अधिक घातक रूप लेकर आई है और इसका प्रसार सरकारों की तैयारियों से कई गुना तेज गति से बढ़ रहा है। इस संक्रमण को रोकना ही

सर्वाधिक जरूरी काम है, जिसमें राजनीतिक कार्यकताओं और नेताओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। आम लोगों को रोग की गंभीरता के प्रति जागरूक करने, इससे बचाव करने तथा पीड़ित होने की स्थिति में उपचार उपलब्ध कराने में सहयोग करने के लिए राजनीतिक दलों को सकारात्मक प्रयास करने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना संकट से जूझने सहित जनहित में राजनेताओं तथा आमजन द्वारा की गई शिकायत और सुझावों को राज्य सरकार गंभीरता से लेती है। शिकायतों को आलोचना के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सरकार के प्रयासों में रही कमी पर ध्यान आकर्षित करने से किसी बीमार को आवश्यक सुविधा मिल सकेगी तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ ही होगा। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स, सरकार और अधिकारियों द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करने पर राजनेताओं का आभार भी व्यक्त किया।

श्री गहलोत ने प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति का कोटा बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से की जा रही मांग पर सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सहित सभी पार्टियों के नेता केन्द्र सरकार से अपील करें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या के दृष्टिगत मेडिकल ऑक्सीजन, अन्य संसाधनों तथा उपकरणों की समुचित आपूर्ति की जाए। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां प्रदेश में सम्पूर्ण टीकाकरण के लिए वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने की मांग को भी पुरजोर ढंग से केन्द्र के समक्ष रखें।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने महामारी से मुकाबले के लिए 'क्यूरेटिव अप्रोच' के साथ-साथ 'प्रीवेन्टिव अप्रोच' पर काम करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी महामारी से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर काम राज्य सरकार को करना होता है, लेकिन संसाधनों के समुचित प्रबंधन और संतुलित वितरण में केन्द्र सरकार की भूमिका अहम् है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग मजबूती से लड़ी जा रही है। राज्य सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया है, लेकिन कोरोना महामारी भयावह रूप से सामने आई है और संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है। ऐसे में, आपसी वैचारिक मतभेदों को भुलाकर जीवन की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा तथा प्रदेश हित में केन्द्र सरकार सहित हरसंभव स्रोतों से संसाधनों को जुटाने में मदद करनी होगी।

बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में कहा कि संकट की इस घड़ी में वे राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। अपने-अपने संगठनों के माध्यम से वे महामारी से बचाव के उपायों, उपचार की सुविधाओं के बारे में जागरूकता के प्रसार तथा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हरसंभव सहयोग देंगे। उन्होंने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को अधिक गति देने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने आदि के लिए अधिक सतर्कता बरतने सहित कोविड अनुशासन के बारे में अन्य महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चन्द कटारिया ने कहा कि सभी राजनीतिक दल राज्य सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग की अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को दवाओं की आपूर्ति तथा मरीजों को प्रारंभिक राहत देने के लिए सीएचसी और पीएचएसी स्तर तक व्यवस्था मजबूत करने जैसे सुझाव दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक श्री सतीश पूनिया, शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेन्द्र राठौड़, नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल, चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, विधायक श्री रामप्रसाद, विधायक श्री बलवान पूनिया, विधायक श्री पुखराज गर्ग, निर्दलीय विधायक श्री राजकुमार गौड़ एवं श्री संयम लोढा, पूर्व विधायक श्री अमराराम,

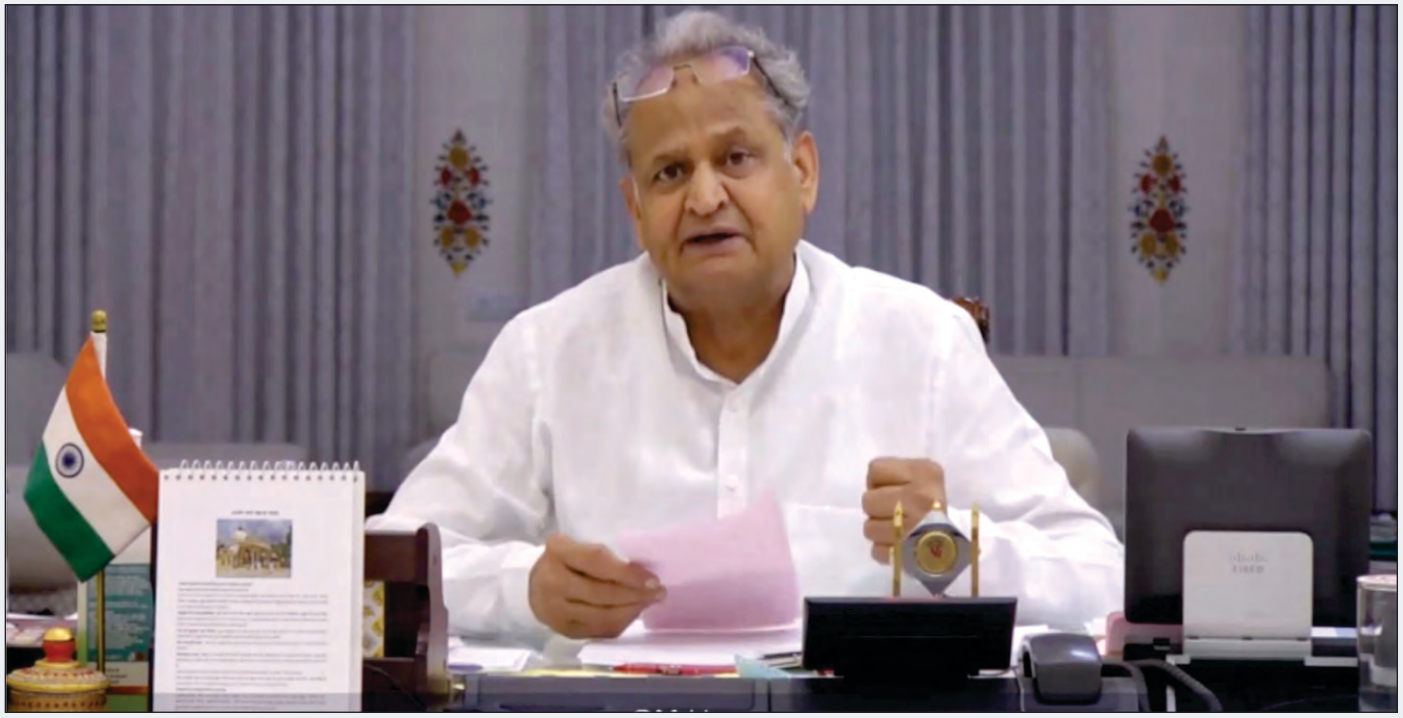

श्री रामपाल जाट, श्री नरेन्द्र आचार्य, श्री डीके छंगाणी एवं श्रीमती सुमित्रा चौपड़ा आदि ने भी अपने सुझाव एवं विचार साझा किए।

शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन ने प्रदेश में कोविड प्रबंधन पर प्रस्तुतीकरण दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, चिकित्सा विशेषज्ञों डॉ. राजाबाबू पंवार एवं डॉ. वीरेन्द्र सिंह ने राजनीतिक प्रतिनिधियों को कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, इसकी गंभीरता और प्रसार को रोकने के उपायों पर जानकारी दी।

पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विधायकों तथा पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया है कि प्रदेश भर में लागू लॉकडाउन के प्रतिबंधों की कड़ाई से पालना करने के लिए आमजन को प्रेरित करें तथा कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने में राज्य सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पक्ष-विपक्ष और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर ही यह जंग बेहतर तरीके से लड़ी जा सकती है। श्री गहलोत ने अपील की कि सभी लोग यह संकल्प लें कि वे लॉकडाउन को सफल बनाएंगे।

श्री गहलोत ने 10 मई को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के विषय पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों, विधायकगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, जिला प्रमुख से लेकर वार्ड पंच स्तर तक के पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार संक्रमितों के इलाज का बेहतर प्रबंधन कर सकती है, उन्हें अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा सकती है। लेकिन अगर संक्रमण बढ़ता रहा तो ये सुविधाएं भी कम पड़ सकती हैं। ऐसे में, नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संक्रमण से बचाव के लिए आत्मसंयम बरतें और दो गज दूरी रखने, मास्क पहनने तथा बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने के कोविड हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में घातक वायरस शहरों के साथ-साथ गांव-ढाणी तक फैल रहा है। बड़ी संख्या में युवाओं, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं तक को चपेट में ले रहा है तथा इससे होने वाली मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश और प्रदेश में बेहद चिंताजनक एवं व्यथित करने वाले हालात हैं, जिन्हें पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कोविड अनुशासन की पालना करके ही सुधारा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कोविड सहित विभिन्न गंभीर बीमारियों के इलाज को कवर किया गया है, इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस योजना की जानकारी अधिकाधिक लोगों को दें और सभी परिवारों का ई-मित्र आदि के माध्यम से समय पर निःशुल्क पंजीयन करवाएं।

श्री गहलोत ने कहा कि वायरस से संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी हथियार के तौर पर प्रदेश में लॉकडाउन के तहत आवागमन पर प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इन नियमों की पालना करवाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बीमार लोगों की जांच करवाने, संदिग्ध व्यक्तियों को होम आइसोलेशन अथवा संस्थागत क्वारेंटाइन केन्द्रों में रखने और संक्रमितों को उपचार की सुविधा तथा जरूरतमंदों को भोजन आदि उपलब्ध करवाने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की

भूमिका अहम् है। उन्होंने अपील की कि प्रदेशवासियों को संकट के दौर से बाहर निकालने में सभी लोग एक-दूसरे की मदद करें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि वैक्सीनेशन को गति देकर इस महामारी से बचा जा सकता है। हमारा पूरा प्रयास है कि राज्य में वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि यह समय खामियां या कमियां गिनाने का नहीं, कोरोना के खिलाफ राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठते हुए एकजुटता से लड़ाई लड़ने का है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस विषम परिस्थिति में राज्य सरकार को प्रतिपक्ष की ओर से सकारात्मक सहयोग मिलेगा। उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ तथा विधायक श्री सतीश पूनिया ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड अनुशासन की पालना में पंचायत जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पहली लहर से भी अधिक बढ़ गई है।

नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल, राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी, शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, विधानसभा में मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी, विधायक श्री बलवान पूनिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमें लड़ाई सामाजिक रूप से भी लड़नी होगी। इसके लिए गांव-ढाणी तक जागरूकता को हथियार बनाना होगा।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कोरोना की दूसरी भयावह लहर की तीव्रता तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे संक्रमण के बारे में जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक श्री एमएल लाठर तथा प्रमुख सचिव गृह श्री अभय कुमार ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शासन सचिव पंचायतीराज श्रीमती मंजू राजपाल ने कोविड प्रबंधन तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीयन में वार्ड स्तर से लेकर जिला प्रमुख तक सभी पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में बताया।

शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन ने कोविड प्रबंधन के बारे में बताया कि प्रदेश में एक्टिव रोगियों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। संक्रमण की यही रफ्तार रही तो 26 दिन में यह संख्या दोगुनी हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से कोरोना संक्रमितों की पहचान करने और दवा किट वितरण का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। अभी तक 7 लाख से अधिक लोगों की खांसी, बुखार, जुकाम से पीड़ित के रूप में पहचान की गई है और उन्हें दवाओं का वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट और मोबाइल वैन के माध्यम से भी कोविड के साथ-साथ नॉन कोविड बीमारियों के इलाज की व्यवस्था की गई है।

कॉन्फ्रेंस के दौरान चिकित्सा विशेषज्ञों में डॉ. राजाबाबू पंवार एवं डॉ. सुधीर भंडारी ने जनप्रतिनिधियों को कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, इसकी गंभीरता और तेजी से हो रहे प्रसार को रोकने के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी।

कोविड की चुनौती में आयुष चिकित्सा पद्धतियों की विशेष भूमिका

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना का संक्रमण शहरों के साथ-साथ गांवों में और युवाओं में भी तेजी से फैल रहा है। साथ ही मौतों की संख्या भी बढ़ी है। प्रदेश के अस्पतालों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ पर अत्यधिक दबाव है। संकट की इस घड़ी में रोगियों के बेहतर उपचार और इस चुनौती से लड़ने के लिए जरूरी है कि आयुष पद्धतियों और इनसे जुड़े तमाम संसाधनों का भी समुचित उपयोग सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि पहली लहर में आयुष पद्धति के माध्यम से कोरोना की जंग लड़ने में बड़ी मदद मिली थी। दूसरी लहर में भी इन पद्धतियों के सहयोग से हमें गांव-ढाणी तक लोगों की जीवन रक्षा में आसानी होगी।

मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुष की भारतीय चिकित्सा पद्धतियां इतनी कारगर हैं कि उनमें बिना दुष्प्रभावों के गंभीर एवं जटिल रोगों का जड़ से निदान करने की क्षमता मौजूद है। आवश्यकता इस बात है कि इन पद्धतियों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। राज्य सरकार इस दिशा में तमाम प्रयास कर रही है। बजट में कई घोषणाएं की गई हैं, जिनसे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री गहलोत ने कहा कि हमारे बीच में से ही ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, जिनमें लोग आयुष पद्धतियों को अपनाकर कोरोना सहित अन्य गंभीर बीमारियों से सफलतापूर्वक लड़ पाए। यह पद्धतियां हमारे जीवन शैली, योग, आहारचर्या एवं ऋतुचर्या आदि से जुड़ी हुई हैं, अगर पूरे संयम और अनुशासन के साथ इनका पालन करें तो हम निरोगी बने रह सकते हैं। कोविड की इस आपदा में इन पद्धतियों की भूमिका और महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष विभाग ने कोरोना की पहली लहर में आयुर्वेदिक काढ़े, यूनानी काढ़े, आयुष-क्वाथ, आर्सेनिक एल्बम जैसी दवाओं से लोगों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया, उससे हमें काफी मदद मिली थी। दूसरी लहर में भी लोगों को जागरूक करने, कोरोना से बचाव तथा गांव-गांव तक फैली अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से विभाग संकट की इस घड़ी में निरन्तर अपनी भूमिका निभाए।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने में आयुष चिकित्सा पद्धतियों की विशेष भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य में आयुष

चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट में 1 हजार आयुर्वेद औषधालयों को वैलनेस सेन्टर के रूप में विकसित करने, राज्य आयुष अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। साथ ही, राज्य की नई आयुष नीति का भी अनुमोदन किया गया है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में हमेशा ही आयुर्वेद एवं अन्य आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौर में इन पद्धतियों की भूमिका और बढ़ गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि वन विभाग के माध्यम से औषधीय पौधों की नर्सरियां स्थापित की जा सकती हैं।

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग के सचिव श्री सुरेश गुप्ता ने आयुष विभाग की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति डॉ. अभिमन्यु कुमार ने बताया कि कोरोना के समय में विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को लगातार अध्ययन से जोड़े रखने के लिए ई-लर्निंग के माध्यम से स्टडी मैटेरियल तैयार किया है।

वैक्सीन खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 12 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए वैक्सीन, दवाओं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की त्वरित खरीद के लिए महत्त्वपूर्ण निर्णय किए गए।

मंत्रिपरिषद् ने प्रदेश में वैक्सीनेशन को गति देने तथा वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। इससे विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन की 1 करोड़ डोज खरीदी जा सकेंगी। यह खरीद जल्द से जल्द हो, इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन को नोडल एजेंसी बनाकर शीघ्र ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जारी किया जाएगा।

जीवन रक्षा के लिए वैक्सीनेशन को गति देना जरूरी

मंत्रिपरिषद ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कोरोना संक्रमण का तेजी से प्रसार हो रहा है। देशभर में बड़ी संख्या में मौतें भी हो रही हैं। लेकिन वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होने से टीकाकरण की गति काफी धीमी हो गई है। वैक्सीन की कमी के कारण प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन कुछ ही स्थानों पर शुरू हो पाया है, जबकि दूसरी घातक लहर युवाओं को अधिक संक्रमित कर रही है। ऐसे में जीवन रक्षा के लिए वैक्सीनेशन को गति देना बेहद जरूरी है। मंत्रिपरिषद ने इसके लिए विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर पर सहमति व्यक्त की।

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

कोरोना से बचना है तो हमें जागना होगा

"कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है।

- इस बार 80 प्रतिशत को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, पिछली बार 20 प्रतिशत हो ही जरूरत पड़ी थी।
- आज लगभग 150 मौतें प्रतिदिन हो रही हैं, पिछली बार यह संख्या पूरे वर्ष 0 से 20 तक ही थी।
- इस बार बच्चे, युवा एवं गर्भवती महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, पिछली बार यह संख्या नगण्य थी।

हालात हृदय विदारक हैं। एक विकराल रूप ले रहा है-कोरोना। जीवन रक्षक दवाइयां और ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है और दूसरी तरफ सप्लाई कम है, जिसका प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। हम उनसे बराबर मांग कर रहे हैं कि आपूर्ति बढ़ाएं। संक्रमितों का नम्बर दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है।

सरकारी इलाज एवं अन्य व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं आने देंगे, चाहे कितना ही बजट खर्च करना पड़े। लेकिन कोरोना से बचना है तो आप सब को यह समझना बेहद जरूरी है कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस (मास्क सहित कोविड प्रोटोकॉल) की पालना पूर्ण रूप से करनी अति आवश्यक है।

समय की मांग है कि आप सभी अपने पर, 'स्वयं लॉकडाउन' समझकर ही व्यवहार करें। इस स्तर का जन सहयोग रहेगा तभी हम मिलकर कोरोना को हरा पाएंगे। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, इसलिए हमें जागना ही होगा।"

'निज पर शासन, फिर अनुशासन'

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री

राजस्थान संवाद

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

निरोगी राजस्थान समृद्ध राजस्थान
पहला सुख निरोगी काया

संयम रखें

अनावश्यक भीड़ से बचें
अपनी बारी का इंतजार करें

प्रदेशवासियों को नि:शुल्क वैक्सीन सुलभता से उपलब्ध हो इसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

'' मैं 18- 44 आयु वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि केवल अपॉइंटमेंट बुक होने पर ही टीकाकरण केंद्र पर जाएं, भीड़ से ही संक्रमण बढ़ता है। वायरस की चेन टूटे यह ज़िम्मेदारी हम सभी की है।''

आप इन निम्न स्टेप्स को फॉलो कर कोविन पोर्टल पर रजिस्टर करें:

1. लॉगिन करें selfregistration.cowin.gov.in
2. अपना मोबाइल नंबर डालें, प्राप्त ओटीपी डाल कर लॉगिन करें।
3. 'रजिस्टर मेम्बर' बटन पर क्लिक कर अपनी व्यक्तिगत जानकारी डालें।
4. समय और तारीख चुनकर अपना टीकाकरण अपॉइंटमेंट बुक करें।

45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया यथावत है।

टोल फ्री : 104/108

पहनिए मास्क | धोइए हाथ | रखिए दो गज दूरी

कोरोना वॉर रूम: 181

राजस्थान संवाद

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
राजस्थान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. सेवाएं राजस्थान

बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि केंद्र सरकार द्वारा युवा वर्ग के लिए निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण राज्य सरकार ने स्वयं के संसाधनों से करीब 3 हजार करोड़ रुपए व्यय कर निःशुल्क टीकाकरण का निर्णय किया है। ऐसे में तमाम प्रयास कर प्रदेश की इस युवा आबादी का टीकाकरण जल्द से जल्द कराया जाना बेहतर होगा।

आपातकालीन उपयोग के लिए दवाओं की जल्द हो सकेगी खरीद

मंत्रिपरिषद ने संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए विभिन्न जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मेडिकल उपकरण आदि की खरीद तथा ऑक्सीजन परिवहन के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं में शिथिलता के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया। इससे इन आवश्यक दवाओं तथा उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में आसानी होगी और रोगियों को समय पर समुचित उपचार मिल सकेगा। कोविड में आपातकालीन प्रयोग के लिए मंजूर की गई औषधि 2डीजी, केसीरीविमेब एवं इम्डीविमेब आदि के बाजार में उपलब्ध होने पर निर्माता कंपनी से सीधे ही उपापन करने तथा भविष्य में कोरोना की अन्य दवाओं को भी सीधे क्रय किए जाने के प्रस्ताव का भी बैठक में अनुमोदन किया गया।

प्रभारी मंत्री जिलों में कोविड स्थिति की करेंगे नियमित समीक्षा

बैठक में निर्णय लिया गया कि जिलों में संक्रमण की स्थिति की गहन समीक्षा और उसके अनुरूप पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लोगों को राहत देने के लिए प्रभारी मंत्री जिलों का नियमित दौरा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस, दूरभाष आदि के माध्यम से भी जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में रहेंगे। जरूरतमंदों की मदद, कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने तथा उपचार के लिए भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के सहयोग से संसाधन जुटाने के लिए भी समन्वय करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल एवं लॉकडाउन की प्रभावी पालना के लिए ग्राम स्तरीय समितियों को सक्रिय करने, पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ ही आगामी आवश्यकताओं के लिए फीडबैक भी प्राप्त करेंगे।

62 निकायों में 105 ऑक्सीजन प्लांट के लिए कार्यादेश जारी

मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा हुई कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है। इसके लिए वित्तीय संसाधनों की भी कोई कमी नहीं रखी जा रही है, लेकिन कोरोना का संक्रमण जिस गति से फैल रहा है, उसके अनुरूप ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस बात के प्रयास किए जाएं जिससे राज्य कोरोना से लड़ने के लिए ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं, मेडिकल उपकरण सहित अन्य संसाधनों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ सके। विशेषज्ञों के मुताबिक यह महामारी कब खत्म होगी कोई नहीं कह सकता। नगरीय विकास विभाग की ओर से 62 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 105 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए है।

चिकित्सा विभाग की ओर से प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। उसे देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक में एक सामुदायिक केंद्र को कोविड कंसल्टेशन एवं कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें रोगियों के लिए ओपीडी, आईपीडी के साथ डे-केयर की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। साथ ही, प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 5 लाख से अधिक व्यक्तियों का अब तक टीकाकरण किया जा चुका है।

प्रदेश में ब्लैक फंगस की दवा खरीद के आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि कोविड के बाद मधुमेह से ग्रसित लोगों को होने वाली बीमारी 'ब्लैक फंगस' के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने बीमारी के दौरान काम आने वाली दवाओं की आपूर्ति के साथ उपचार के लिए भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। संक्रमण में काम आने वाली दवाओं के संबंध में क्रय आदेश जारी कर दिए गए हैं। विशेष रूप से ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में काम आने वाली दवा 'लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी' की आपूर्ति कर संबंधित फर्म को क्रय करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

राज्य सरकार प्रदेशवासियों के स्वस्थ और सुरक्षित जीवन को लेकर बेहद चिंतित है। मंत्रिपरिषद् ने अपेक्षा की है कि सभी लोग राज्य सरकार के इन प्रयासों को सार्थक रूप देने के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कर अपनी और अपनों की जीवन रक्षा के दायित्व का जिम्मेदार नागरिक के रूप में निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने समय-समय पर मीडिया के माध्यम से ऐसी अपीलें जारी कर प्रदेशवासियों से की है।

कुल मिलाकर कोविड महामारी के इस वर्तमान और आसन्न भावी संकट से प्रदेश के हर व्यक्ति के जीवन को बेशकीमती समझकर उसे बचाने के लिए जिस तत्परता के साथ राज्य सरकार अपना उद्यम भरा जज्बा दिखा रही है, उसे देखते हुए एक शेर अनायास स्मृतियों में कौंध जाता है-

'लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती,
हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती।
जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा,
उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती'।

कल्याणकारी योजनाएं : आमजन को मिला संबल

–डॉ. सत्यनारायण सिंह
भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में लोक कल्याण और जन सेवा की भावना से उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील कार्यप्रणाली विकसित करने की दिशा में नये आयाम स्थापित किये हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों एवं नैतिक आदर्शों यथा सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, ग्राम स्वराज, सत्याग्रह के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सरकार उन्हीं मूल्यों का अनुसरण कर रही है एवं उनके मूल्यों को आत्मसात करने के लिए सतत प्रयास जारी है। राज्य सरकार द्वारा नवीन समृद्ध राजस्थान के निर्माण की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ कार्य किये जा रहे हैं।

राज्य सरकार प्रदेश के आमजन एवं गरीब को समय पर निःशुल्क और सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा आम आदमी को अनिवार्य रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ''राइट टू हेल्थ केयर'' कानून लाने की कार्यवाही की जा रही है। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसम्बर 2019 से शुभारम्भ कर 40 हजार गांवों में 80 हजार स्वास्थ्य मित्र बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवायी जा रही 607 दवाइयों में कैंसर, हृदय, श्वास एवं गुर्दा रोग आदि के उपचार हेतु नई दवाओं को शामिल करते हुये अब 709 दवाइयां उपलब्ध करवायी जा रही हैं। निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत जांचों की संख्या 70 से बढ़ाकर 90 की गयी है।

बी.पी.एल. एवं वरिष्ठ नागरिकों को एम.आर.आई. एवं सीटी स्केन की सुविधायें एस.एम.एस. अस्पताल की तर्ज पर 6 अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं आर.यू.एच.एस. मेडिकल कॉलेज (जयपुरिया अस्पताल) में भी निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं। 12 जनता क्लिनिक खोले गए हैं। राज्य में 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति भी भारत सरकार से लेने में राज्य सरकार सफल हुई है। 58 पंचायत मुख्यालयों पर आयुर्वेद चिकित्सालय- औषधालय खोले जाएंगे।

किसानों के हितार्थ 1 हजार करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष का गठन, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 जारी की गयी। फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ लगाने वाले किसानों को 10 हेक्टेयर तक जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन कराने की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है। कृषि महाविद्यालय खोले गये हैं। किसान सेवा पोर्टल शुरू किया गया है। लघु एवं सीमान्त वृद्धजन सम्मान किसान पेंशन योजना को प्रदेशभर में लागू कर 75 वर्ष से कम आयु के किसानों को 750 रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष एवं अधिक आयु के किसानों को 1 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन से लाभान्वित किया जा रहा है। 20 लाख 26 हजार कृषकों को ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी कर 7 हजार 689 करोड़ रुपये के ऋण माफ कर कृषकों को राहत दी गयी है। अब तक 30 हजार 37 किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए 47 करोड़ 80 लाख रुपये का बजट आवंटित किया जा चुका है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राज्य की राजकीय सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अति पिछड़े वर्गों के लिए 5 प्रतिशत एवं आर्थिक कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। पेंशन राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये किये गये हैं। वृद्धावस्था पेंशनधारियों की पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि की गयी है। प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना' प्रारम्भ की गयी है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों एवं नैतिक आदर्शों यथा सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, ग्राम स्वराज, सत्याग्रह के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सरकार उन्हीं मूल्यों का अनुसरण कर रही है एवं उनके मूल्यों को आत्मसात करने के लिए सतत प्रयास जारी है। राज्य सरकार द्वारा नवीन समृद्ध राजस्थान के निर्माण की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ कार्य किये जा रहे हैं।

राजस्थान सिलिकोसिस नीति-2019 लागू कर दी गयी है। आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने की मंशा के साथ 4 नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राशि का भुगतान सीधे ही विद्यार्थियों के खातों में हस्तांतरित किया जा रहा है। एक हजार करोड़ रुपये की इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 7 हजार 500 रुपये किया गया है। 746 करोड़ रुपये व्यय कर ग्रामीण आधारभूत संरचना के 14 हजार कार्य पूर्ण कराये गये हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना में 5 हजार 810 करोड़ रुपये व्यय कर 51 लाख 89 हजार परिवारों के 73 लाख 51 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रति आवास पर 1 लाख 49 हजार 280 रुपये व्यय करते हुए 3 लाख 64 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। ''महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर'' आयोजित कर 1 लाख 37 हजार 751 पट्टे जारी कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। तीन नये नगर निगम गठित किये गये हैं। हेरिटेज प्लान, चारदीवारी संरक्षण एवं ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है।

राज्य में कोई भी व्यक्ति निःसंकोच पुलिस थाने अथवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। ऐसी व्यवस्था करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान देश का दूसरा ऐसा राज्य है, जिसने मॉब लिंचिंग कानून बनाया है। राज्य में दर्ज विशेष जघन्य अपराधों (हीनियस क्राइम) पर निगरानी रखने हेतु एक सी.आई.डी. (सी.बी.) शाखा में मॉनिटरिंग इकाई स्थापित की गयी है।

विद्युत के 1 लाख 27 हजार 910 कृषि कनेक्शन एवं 6 लाख घरेलू कनेक्शन जारी किये गये। अक्टूबर, 2019 तक 7 हजार 128 करोड़ रुपये के किसानों के बिजली के बिलों में राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है। कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दरें नहीं बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये 14 हजार 51 नवीन कक्षों, 23 नवीन भवनों के निर्माण तथा 83 भवनों की वृहद् मरम्मत कार्यों हेतु लगभग 1 हजार 582 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए हैं। 60 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जा रहा है। दूध का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना में 1 फरवरी, 2019 से पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है।

1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में सरकारी क्षेत्र में 31 हजार 513 पदों पर युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गयी है तथा 28 हजार 601 पदों के परिणाम जारी हो चुके हैं जिनकी नियुक्ति शीघ्र की जा रही है। इसके अलावा 8 हजार 922 पदों हेतु परीक्षा आयोजित हो चुकी है, जिनका परिणाम आना शेष है। साथ ही 37 हजार 503 नये पदों हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है।

लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने हेतु ''राजस्थान जन-आधार योजना, 2019'' का शुभारम्भ 18 दिसम्बर, 2019 को किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर राज्य सरकार द्वारा खादी क्षेत्र में कतिन एवं बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिये खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर 50 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है।

11 नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों की चिकित्सा सहायता 4 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह की गयी। जयपुर में राज्य खेल का आयोजन किया गया, जिसमें 18 खेलों में 8 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिसम्बर, 2019 तक 2044 करोड़ 98 लाख रुपये का व्यय किया गया है। चम्बल नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2019 तक 39 करोड़ 17 लाख व्यय किये जाकर 53 किलोमीटर पाइप लाइनिंग का कार्य पूरा किया गया है।

कोई भूखा न सोये तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ता भोजन मुहैया कराने हेतु सभी नगरपालिका क्षेत्रों में इन्दिरा रसोई योजना एवं सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनरों, जनप्रतिनिधियों के लिए राजस्थान मेडिकल हेल्थ बीमा योजना प्रारम्भ की। आम जनता के लिए 5 लाख तक का इलाज मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। अब सभी नागरिकों को (18 से 45 आयु वर्ग व इसके ऊपर) मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। कोराना में मृतकों के दाह संस्कार आदि का खर्च भी राज्य सरकार वहन कर रही है।•

निकायों को सुदृढ़ कर जनहित के कार्य करना ही राज्य सरकार का ध्येय

हमारे लिए स्थानीय सरकारों की स्थिति को सुदृढ़ करना एक चुनौती था। जिसे हमने स्वीकार करते हुए नगरीय निकायों के ढ़ांचे में मूलभूत परिवर्तन किये। नगरीय निकायों के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए उन्हें स्वायत्तता प्रदान की है। जिससे सभी नगरीय निकाय फिर से जनहित के कार्यों में जुटे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के संकल्प को पूरा करते हुए समूचे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों को इन्दिरा रसोइयों से नि:शुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस हेतु विभिन्न अस्पताल/कोविड केयर सेन्टर/ आईसोलेशन सेन्टर में इन्दिरा रसोइयों के एक्सटेंशन काउन्टर खोले गए हैं। वहीं रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के तहत लॉकडाउन की अवधि में इन्दिरा रसोइयों के माध्यम से जरूरतमन्दों को नि:शुल्क भोजन वितरण कराने का बीड़ा उठाया है, इस कार्य में विभाग द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, दानदाताओं का भी सहयोग लिया जा रहा है।

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल का दृष्टिकोण

उपनिदेशक, जनसम्पर्क ब्रजेश पारीक द्वारा लिये गये साक्षात्कार के महत्त्वपूर्ण अंश

वर्तमान सरकार को स्वायत्त शासन विभाग में क्या चुनौतियां मिली और कौनसे नवाचार किये जा रहे है?

हमारे लिए स्थानीय सरकारों की स्थिति को सुदृढ़ करना एक चुनौती था। जिसे हमने स्वीकार करते हुए नगरीय निकायों के ढ़ांचे में मूलभूत परिवर्तन किये। नगरीय निकायों के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए उन्हें स्वायत्ता प्रदान की है। जिससे सभी नगरीय निकाय फिर से जनहित के कार्यों में जुट गये है।

नवाचार:- स्वायत्त शासन को सुगम बनाने के लिए निकायों के वार्डो का डिलिमिटेशन, जयपुर, जोधपुर, कोटा में दो-दो नगर निगम का गठन। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति, साईनेज लाईसेन्स, फायर एन.ओ.सी. प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाईसेन्स, नाम हस्तान्तरण, सीवर कनेक्शन, 90ए भू-रुपान्तरण जैसी आवश्यक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निस्पादन नियम 1974 के नियम 17 में संशोधन, पत्रकारगणों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित। जयपुर शहर विश्व हेरिटेज सिटी सूची में सम्मिलित, एरियल सर्वे डिजिटल गुगल सर्वे से जयपुर में सम्पत्तियों का चिह्नीकरण। नगरपालिकाओं के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता समाप्त, निकायों के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से एक लाख के कम जनसंख्या वाले शहर के लिए जोनल/सेक्टर डवलपमेंट प्लान अनिवार्य समाप्त। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्यो को सम्मिलित कर 2813 करोड़ रुपये के कार्य जयपुर, कोटा, अजमेर एवं उदयपुर में प्रगति पर है।

कोविड काल के इस कठिन दौर में स्वायत्त शासन की क्या कार्य योजना है?

कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में भीलवाड़ा जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए किये गये कार्यो ''भीलवाड़ा मॉडल'' को देश-विदेश में सराहा व अपनाया गया है। प्रदेश में 02 अक्टूबर, 2020 से कोरोना के विरूद्ध जनआन्दोलन प्रारम्भ किया गया। कोरोना की द्वितीय लहर के समय ''नो मास्क नो मूवमेंट'' अभियान को रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में सख्ती से लागू किया गया। लॉकडाउन के दौरान अब तक 77.17 लाख लीटर सोडियम हाइपोक्लोराईट का छिड़काव, 1.99 करोड़ से अधिक मास्क का वितरण, 101 लाख घरों के बाहर जागरूकता पोस्टर चस्पा किये गये है। 62 लाख पोस्टरों का वितरण, 49054 जागरूकता रैलियों का आयोजन, 81832 जागरूकता होर्डिंग्स लगाये एवं प्रतिदिन औसतन 5480 वाहनों के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

कोविड जनित/सन्देहास्पद कोविड जनित मृत्यु के प्रकरणों में पार्थिव देह को अन्तिम संस्कार स्थल तक प्रदेश के नगरीय निकायों में 155 एम्बूलेंस लगाकर परिवहन की नि:शुल्क व्यवस्था व कोविड प्रोटोकॉल के तहत अन्तिम संस्कार में होने वाले समस्त व्यय का वहन संबंधित नगरीय निकाय द्वारा 25 अप्रैल, 2021 से किया जा रहा है। अब तक इन निकायों द्वारा 2489 अन्तिम संस्कार किये जा चुके है। राज्य सरकार द्वारा इन कार्यों के लिए नगरीय निकायों को 34 करोड़ रुपये आवंटित किये जा चुके हैं।

कोविड-19 की दूसरी घातक लहर से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए प्रथम चरण में 105 ऑक्सीजन प्लांट हेतु 61.66 करोड़ रुपये का कार्यादेश जारी किया गया है। सभी ऑक्सीजन प्लान्ट आगामी दो माह में स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण करवाया जा चुका है।

स्वायत्त शासन विभाग के बतौर मुखिया राजस्थान प्रदेश के लिये आगामी 3 वर्षो में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी ?

नगरीय निकाय क्षेत्र में आमजन के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने एवं उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनेक कार्य योजनाओं पर कार्य किया जा रहा हैं जिनमें सड़क, नाली, सीवरेज, शौचालय निर्माण एवं सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था प्रमुख हैं। राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों में विगत 3 वर्षो की बजट घोषणाओं में लगभग 2700 करोड़ रुपये के विकास कार्य यथा टाउन हॉल, ड्रेनेज सिस्टम, तालाबों का पुनरुद्धार, पुरानी व नई सीवरेज लाईन, एस.टी.पी., एफ.एस.टी.पी., ओपन जिम, रिवर फ्रन्ट, शहीद स्मारक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं सैप्टिक टैंक व सीवर सफाई कार्य हेतु सुरक्षा उपकरण/मशीन तथा मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर आदि कार्यों को गुणवत्तापूर्ण इस सरकार के कार्यकाल में पूर्ण करवाये जाएंगे। इसके अतिरिक्त अमृत योजना के तहत 29 शहरों में 3224 करोड़ के सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, ग्रीन स्पेस के कार्य किये जा रहे है। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत 2813 करोड़ रू. के कार्य जयपुर, कोटा, अजमेर एवं उदयपुर में प्रगति पर है।

अग्निशमन सुविधा के सुदृढ़ीकरण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

बढ़ते औद्योगिकीकरण एवं बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के कारण आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी को रोकने के लिए अग्निशमन व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। जिसके तहत 155 अग्निशमन वाहन चालकों की भर्ती की जा चुकी है तथा 29 सहायक अग्निशमन अधिकारी व 600 फायरमैन की शीघ्र भर्ती की जायेगी।

फायर फाइटर्स की सुरक्षा के क्या विशेष बन्दोबस्त किये गये हैं ?

कोविड-19 के दौरान प्रदेश की अग्निशमन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने बेहतरीन कार्य का प्रदर्शन किया है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सोडियम हाईपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इन कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा की दृष्टि से मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, दस्ताने क्रय करने के लिए 1000 रुपये नकद भुगतान किया गया। इस दौरान 58 वर्ष व इससे अधिक आयु के अग्निशमन कर्मचारियों को फील्ड ड्यूटी में नहीं लगाया गया। कोरोना वायरस ड्यूटी के दौरान नगरीय निकायों में कार्यरत अस्थायी, संविदाकर्मी एवं स्थायी कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवारजन को 50 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी। प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण करवाया जा चुका है।

शहरों में पार्किंग स्थल बनाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है ?

नियोजित यातायात प्रबंधन तथा पार्किंग हेतु निर्धारित आवश्यक स्थानों को चिह्नित किया जाना प्रस्तावित है। जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी प्रॉजेक्ट के अंतर्गत चार स्थानों पर 126 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये है। जिनमें से चौगान स्टेडियम पर पार्किंग निर्माण का कार्य पूर्ण गया है तथा जयपुरिया अस्पताल, अनाज मण्डी चांदपोल व रामनिवास बाग (द्वितीय चरण) में पार्किंग निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। अजमेर शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत चार विभिन्न स्थलों पर कुल लागत 12.85 करोड़ रुपये के पार्किंग निर्माण कार्य प्रगतिरत है। कोटा शहर में स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत तीन स्थानों पर कुल राशि 50 करोड़ रुपये के कार्य कराये जा रहे हैं, जिसमें से एमबीएम/कोर्ट परिसर में पार्किंग निर्माण कार्य पूर्ण हो गया हैं तथा जयपुर गोल्डन एवं मल्टीपर्पज स्कूल ग्राउण्ड में कार्य प्रगति पर है।

आवासीय योजनाओं में पत्रकारों के आवास हेतु क्या प्रावधान हैं ?

राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अपनी आवासीय योजनाओं में अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए 2 प्रतिशत आवास आरक्षित किए का जाने का प्रावधान किया हुआ है। दिसम्बर, 2018 के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण की घोषित विभिन्न आवासीय योजनाओं में लॉटरी द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों को 30 भूखण्ड आवंटित किये गये हैं।

कचरा प्रबंधन व स्वच्छता को लेकर क्या कुछ नया किया जाना शेष है ?

शहरी क्षेत्रो में प्रतिदिन सड़कों व नालियों की सफाई, घरों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकले कचरे का संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, निस्तारण एवं परिवहन का कार्य किया जा रहा है। नगरीय निकायों में घर-घर कचरा संग्रहण एवं परिवहन कार्य को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु आवश्यक उपकरण एवं मशीनें क्रय करने की वार्षिक दर स्वीकृत कर दी गई है। नगर निकायों ने अपनी आवश्यकता के आधार पर उपकरणों/मशीनो का क्रय प्रारम्भ कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2020-21 में रू. 88 करोड़ के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं रू. 88 करोड़ के सीवर एवं सैप्टिक टैंक सफाई कार्य सुरक्षा उपकरणों हेतु कुल राशि रू. 176 करोड़ का आधुनिक उपकरणों/मशीनों के लिए प्रावधान किया गया है।

आमजन के लिए कोरोना के इस विकट काल में इंदिरा रसोई योजना के संबंध में क्या आगामी रणनीति रहेगी ?

''कोई भूखा ना सोए'' अवधारणा के तहत सेवाभावी स्थानीय संस्थाओं का चयन कर 213 नगरीय निकायों में 20 अगस्त, 2020 से 358 इन्दिरा रसोइयों के माध्यम से 8 रू. प्रति थाली में शुद्ध पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन दोपहर व रात्रि में सम्मानपूर्वक बैठाकर करवाया जा रहा है। योजना में प्रतिवर्ष 4.87 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जायेगा। इस पर लगभग 100 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है। योजनान्तर्गत अब तक 2.59 करोड़ व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। समूचे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों को इन्दिरा रसोइयों से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। विभिन्न अस्पतालों, कोविड केयर सेन्टर और आइसोलेशन सेन्टर में इन्दिरा रसोइयों के एक्सटेन्शन काउन्टर खोले गये है, वही रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा के तहत् इन्दिरा रसोइयों के माध्यम से जरुरतमंदों को भी निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। •

नये आयामों से संवरता कोटा

– पूनम मेहता
अतिरिक्त निदेशक, अंकेक्षण निधि

कोटा नए आयामों से संवर रहा है। किशोर सागर तालाब पर सेवन वंडर्स पार्क और महावीर नगर में घटोतकच्छ सर्किल के साथ ही कोटा में अनेक निर्माण कार्य नगर स्मार्ट सिटी योजना के तहत करवाए जा रहे हैं।

सिग्नल फ्री शहर

नवंबर, 2021 में कोटा देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां ट्रैफिक सिग्नल नहीं होंगे। स्टेशन से लेकर अनंतपुरा के 25 किमी के सफर में एक भी सिग्नल नहीं होगा। भूटान की राजधानी थिम्पू की तर्ज पर बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट पर लगभग 211.2 करोड़ खर्च होंगे। इस रोड पर 3 अंडरपास और 2 ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। अंटाघर अंडरपास पर 23.96 करोड़, एरोड्रम सर्किल अंडरपास पर 50 करोड़, सिटी मॉल ओवरब्रिज पर 46.35 करोड़ गोबरिया बावडी अंडरपास पर 20.89 करोड़ और अनंतपुरा ओवरब्रिज पर 70 करोड़ खर्च होंगे।

अनन्तपुरा तिराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण

भामाशाह मंडी में जिन्सों की अत्यधिक आवक होने से अनन्तपुरा तिराहे पर भारी यातायात होने के कारण वहां फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य व्यावसायिक केन्द्र गुमानपुरा में इंदिरागांधी तिराहे पर भी फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है।

अंडरपास का निर्माण

भारी यातायात को दृष्टिगत रखते हुए नगर विकास न्यास द्वारा अंटाघर चौराहे, एरोड्राम चौराहे और गोबरिया बावडी चौराहे पर अण्डरपास निर्मित किये जा रहे है।

चौराहों का सौंदर्यीकरण

एरोड्रम सर्किल को नए लुक में बनाया जाएगा। यहां राजस्थानी वास्तु और आधुनिक शिल्प का अनूठा समन्वय होगा। एरोड्रम सर्किल को आकर्षक बनाने के लिए टॉवर ऑफ लिबर्टी के तीन टॉवर लगाए जाएंगे। जो गुलामी पर स्वतंत्रता की जीत के प्रतीक होंगे। टॉवर ऑफ लिबर्टी को राजस्थान की विशिष्ट वास्तुकला, हाड़ौती क्षेत्र की पारम्परिक टॉवर और महरावों की तरह विकसित किया जाएगा। यहां तीन अलग-अलग टॉवर 50 मीटर, 40 मीटर और 25 मीटर ऊंचाई के बनाए जाएंगे।

जगमगाता घोड़े वाले बाबा चौराहा एरोड्रम सर्किल पर बन रहे अंडरपास के बाहर निकलते ही सामने 21 मीटर ऊंचा व्हाइट मार्बल का नक्काशीदार झरने वाला चौराहा नजर आएगा। इस चौराहे के सौंदर्यीकरण और विकास पर 13.83 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसका निर्माण दिसम्बर 2021 में पूरा होने की संभावना है।

गोबरिया बावड़ी से एरोड्रम तक बनेगा हरियाली वाला नाला

रेड लाइट फ्री रोड के सहारे निकल रहे मुख्य नाले को भी अब संवारा जाएगा। कीचड़ और मलबे से अटे-पडे इस नाले को हरियाली वाला नाला बनाया जाएगा। गोबरिया बावडी से लेकर एरोड्रम तक नाले को दो फेज में आरसीसी का पक्का नाला बनाकर पाथ-वे और प्लांटर बनाए जाएंगे ताकि नीचे से पानी बहता रहे और ऊपर हरियाली नजर आए। साथ ही पैदल चलने वालों के लिए भी स्थान मिल जाए। इस पर 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी योजना में अब नाले का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मौजूदा नाले की गहराई बढ़ाकर आरसीसी का पक्का नाला

बनाया जाएगा। दोनों तरफ सवा मीटर चौड़े प्लांटर तैयार किए जाएंगे। साथ ही पाथ-वे भी होगा। प्लांटर में हरियाली होगी ताकि सड़क देखने पर केवल हरीतिमा पट्टी की भांति ही नजर आए। नीचे से पानी बहता रहेगा।

क्रांतिकारियों की वीरगाथा सहजता अदालत चौराहा

यूआईटी 7.30 करोड़ की लागत से कोटा शहर की मुख्य सड़क और अदालत चौराहे का सौंदर्यीकरण करवा रहा है। यह चौराहा आजादी में कोटा के क्रांतिकारियों की वीरगाथा बयां करेगा। यहां पर 1857 से 1947 के बीच स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं को पत्थरों पर नक्काशी कर उकेरा जाएगा। तिरंगे को हाथ में लेकर आन्दोलनकारियों के संघर्ष को इसमें बताया जाएगा। सर्किल पर 4 तोप लगाई जाएंगी। स्टेच्यू को 10 फीट और ऊंचा उठाकर हाथियों द्वारा सलामी देते बनाया जाएगा। अदालत परिसर को भी संवारा जाएगा।

चम्बल रिवरफ्रंट

अब तक शिक्षा नगरी के नाम से देश-विदेश में नाम कमाने वाले कोटा शहर को अगले वर्ष से टूरिज्म सिटी के रूप में भी पहचाना जाने लगा है। यह संभव हो सकेगा चंबल रिवर फ्रंट से जहां चट्टानों पर कई सालों से जमा पानी, उपेक्षित चंबल की डाउन स्ट्रीम का आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर बन रहे इस प्रोजेक्ट पर 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे शहर के निचले इलाकों में बाढ़ की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वहीं दोनों किनारों पर खाने-पीने से लेकर हेरिटेज के भी दर्शन होंगे। चंबल के दोनों तरफ 22 घाट बनाए जाएंगे। वहीं रिवर फ्रंट में महाराणा प्रताप की सबसे बडी मूर्ति, चंबल माता की 40 मीटर ऊंची प्रतिमा के अलावा साहित्य चौक जैसे निर्माण इसे फेवरेट पिकनिक स्पॉट बनाएंगे।

बैराज से लेकर नयापुरा ब्रिज तक चंबल के दोनों किनारों पर 2.6 किलोमीटर लंबाई में बन रहे रिवर फ्रंट पर रामपुरा वाली साइड में देश-दुनिया की तस्वीरें दिखाई देगी, वहीं सकतपुरा वाली साइड में राजस्थान के वैभव से लेकर अध्यात्म के दर्शन होंगे। मनोरंजन और ज्ञान के साथ-साथ देश-दुनिया की प्रमुख शहरों के विशेष स्थानों का नजारा भी देख सकेंगे। चंबल माता की 40 मीटर ऊंची मूर्ति से लेकर दुनिया के सबसे बड़े घंटे और घड़ी को देखा जा सकेगा। नेहरूजी की विशाल प्रतिमा लगेगी। महाराणा प्रताप की प्रदेश में सबसे बडी प्रतिमा यहीं पर देखी जा सकेगी। दोनों तरफ को मिलाकर 22 से अधिक ऐसे स्थान बनाए जा रहे हैं, जहां लोगों को एक-एक स्थान घूमने में कम से कम 20 - 20 मिनट का समय लगेगा। वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रीट, राजस्थान हेरिटेज स्ट्रीट, साहित्य चौक व स्प्रिचुअल घाट बन रहे हैं। रिवरफ्रंट की डिजाइन हाड़ौती व राजपूताना आर्किटेक्चर पर आधारित होगी। इसमें नाव चलेगी, खाने-पीने के शौकीन लोगों के लिए 12 देशों का फूड स्ट्रीट, हैंडीक्राफ्ट बाजार और खूबसूरत गार्डन भी होंगे। मार्च 2022 तक इसको पूरा करने का टार्गेट रखा गया है।

रिवरफ्रंट पर बिजली आपूर्ति के लिए 33 केवी विद्युत सब स्टेशन का भी निर्माण होगा। इस कार्य पर 5 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च होंगे। शहर में चम्बल नदी के किनारे बसी बस्तियों को बाढ़ से बचाने के लिए रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। चम्बल नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए दोनों तरफ नालों को ट्रेप करते हुए गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए एसटीपी प्लांट का निर्माण प्रस्तावित है। दोनों किनारों पर घाट का निर्माण एवं विभिन्न प्रकार के स्कल्पचर आदि का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। यहां दोनों ही तरफ सेल्फी पाइंट और व्यू पाइंट बनाए जा रहे हैं। जहां लोग चंबल और सामने वाले घाट को देख सकेंगे और सेल्फी भी ले सकेंगे।

प्राइड ऑफ कोटा – सिटी पार्क

आई एल परिसर में बन रहा सिटी पार्क 79 एकड़ यानी 32 हैक्टेयर में फैला है। इस पार्क को शिक्षा नगरी कोटा को रिप्रजेंट करते हुए बनाया गया है। स्मार्ट सिटी और यूआईटी द्वारा तैयार करवाए जा रहे इस पार्क के निर्माण पर करीब 60 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।

साइंस म्यूजियम

इस पार्क में साइंस म्यूजियम बनाया जाएगा। इस म्यूजियम को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इनोवेटर्स और एन्टरप्रिन्योर्स यहां आकर मार्केट की जरूरत के लिए नई-नई जानकारियां जुटा सकेंगे।

स्टार प्लाजा

सिटी पार्क की एंट्री भी अलग होगी। यहां पर स्टार डिजाइन का प्लाजा बनाया जा रहा है, जिसमें से होकर लोग अंदर प्रवेश कर सकेंगे। इसमें दुकानें भी होंगी। बीच में 60 फीट ऊंचा फाउंटेन भी लगा होगा।

ट्री मैन

पर्यावरण और इंसान के रिश्ते को बताते हुए ट्री मैन का स्टेच्यू बनाया जा रहा है। जिसमें इंसान की आकृति है और उसके हाथों में से पेड़ की शाखाएं और पत्तियां निकल रही हैं।

सेव अर्थ प्लाजा

पृथ्वी को उससे बचाने का संदेश देते हुए यह सर्किल बनाया जा रहा है।

उल्टा पिरामिड

चारों तरफ छोटी पहाड़ियों के बीच उल्टा पिरामिड लगेगा, जिसमें इंसान अपनी इमेज देख सकेगा। यह सेल्फी और फोटो सेशन का एक अलग ही पाइंट होगा।

बॉटनिकल गार्डन

राजस्थान का पहला बॉटनिकल गार्डन सिटी पार्क में बनेगा। इस गार्डन में छोटे-छोटे माउंट्स बनाकर उन पर फूलों से लदे पौधे लगाए जाएंगे। यहां ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जिस पर 12 महीने ही फूल आएंगे।

यह जगह सेल्फी लेने वालों के लिए पहली पसंद होगी।

पार्क में 17 हजार पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। जिससे शहर की ग्रीनरी में करीब 66 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इससे आसपास के 8 किमी एरिया में कार्बन उत्सर्जन में 2 से 3 प्रतिशत की कमी आएगी। साथ ही 4 किमी क्षेत्र में 2 से 3 डिग्री तापमान में कमी आएगी। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी।

आर्ट गैलेरी, ओपन थिएटर

इस पार्क में कलाकारों के लिए आर्ट गैलेरी और ओपन एम्पिथिएटर भी बनाया जा रहा है। आर्ट गैलेरी में पूरे साल भर शहर के कलाकार अपनी कलाओं की प्रदर्शनी लगा सकेंगे। वहीं एम्पिथियेटर में नाट्यमंचन के कार्यक्रम हो सकेंगे।

कायनेटिक टॉवर

हवा की गति और ताकत को बताने के लिए यहां पर 40 फीट ऊंचा कायनेटिक टॉवर लगाया जा रहा है। यह टॉवर हवा के रूख के साथ स्वत: घूमेगा और डिजाइन बदलेगा। यह बिजली की बजाय हवा से ही चलेगा।

बोटिंग कैनाल

इस पार्क के भीतर सवा किलोमीटर लंबी बोटिंग कैनाल बनेगी। इसमें चप्पू से चलने वाली नाव से सैलानियों द्वारा बोटिंग की जा सकेगी। पार्क के बीच में टापू बनाया जाएगा। इसके आसपास कैनाल बनेगी।

ऑक्सीजोन में बडी संख्या में पक्षी भी रहेंगे। इसके अलावा तुलसी वन भी बनाया जाएगा। इसका निर्माण करने वाली कंपनी आगामी 10 साल तक इसका रखरखाव करेगी। ऑक्सीजोन का निर्माण करीब 35 हैक्टेयर क्षेत्र में होगा। इसमें गुरूद्वारा, मंदिर, डिस्पेंसरी और बिजली विभाग के दफ्तरों के लिए जगह छोड़ी गई है। ऑक्सीजोन में इस तरह के पेड़ लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि 4 किमी तक तापमान में कमी हो सकेगी।

देवनारायण पशुपालक योजना

पिछले कई सालों में शहर की सड़कों पर घूमते मवशियों के कारण हादसे बढ़े तो नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने शहर में पशुओं की समस्या दूर करने और पशुपालकों को नियोजित तरीके से पशुपालन में रोजगार देने के लिए योजना बनाई है। देश में पहली बार पशुपालकों के लिए कोटा में पशुपालक एकीकृत आवासीय योजना का कार्य शुरू हुआ है। इसका नाम देवनारायण नगर रखा गया है। इसमें पशुबाड़े के साथ रहने के लिए आवास भी दिया जा रहा है। यहां पशुपालक परिवारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पशु चिकित्सालय की भी सुविधा होगी। पशुपालकों के बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय भी खोला जाएगा। इसके पहले चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

बहूउद्देशीय देवनारायण पशुपालक योजना धर्मपुरा, पूनिया देवरी क्षेत्र के विकास में सहायक बनेगी। यहां डेयरी उद्योग नए स्वरूप में विकसित होगा। नगर विकास न्यास की ओर से करीब 105.09 हैक्टेयर भूमि पर बहुउद्देशीय पशुपालक योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। आवेदकों को बैंक की ओर से ऋण की सुविधा भी दी जा रही है। यहां प्रतिदिन निकलने वाले गोबर का निस्तारण करने के लिए गोबर गैस प्लांट लगाया जाएगा। देवनारायण योजना पर 300 करोड़ खर्च होंगे, इससे पशुपालकों का जीवनस्तर बेहतर बनेगा। पशुपालन और डेयरी व्यवसाय में नई श्वेतक्रांति होगी। शहर में घूम रहे आवारा मवेशियों से मुक्ति मिलेगी और दुर्घटनाएं नहीं होंगी। कम्प्लीट होने पर यह एशिया की सबसे बडी परियोजना होगी।

कोटा में विकास की गति कोरोना काल में भी अप्रभावित रही है। सभी योजनाएं साकार हो जाएंगी तो कोटा विकास के नए मानदंड छूएगा। •

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

10 हजार से अधिक क्लेम सबमिट, 8 हजार से अधिक लोग लाभान्वित

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेश में लागू होने के बाद से लगभग 5.86 करोड़ रुपये की राशि बुक कर 8,496 लोगो को निःशुल्क लाभान्वित किया जा चुका है। इसके लिये 10 हजार से अधिक क्लेम बीमा कम्पनी को सबमिट किये जा चुके है।

कोरोना महामारी के उच्च प्रसार को देखते हुए लाभार्थियों की सुविधा के लिए सम्बद्ध अस्पतालों के लिए अब कोविड-19 के उपचार के लिए पैकेजज की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई है। उपचार के पैकेजेज की दर भी बढ़ाकर 5000 प्रतिदिन से लेकर 9900 प्रतिदिन निर्धारित की गई है जिसमें योजना के लाभार्थी को परामर्श शुल्क, नर्सिंग चार्जेज, बैड, भोजन, निर्धारित उपचार, कोविड-19 टेस्ट, मॉनिटरिंग एवं फिजियोथैरेपी शुल्क, पी.पी.ई.किट, दवाएं एवं कंज्यूमेबल्स, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज, समस्त प्रकार की जांचे जैसे-बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इमेजिंग सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होंगी।

परिवेदनाओं का त्वरित हो रहा निपटारा, प्रत्येक परिवेदना का लगातार कर रहे निस्तारण

योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं को लेकर गठित कमेटी त्वरित रूप से परिवेदनाओं का निस्तारण लगातार कर रही है।

''मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी'', कोरोना संक्रमण रोकें : डॉ. रघु शर्मा

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मंत्री एवं भीलवाड़ा जिले के प्रभारी डॉ. श्री रघु शर्मा ने 17 मई को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से भीलवाड़ा जिला कलक्टर व जिला स्तरीय अधिकारियो के साथ बैठक कर कोरोना के बढ़ते प्रकरणों की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों व जारी लॉकडाउन के तहत वर्तमान परिस्थिति की जानकारी ली।

प्रभारी मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने व संक्रमित मरीजो को जल्द चिह्नित करने के लिए मोबाईल ओपीडी वेन द्वारा माईक सुविधा लगाकर 10 से ज्यादा गांवो में जाकर ज्यादा से ज्यादा एंटीजन टेस्ट करवाने को कहा।

उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फैल रहा है जिसको रोकने में वहां के नागरिकों व जन-प्रतिनिधि द्वारा ''मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी'' निभाकर संक्रमण को रोका जा सकता है।

डॉ. श्री शर्मा ने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के होम आइसोलेशन/क्वारंटाईन की व्यवस्था ना होने पर गठित विलेज ग्रुप द्वारा स्कूल या अन्य भवन में व्यवस्था कर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

राजस्थान कोरोना प्रबन्धन में देश में अग्रणी : मुख्य सचिव

राजस्थान ब्यूरोक्रेसी के मुखिया मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने पद भार ग्रहण करने के बाद अब तक 100 से अधिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग की हैं। विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों, सभी जिला कलक्टरों एवं कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए तैनात अधिकारियों से सम्पर्क कर मुख्य सचिव उन्हें नियमित दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इनके कार्यालय और निवास पर आमजन निर्बाध व बेहिचक शिकायतें लेकर इनसे मिलते रहते हैं।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य से बातचीत

संयुक्त निदेशक, जनसम्पर्क अरुण जोशी द्वारा की गई बातचीत के महत्त्वपूर्ण अंश

कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर सरकार के क्या प्रयास हैं ?

राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां मास्क लगाने की अनिवार्यता का कानून बनाया गया। राजस्थान पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से नियंत्रण के लिए सबसे पहले लॉकडाउन लगाया। केन्द्र सरकार ने हमारे बाद लॉकडाउन लगाया था। प्रारम्भ में कोरोना की जांच की क्षमता जहां शून्य थी, वहीं राज्य सरकार ने अपने प्रयास कर प्रतिदिन एक लाख से अधिक तक की क्षमता बढ़ाई है। शत प्रतिशत आरटी-पीसीआर जांचे की जा रही हैं।

कोरोना संक्रमण को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे किये गये तथा प्रारंम्भिक लक्षण पाये जाने पर दस लाख मेडिकल किट बांटे गये। ऑक्सीजन बेड की संख्या में वृद्धि की गई हैं। कोविड केयर सेन्टर आरम्भ किये गये हैं। मृत्युदर कम करने में राज्य ने कोरोना की प्रथम लहर में उल्लेखनीय कार्य किया। कन्टेनमेन्ट जोन बना कर संक्रमण को एक जगह पूरी आईईसी के विभिन्न तरीकों से ग्रामीण व शहरी लोगों को सीएबी (कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर) के लिए जागरूक किया गया। पुलिस द्वारा सीएबी पालना नहीं करने पर हजारों की संख्या में चालान किये गये। ऑक्सीजन ऑडिट, बेड मैनेजमेन्ट एवं एडमिशन पॉलिसी बनायी गयी। भारत सरकार से निरन्तर सम्पर्क रखकर ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया, टैंकर्स का अधिकतम उपयोग किया गया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गयी। क्राइसिस मैनेजमेन्ट के लिए मैं लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूं।

औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार की क्या कार्य योजना है ?

राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई एक्ट लाया गया जिसमें किसी भी एमएसएमई उद्यमी को बिना कन्वर्जन अपना प्लांट लगाने की अनुमति है। आरआईपीएस-2021में विभिन्न रियायतें एवं प्रोत्साहन पैकेज दिया गया। पर्यटन को इण्डस्ट्री का दर्जा दिया गया और 500 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया। इसी का परिणाम था कि रीको के प्लॉट 11 गुना अधिक कीमत में बिके है और रीको का लाभ दस गुना बढ़ गया है। प्रदेश में निवेश की संभावना बढ़ी है।

आमजन की शिकायतों के समाधान के क्या नए प्रयास हैं ?

मुख्य सचिव कार्यालय में आमजन की समस्याओं का समाधान किया जाता है। बैठकों के अलावा कोई भी परिवादी अपने कार्य के लिए कार्यालय में सीधे मुख्य सचिव से मिल सकता है। प्रतिदिन लगभग 100 लोग अपनी समस्याओं के साथ बेझिझक मिलते हैं और जहां तक संभव हो, अपनी समस्या के समाधान व व्यवहार से संतुष्ट होकर जाते हैं। इतना ही नहीं मेरे राजकीय निवास पर भी काफी लोग अपनी परिवेदनाओं के साथ मिलते हैं और मैं समाधान के गंभीर प्रयास करता हूं।

पत्राचार के समयबद्ध निस्तारण की क्या व्यवस्थाएं हैं ?

मुख्य सचिव कार्यालय में इस सम्बन्ध में तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हैं।

1. CLEARS-भारत सरकार में सचिव स्तर से मुख्य सचिव को प्राप्त पत्रों के संबंध में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए Chief Secretary's Letters Earmarked for Action & Response System (CLEARS) प्रारम्भ किया गया है, जिसकी प्रतिमाह मीटिंग में मोनिटरिंग होती है।

2. PINK LETTER SYSTEM-गुलाबी रंग के पेपर पर परिवेदनाएं सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित की जाती हैं, जिनका जवाब 15 दिवस से एक माह की अवधि में ग्रेविटी के अनुसार दिया जाना होता है।

3. LINES (Local Information Enquiry System)-प्रतिदिन के समाचारपत्रों में प्रकाशित महत्त्वपूर्ण समाचारों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर उन पर त्वरित कार्यवाही की जाती हैं। इनके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

अधिकारियों की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए क्या नवाचार किये जा रहे हैं ?

अधिकारियों की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए मैने एक नवाचार किया है। मैं जिला कलक्टरों को हर सप्ताह इन्स्पेक्शन के निर्देश देता हूं। हर शनिवार को सभी 33 जिला कलेक्टरों को सुबह 8 बजे एक थीम दी जाती है। जैसे नरेगा के कार्यों का इन्स्पेक्शन करने के लिए जो मुख्यालय से 50 किमी दूर हो, पालनहार योजना, सीएचसी, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, पी.डी.एस. अथवा ई-मित्र केन्द्र के निरीक्षण करने का टास्क दिया जाता है। इन सभी टास्क को पूरा करने के बाद सांय को सभी 33 जिला कलक्टर अपने-अपने दौरों एवं निरीक्षण की वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजते हैं। मैं सभी वीडियो को खुद देखता हूं और अपने कमेन्ट उन तक पहुंचाता हूं।

आधुनिक भारत के दृष्टा : भारत रत्न राजीव गांधी

– शुभ्रा शर्मा
शोध अध्येता

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय राष्ट्र के छठे प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी को जाता है। अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान श्री गांधी ने अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए।

स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले श्री गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से आगे बढाना चाहते थे और जैसा कि वे बार-बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाये रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में इक्कीसवीं सदी के भारत का निर्माण भी है।

40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। स्व. श्री राजीव गांधी संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र की सरकार का नेतृत्व किया। युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जानते थे कि लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका कितनी महत्त्वपूर्ण होती है, इसीलिए उन्होंने मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार दिलवाया।

ग्रामीण बच्चों को मुफ्त आधुनिक शिक्षा देने के मकसद से नवोदय विद्यालयों के शुभारंभ का श्रेय भी स्व. राजीव गांधी को ही जाता है। गांवों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा मिले इस सोच के साथ श्री राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की नींव डाली। श्री राजीव गांधी के समय में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई जिसके तहत पूरे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ।

स्व. श्री राजीव गांधी की 1988 में चीन की यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा थी। चीन के साथ संबंध सामान्य होने में यह यात्रा सहयोगी रही। सीमा विवादों के लिए चीन के साथ मिलकर बनायी गई ज्वाईंट वर्किंग कमेटी शांति की दिशा में ठोस कदम थी।

स्व. श्री राजीव गांधी जी की राजनीति में अपना करियर बनाने में कोई रूचि नहीं थी। उनके सहपाठियों के अनुसार उनके पास दर्शन, राजनीति या इतिहास से संबंधित पुस्तकें न होकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की कई पुस्तकें हुआ करती थीं। हालांकि संगीत में उनकी बहुत रुचि थी। उन्हें पश्चिमी और हिन्दुस्तानी शास्त्रीय एवं आधुनिक संगीत पसंद था। उन्हें फोटोग्राफी एवं रेडियो सुनने का भी शौक था।

हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। अपेक्षानुसार इंग्लैंड से घर लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की एवं वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया। जल्द ही वे घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए।

खेलों की बुनियादी सुविधाओं को भी पूरा करने में स्व. श्री राजीव गांधी ने पहल की। उन्होंने दक्षता एवं निर्बाध समन्वय का प्रदर्शन करते हुए चुनौतीपूर्ण कार्यों को संपन्न किया।

21 मई, 1991 को आतंकवादियों ने श्री राजीव गांधी की एक बम विस्फ़ोट में हत्या कर दी।

पूरा राष्ट्र उन्हें आज भी याद कर रहा है। उन्हें श्रद्धाजंलि दे रहा है। युवा प्रधानमंत्री भले ही अब नहीं है लेकिन उनके सपनों को साकार करने के लिए देश का युवा सजग है और अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के भारत की प्रगति के संबंध में उनके सपनों को साकार करने में सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट है। उनके सिद्धांतो पर चलकर देश एकता, अखण्डता और मजबूती के लिए कार्य करने को दृढ संकल्पित है।

फोटो–फीचर

लॉकडाउन में स्वअनुशासित पिंकसिटी

पद्म सैनी
छायाकार

नाहरगढ़ से जयपुर शहर का विहंगम दृश्य

जौहरी बाजार

चांदपोल

बड़ी चौपड़

छोटी चौपड़

एमआई रोड़

जौहरी बाजार

रामगंज

जौहरी बाजार

विधानसभा, जनपथ

जनपथ

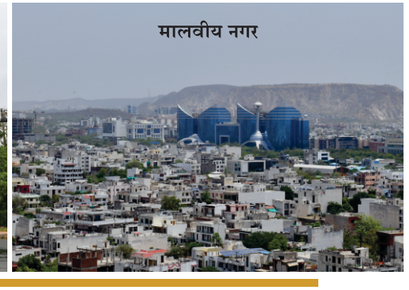

मालवीय नगर

अजमेर रोड़

अजमेर रोड़

दुर्गापुरा

आयुर्वेद : कोरोना से बचाव के उपाय

– वैद्य विजय प्रकाश गौतम
वरिष्ठ चिकित्सक, आयुर्वेद

कोरोना की द्वितीय लहर में आम जनता भीषण त्रासदी से गुजर रही है। राजस्थान सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की है। लेकिन लगातार रोगियों की संख्या में अभिवृद्धि चिन्ता का विषय है। सरकार ने पूर्ण क्षमता के साथ संसाधन उपलब्ध कराये हैं। लेकिन आम जनता स्वयं अनुशासित नहीं होगी तब तक कितने भी संसाधन हों उनकी न्यूनता स्वभाविक है।

द्वितीय लहर में जो लक्षण देखे जा रहे हैं उनमें

बुखार, खांसी के साथ बुखार, सिरदर्द, गले में दर्द/ खराश, श्वास लेने में तकलीफ, बदन दर्द, श्वास व खुशबू की क्षमता खोना, थकान एवं दस्त आदि कोरोना के प्रमुख लक्षण हैं। हम यदि सावधानी रखें तो हमारी रोग-प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है। इसके लिए आयुर्वेद की कुछ औषधियां जो सामान्य व सर्वसुलभ है, उनका नियमित प्रयोग किया जाये एवं दिनचर्या को ठीक ढंग से रखें व संतुलित पोषक आहार का सेवन करें तथा दैनिक व्यायाम व योग-प्राणायाम करें तो इस महामारी से लड़ने में शरीर को सक्षम बनाया जा सकता हैं।

सर्व सुलभ औषध

गिलोय के डंठल का रस अथवा क्वाथ, तुलसी के 4-5 पत्तो का रस, अश्वगंधा चूर्ण 3 से 5 ग्राम दूध के साथ, हल्दी पाउडर 1/4 से 1/2 चम्मच दूध में मिलाकर रात्रि में पीये, ताजा आंवले के रस अथवा चूर्ण को पानी के साथ और 5 से 6 कालीमिर्च सुबह-शाम लें।

रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि हेतु

तुलसी पत्र 4 भाग, दालचीनी 2 भाग, सोंठ 2 भाग, कालीमिर्च 1भाग का आयुष क्वाथ लिया जाये।

इनका क्वाथ बनाकर पीये – संशमनी या गिलोय घन वटी 500-500 मिली ग्राम भोजन के बाद, अश्वगंधा चूर्ण या केप्सूल, च्यवनप्राश 10-10 ग्राम, हल्दी व नमक के गरारे, केप आयुष 64 2-2 बार, सुबह-शाम योग- प्राणायाम, हल्का व्यायाम करें। इन सबके अतिरिक्त यदि हम अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान दें तो हमारी रोग-प्रतिरोधक क्षमता में अभिवृद्धि होगी। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व बिस्तर त्याग। उठने पर 2-3 गिलास पानी पीये। शौच आदि क्रिया व मुंह साफ करने के बाद नाक में 3-3 बूंद सरसों का तेल/ नारियल का तेल डालें। प्रतिदिन हल्का व्यायाम एवं योग प्राणायाम करें। 7 से 8 घंटे की नींद व संतुलित आहार का सेवन करें। हम अनुशासित जीवन जीये। मास्क का प्रयोग करें। निश्चित दूरी बनाए रखें व सकारात्मक विचारों को बढ़ायें।

कोविड-19 आयुष मंत्रालय, प्रोटोकॉल अनुसार आयुर्वेद दवाइयां

1. आयुष क्वाथ 150ml (1 कप)
   घटक द्रव्य:- (तुलसी पत्र- 4 भाग, दालचीनी-2 भाग, सौंठ-2 भाग, काली मिर्च-1 भाग)
2. संशमनी वटी 500mg सुबह शाम भोजन के बाद
3. अश्वगंधा चूर्ण 1 से 3 ग्राम या अश्वगंधा कैप्सूल या टैबलेट 500mg सुबह शाम खाने के बाद।
4. च्यवनप्राश 1/2 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी या दूध के साथ लें।
5. आंवला फल 1 या आंवला चूर्ण 1 से 3 ग्राम पानी के साथ लें।
6. हल्दी नमक के गरारे करें दिन में 3 बार।
7. 1/2 चम्मच हल्दी के साथ दूध का सेवन करे रात में सोते समय।
8. दालचीनी, सौंठ, इलाइची, कालीमिर्च के पानी के गरारे या सेवन करें।
9. सुबह-शाम योग प्राणायाम एवं हल्का व्यायाम करें।

रोगप्रतिरोधक क्षमतावर्धक औषधियां

द्रव्य नाम	द्रव्य परिचय	प्रयोग विधि
गिलोय (TINOSPORA-CORDIFOLIA)		इसके डण्ठल (shaft) को 5-10 gm लेकर इसका रस या काढ़ा बनाकर प्रतिदन पीना चाहिए।
तुलसी (Ocimum Sanctum)		4-5 तुलसी के पत्ते प्रतिदिन लेवें
अश्वगंधा (WITHMNIA-SOMNIFERA)		अश्वगंधा चूर्ण (3-5 gm) को 1 कप दूध के साथ प्रतिदिन सुबह-शाम लें।
हल्दी (CURCUMA LONGA)		एक चुटकी से लेकर 1/2 चम्मच तक 1 कप दूध में मिलाकर प्रतिदिन रात्रि को सोते समय पीया जाए।
दालचीनी (CINNAMONMUM ZEYLANICUM)		1/2 चम्मच चूर्ण 1 कप दूध तथा 1 कप पानी में उबालकर पियें।
आंवला (PHYLLANTHUS EMBLICA)		एक ताजा आंवला या 1 चम्मच चूर्ण पानी से नित्य सेवन करें।
कालीमिर्च (PIPER NIGRUM)		5-6 काली मिर्च सुबह-शाम प्रतिदिन लें

जरावस्था में देखभाल

करणीय आहार	करणीय विहार	सेवनीय रसायन/औषध	उपलब्ध सेवाएं
हल्का सुपाच्य भोजन जैसे- मूंग, जौ, दलिया ऋतु अनुसार	प्रातः/सायंकाल भ्रमण, दिन में पर्याप्त विश्राम	च्यवनप्राश, ब्राह्म रसायन, त्रिफला, द्राक्षावलेह, दशमूलारिष्ट	स्नेहन-स्वेदन (शुष्क स्वेदन, नाडी स्वेदन)
ताजा-गर्म, कम मसालेदार, सभी रसों से युक्त भोजन	अत्याधिक श्रम ना करें, चिंता, भय, क्रोध से मुक्त रहने का प्रयास करें	अमलतास, हरड, आंवला, गोखरू, गिलोय, पिप्पली, हल्दी, त्रिकटु	बस्ती चिकित्सा (निरूह-आस्थापन आदि)
ताजे फल, हरी सब्जियां, अंकुरित धान्य सूप, सलाद	हल्का योग, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम व तनाव मुक्त जीवन	अश्वगंधा, छाछ, लहसुन आंवला	आयुर्वेद विभाग द्वारा दी जा रही औषधियां
सौंठ/तुलसी/केसर/ इलायची/हल्दी/दालचीनी /पीपली/सौंफ युक्त दूध	ऋतु अनुसार आवास, वस्त्र आदि का सेवन	उपरोक्त सभी रसायन व औषधियों का प्रयोग वैद्यकीय परामर्श अनुसार ही करें।	अनुभवी चिकित्साधिकारियों द्वारा निःशुल्क परामर्श की सुविधा (I.P.D.)

काला गेहूं सुनहरा सच

- डॉ. देवदत्त शर्मा
पूर्व उप निदेशक, जनसम्पर्क

काला गेहूं! सुनने में यकायक विश्वास नहीं होता किन्तु जयपुर के दूधली गांव के एक शिक्षित युवक धर्मराज चौधरी ने कृषि में नवाचार कर काले गेहूं का उत्पादन कर अन्य किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने का द्वार खोल दिया है। जयपुर जिले के बस्सी कस्बे से करीब चार किलोमीटर दूर दूधली गांव इन दिनों कृषि में किए गए नवाचारों के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। यह काला गेहूं पौष्टिक होने के कारण सेहत के लिए सेहतमंद और शुगर फ्री होने के कारण डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए लाभदायक है।

विज्ञान विषय में स्नातक श्री धर्मराज अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल लेने के लिए जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक विधि से स्वयं के द्वारा तैयार 'जीवामृत' का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि उनके खेत की जैविक सब्जियां हाथों-हाथ बिक जाती हैं और मसाले तथा दालों की मांग बनी रहती है। काला गेहूं 65 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता है, इससे सामान्य गेहूं के मुकाबले उन्हें तीन से चार गुना अधिक दाम मिलते हैं। काला गेहूं का भूसा भी गुणकारी जिसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। काले गेहूं का दाना सामान्य गेहूं से थोड़ा पतला होता है किन्तु बालियों में कोई अंतर नहीं होता। पकने से पहले दोनों एक जैसी दिखाई देती हैं। इसी प्रकार दाना पतला होते हुए भी इसकी उपज में विशेष अंतर नहीं है। एक बीघा में करीब दस क्विंटल काले गेहूं की पैदावार होती है जो सामान्य गेहूं से थोड़ा कम है। किन्तु मूल्य तिगुना या उससे अधिक मिलने पर लाभ अधिक होता है। धुन के धनी श्री धर्मराज इससे पूर्व भी खेती-बाड़ी में अनेक नवाचार कर चुके हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने सहजने की खेती आरंभ की। आज उनके पास सहजने के करीब 75 हजार पेड़ हैं जिनके फूल, पत्तियां और फलियों की बिक्री से वह करीब तीस लाख रुपये सालाना कमा लेते हैं।

काले गेहूं पैदा करने की प्रेरणा कैसे मिली इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि लॉकडाउन और कोरोना के चलते यद्यपि लोगों में डायबिटीज, रक्तचाप और स्ट्रेस बढ़ा है किन्तु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। लोगों को हेल्दी डाइट मिले यह सोचकर वह हिमाचल के मोहाली स्थित नेशनल एग्रो फूड बायोटैक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से जुड़े सोलन केन्द्र पर गये। वहां काले गेहूं की खेती देखने की प्रेरणा मिली। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि उन्होंने यह सब कर दिखाया।

नेशनल एग्रो फूड बॉयोटैक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की कृषि वैज्ञानिक डॉ. मोनिका गर्ग के नेतृत्व में शोध किए गए इस गेहूं की किस्म को विकसित करने में सात वर्ष लगे। इंस्टीट्यूट द्वारा इसका पेटेंट कराया गया जिसे 'नाबी एमजी' नाम दिया गया है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सामान्य गेहूं में जहां एंथोसाइनिन की मात्रा 5 से 15 पीपीएम होती है वहीं काले गेहूं में 35 से 130 पीपीएम होती है। एंथोसाइनिन ब्लू बेरी जैसे फलों की तरह लाभदायक है। यह शरीर से फ्री-रेडिकल्स निकालकर बीमारियों की रोकथाम करता है और डायबिटीज तथा कैंसर की रोकथाम में मददगार है। इसमें प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट व पॉलिसेकेराइड होते हैं। आज के दौर में जहां पढ़े-लिखे युवक नौकरियों के चक्कर में रहते हैं वहां श्री धर्मराज ऐसे युवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। आज उनके साथ अनेक किसान और युवा जुड़ने लगे हैं तथा जैविक उत्पादों के प्रति जागरूक हो रहे हैं।

सशक्त लोकतंत्र की धुरी-मतदाता साक्षरता क्लब

– शिखा सोनी
स्वीप कसंलटेंट, निर्वाचन विभाग

राल्फ नैडर के अनुसार ''नागरिकता के बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता।'' एक सशक्त लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी एवं भागीदारी अहम भूमिका निभाती है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव एक सशक्त लोकतंत्र के स्थापना की पहचान होती है। मतदाता के इस महत्व को परिभाषित करते हुए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एन वैंकटचलैया ने लिखा था ''एक अदना सा व्यक्ति एक अदने से बूथ तक चलकर राजनीतिक क्रांति का अग्रदूत साबित हो सकता है।'' सफल लोकतंत्र में मतदाता की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं तत्पश्चात मतदाता जागरूकता को एक मुहिम का रूप देते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप फ्लैगशिप योजना 2009 में प्रारंभ की गई जिसका पूरा रूप ''सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन'' है।

लोकतांत्रिक और निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता सशक्त लोकतंत्र की मूल धारणा को अवतरित करती है एवं मतदाता को सशक्त, जागरूक, सतर्क एवं सुरक्षित बनाने के लिए शिक्षा का प्रमुख योगदान है। ''एक उदार समाज के मूल में उदार शिक्षा होती है और एक उदार शिक्षा के मूल में शिक्षण का कार्य होता है।'' यह सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम, स्वीप के रूप में प्रचलित है।

निर्वाचन साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) का गठन किया गया है। यह क्लब हर उम्र के भारतीय नागरिक को निर्वाचन साक्षरता देने का कार्य करते हैं। यह शिक्षा रोचक एवं मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से दी जाती है। लक्ष्य यह रहता है कि यह गतिविधियां व्यवहारिक रूप से संपादित की जा सके तथा तटस्थ एवं बिना किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हुए किया जाए।

मतदाता शिक्षा को गतिशील बनाने एवं उसे एक निश्चित लक्ष्य-केंद्रित दिशा देने हेतु इन ईएलसी की क्रियाशील भूमिका होती है। अप्रैल, 2021 में राजस्थान में आयोजित उपचुनाव में निर्वाचन साक्षरता क्लब की भूमिका को गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपादित किया गया। राज्य में सहाड़ा (भीलवाड़ा), राजसमंद (राजसमंद), सुजानगढ़ (चूरू) में दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को उपचुनाव की पूर्व तैयारी में मतदाता जागरूकता के लिये ईएलसी की कार्यान्विति एवं गतिशीलता सुनिश्चित की गई।

थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था कि ''महान लोकतंत्र को प्रगतिशील होना चाहिए'', इसी मूल धारणा के परिप्रेक्ष्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता एवं अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री कृष्ण कुणाल के कुशल नेतृत्व में निर्वाचन विभाग द्वारा एक निश्चित कार्ययोजना बना कर उसकी कार्यान्विति की गई। इसके अन्तर्गत ईएलसी के माध्यम से सम्पादित स्वीप गतिविधियों द्वारा ई-ईपीक, हेलो वोटर्स, पीडब्लयूडी, वोटर पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन एप, 1950 कॉल सेंटर सुविधा का विस्तृत प्रचार प्रसार किया गया।

यह निर्वाचन साक्षरता क्लब चार स्तर पर संचालित किये जाते हैं:-

1- ईएलसी- विद्यालय स्तर
2- ईएलसी- कॉलेज स्तर
3- ईएलसी- संगठन स्तर (वोटर्स अवेयरनेस फोरम) VAF
4- ईएलसी- समुदाय स्तर (चुनाव पाठशाला)

प्रत्येक स्तर के ईएलसी हेतु जिलेवार नोडल अधिकारी चिह्नित किए गए। इसके साथ ही पीडब्लयूडी एवं एनएसएस नोडल अधिकारी भी चिह्नित किये गये। इन अधिकारियों के साथ निरन्तर वेबिनार आयोजित किए गए, जिसमें स्वीप के संबंध में इनकी भूमिका एवं ईएलसी की गतिविधियों की कार्यान्विति के बारे में राज्य निर्वाचन विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं स्वीप कन्सलटेंट द्वारा विस्तृत आमुखीकरण किया गया। कोराना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में संबंधित दिशा-निर्देशों की पालना एवं वातावरण निर्मित करते हुए पोस्टर, स्लोगन, निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई। नये मतदाताओं को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु ईएलसी कॉलेज के माध्यम से कल्स्टर एनरोलमेंट ड्राइव (Cluster Enrollment Drive) आयोजित की गई।

आईईसी सामग्री को लेक्स, पोस्टर, ग्राफिक्स, होर्डिंग के रूप में प्रसारित किया गया। प्रत्येक जिले में विद्यालय एवं कॉलेज स्तर पर लीड ईएलसी का गठन किया गया जिसके द्वारा अपने परिक्षेत्र के समस्त ईएलसी हेतु मेंटोर एवं रिर्सोस के रूप में कार्य संपादित किया जाता है।

निर्वाचन साक्षरता क्लब के उद्देश्य :– लक्ष्य समूह को मतदाता पंजीकरण चुनावी प्रक्रिया और अन्य संबंधित बातों के बारे में व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से शिक्षित करना। प्रतिभागियों को ईवीएम और वीवीपैट से परिचित कराना और उन्हीं ईवीएम की मजबूती और ईवीएम का प्रयोग करके उत्पन्न होने वाले चुनाव प्रक्रिया की प्रामाणिकता के बारे में बताना। वोट का महत्त्व समझने में लक्ष्य समूह की मदद करना साथ ही वे अपने मताधिकार का प्रयोग पूरे विश्वास के साथ सुविधाजनक तरीके से तथा नैतिकता के साथ कर सकें इसमें उनकी सहायता करना। निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य समुदाय में निर्वाचन साक्षरता का प्रसार कर सकें इसके लिए उनकी क्षमता वृद्धि करना। जो सदस्य 18 वर्ष की आयु के हो जाएं उन्हें मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराने में मदद करना। चुनाव में भागीदारी करने और सोच समझकर व नैतिकता के साथ वोट देने की संस्कृति विकसित करना साथ ही इस सिद्धांत का पालन करने पर जोर देना कि 'हर वोट महत्त्वपूर्ण है' तथा 'कोई मतदाता न छूटे'। इस प्रकार स्वीप का प्रमुख लक्ष्य चुनाव के दौरान समस्त पात्र नागरिकों को मत देने एवं जागरूक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।•

देश में चर्चित

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

– गोपेन्द्र भट्ट
पूर्व अतिरिक्त निदेशक, जनसम्पर्क

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। विशेषकर जन स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के लिए वे चर्चित हैं। प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर करने की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना लाकर वे फिर से देश भर में चर्चित हो रहे हैं। देश में इस प्रकार की योजना लाने वाला राजस्थान पहला प्रदेश है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विभिन्न कार्यकालों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति से लेकर आम व्यक्ति, वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों और पत्रकारों की सेहत की चिंता की है। श्री गहलोत ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों विशेष कर किडनी (गुर्दा), लीवर और घुटने का प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, विभिन्न प्रकार के कैंसर आदि के उपचार के लिए हमेशा सरकारी खजाना खोल कर रखा है। श्री गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में सरकारी और निजी सभी अस्पतालों में गम्भीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के उपचार, ऑपरेशन आदि का पूरा पैसा सरकारी ख़ज़ाने से दिलवाने के साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जेनरिक दवाइयों की शुरुआत करवा कर देश भर में वाहवाही लूटी थी। उनकी यह योजना देश- प्रदेश में काफी लोकप्रिय हुई थी।

इस बार एक कदम और आगे बढ़ाते हुए श्री गहलोत, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आए हैं जिसमें प्रदेश के सभी नागरिकों को सरकारी और निजी सभी अस्पतालों में कैश लेस इलाज और प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक के बीमा कवर की सुविधा मिलेगी। विशेष कर निर्धन वर्ग के लोगों के लिए यह सुविधा बिल्कुल मुफ़्त और मध्यम एवं उच्च वर्ग के लिए मात्र 850 रु. मात्र के मामूली प्रीमियम शुल्क में यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राज्य के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये का कैशलेस बीमा दिया जाता है। इसमें आर्थिक रूप से ग़रीबों को बिना किसी प्रीमियम के यह बीमा मिलेगा जबकि अन्य सभी परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए 850 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना होगा।

इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान है। योजना से जुड़ने के लिए एक अप्रेल से तीस अप्रेल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए । इस अवधि को 31 मई तक बढ़ाया गया है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभान्वित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना-2011 के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड या नम्बर होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए सभी ज़िला कलक्टर ने ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर देखरेख समितियां गठित की है। योजना का लाभ एक मई से मिलना शुरु हो गया है। पंजीयन की तिथि से योजना का लाभ मिलेगा। किसी भी बीमा योजना से जुड़ने के लिए अमूमन उम्र सीमा भी कहीं न कहीं मायने रखती है लेकिन चिरंजीवी योजना पूरे परिवार के लिए है। योजना में परिवार के सदस्यों की संख्या की पाबंदी नहीं है और उम्र की भी सीमा नहीं है। जन्मे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी योजना के लाभार्थी होंगे। योजना में जुड़ने से पहले यदि कोई बीमारी से ग्रसित है, तो भी वह इस योजना का लाभ ले सकेगा। योजना में चिन्हित बीमारियों के लिए 50 हज़ार रुपये एवं गंभीर बीमारियों के लिए 4 लाख 50 हज़ार का बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न बीमारियों के 1,576 पैकेज शामिल किए गए हैं। राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना में राज्य के सभी परिवार और सभी आयवर्ग को शामिल किया गया है।

कोरोना के विकट समय में राज्य सरकार की नई पहल चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के लिए कुछ प्रतिपक्ष के नेताओं ने भी वक्तव्य जारी कर योजना की प्रशंसा की है। विकसित देशों की तरह जरूरतमंद, असहाय एवं वंचित वर्ग को स्वस्थ एवं सम्मानपूर्वक जीवन यापन की सुविधा देने तथा अमीरी-गरीबी की खाई को पाटने के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का समय आ गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इसी दिशा में राजस्थान सरकार का

ऐतिहासिक कदम है, जो प्रदेश के लोगों को इलाज के भारी भरकम खर्च की चिंता से मुक्त कर देगा।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क टीकाकरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने योजना की वेबसाइट chiranjeevi.rajasthan.gov.in का लोकार्पण भी किया। उन्होंने इस दौरान जयपुर, अजमेर और जोधपुर में टीका लगवाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं से संवाद किया। इन तीनों जिलों के चयनित लाभार्थियों को चिरंजीवी योजना के पॉलिसी दस्तावेज भी वितरित किए गए।

दूसरे राज्य भी करें ऐसी योजना पर विचार

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना के बाद हर प्रदेशवासी को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के उद्देश्य से यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में देश में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। उस समय देशवासियों को सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा और महात्मा गांधी नरेगा जैसे अधिकार आधारित कार्यक्रमों की सौगात दी गई। मनरेगा जैसा कार्यक्रम कोविड संकट में गरीब वर्ग के लिए वरदान साबित हुआ है। प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार देने की दिशा में चिरंजीवी योजना लागू की है।

सभी परिवार आवश्यक रूप से कराएं पंजीयन

श्री गहलोत ने कहा कि इस योजना का लाभ हर राजस्थान वासी तक पहुंचाने के लिए सभी परिवारों का पंजीयन आवश्यक है। इसके लिए पंजीयन की तिथि 30 अप्रेल से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। लोगों से अपील है कि वे अपने परिवार का पंजीयन आवश्यक रूप से कराएं और अन्य लोगों को योजना की जानकारी देकर पंजीयन के लिए प्रेरित करें और इसमें सहयोग करें।

महामारी से बचाव के लिए निःशुल्क टीकाकरण

मुख्यमंत्री ने राजस्थान में 18-45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि इतिहास रहा है कि महामारी से बचाव के लिए हमेशा टीकाकरण निःशुल्क किया गया है। भारत में सभी आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण निःशुल्क किये जाने के लिए हमने केन्द्र सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से मांग रखी थी, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा मांग नहीं माने जाने पर राज्य सरकार ने स्वयं 3 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करते हुए 18-45 वर्ष के आयु वर्ग को भी निःशुल्क टीकाकरण की योजना बनाई है।

चिरंजीवी योजना में दूसरे बीमा जैसी जटिलताएं नहीं

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश का हर व्यक्ति निरोगी और इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त हो। चिरंजीवी योजना इसी दिशा में उठाया गया क्रांतिकारी कदम है। स्वास्थ्य बीमा की इस अनूठी योजना में प्रदेशवासियों को पंजीयन के समय स्वास्थ्य जांच, परिवार के सदस्यों की संख्या, एक निश्चित अवधि बाद ही बीमा का लाभ मिलने जैसी जटिलताओं से मुक्त रखा गया है।

6500 करोड़ रुपये होंगे खर्च

चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कोविड संकट के कारण वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए चिरंजीवी योजना एवं 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए निःशुल्क टीकाकरण की शुरूआत की है। इन दोनों योजनाओं पर 6500 करोड़ रुपये की बड़ी राशि खर्च होगी।

मुख्यमंत्री ने समझा गरीबों का दर्द

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि जिन लोगों के पास आय के साधन नहीं हैं, उनके लिए बीमारी का इलाज एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने इसी दर्द को समझते हुए चिरंजीवी योजना लागू की है। निजी क्षेत्र में 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा के लिए भारी प्रीमियम चुकाना पड़ता है जबकि चिरंजीवी योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत कृषक, संविदा तथा मानदेय कर्मी और गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराया गया है। शेष परिवारों को मात्र 850 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना का लाभ मिलेगा।

1576 पैकेज शामिल, करीब 1100 अस्पतालों में उपचार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि 3500 करोड़ रुपये की लागत से संचालित इस योजना में हार्ट, कैंसर, किडनी डायलिसिस और कोविड जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1576 प्रकार के पैकेज शामिल हैं। राज्य के 765 सरकारी और 330 से अधिक संबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। •

देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू

2 अक्टूबर 1959 को नागौर में प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू पंचायती राज का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ करते हुए।

– देवी सिंह नरूका
पूर्व उप निदेशक, जनसंपर्क

पन्द्रह अगस्त, 1947 से 1964 की अवधि में लगभग 17 वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके प्रधानमंत्री काल में ही भारत ने संविधान का नया जामा पहना। पंचवर्षीय योजनायें बनाकर उन्हें कार्यान्वित किया गया। श्री नेहरू जैसे महान् व्यक्ति के इस महत्त्वपूर्ण पद पर आसीन रहने के कारण ही देश में लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हुई।

श्री जवाहरलाल नेहरू (1889-1964 ई.) सच्चे मायने में जननायक थे। कई बार जनसभाओं में उनकी धीर, गंभीर, ओजस्वी वाणी को सुनने का मौका मिला। उनके भाषण हिन्दी में होते थे। ऐतिहासिक और गूढ़ बातों को भी बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत करते थे। उनके भाषणों से राष्ट्रभक्ति और देश सेवा की प्रेरणा प्राप्त होती थी। उनका भाषण सुनकर लोग कहते थे और अखबारों में लिखा जाता था कि श्री जवाहरलाल नेहरू एक चलते फिरते विश्वविद्यालय हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार का राजस्थान से गहरा संबंध रहा है। इसलिए आजादी के पहले और उसके बाद भी कई बार वह इस प्रदेश में आये। विकास कार्यों को गति दी और लोगों में नवजीवन का संचार किया। श्री जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू बचपन में राजस्थान के खेतड़ी में रहते थे। श्री मोतीलाल नेहरू के बड़े भाई श्री नंदलाल खेतड़ी राज्य के दीवान थे।

इस प्रसंग में पं. झाबरमल शर्मा ने लिखा था कि सन् 1957 में पहली बार उनकी भेंट दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में श्री जवाहरलाल नेहरू से हुई। खेतड़ी की पुरानी बातों की चर्चा चल रही थी। इसी बीच श्री शर्मा ने पूछा, ''पण्डित जी बताइये तो आपके स्वभाव के इस करारेपन का क्या रहस्य है? जब श्री नेहरू मौन रहे तो श्री शर्मा ने कहा कि यह राजस्थान का दूध है पण्डित जी, जो श्री मोतीलाल जी ने पीया था। दूध का असर तीन पीढ़ी तक चलता है। इस पर श्री जवाहरलाल सरलता से मुस्करा गये''।

सन् 1929 में पहली बार श्री जवाहरलाल नेहरू अपने पिता श्री मोतीलाल नेहरू के साथ पुष्कर आये थे। सन् 1939 में पण्डित

जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद् के अध्यक्ष बने थे और सभी देशी रियासतों से उनका जुड़ाव हो गया था। सन् 1945 में जयपुर में प्रजामंडल के आपसी मतभेद दूर करने वे राजस्थान आये थे। देश की आजादी के बाद 18 अप्रेल, 1948 को उन्होंने उदयपुर में संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया।

सन् 1955 में उनके नेतृत्व में सैकड़ों वर्षों से अपनी जिद पर अड़े गाड़िया लुहारों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश किया। सन् 1959 में नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन करते हुए पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ''राजस्थान एक मायने में भारत का हृदय है। राजस्थान के लोगों ने अब निश्चय किया है कि वे लोकतंत्र को उठायेंगे। यह बड़ा काम है। ऐतिहासिक काम है। पहले दो चीजें थीं राजा और प्रजा। अब वे दोनों चीजें नहीं रही क्योंकि राजा भी प्रजा हो गया और प्रजा भी राजा हो गई।''

सन् 1953 में पिलानी यात्रा के दौरान खाने से पहले उन्हें सूप पिलाया गया। खास मेहमान के आगे कई लोग सूप लेकर पहुंच गये। विनोदी स्वभाव के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कराते हुए कहा ''भाई पिलानी है तो क्या पिलाओगे ही पिलाओगे कुछ खिलाओगे नहीं?''

सन् 1945 में जयपुर यात्रा के दौरान वह महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा आयोजित गार्डन पार्टी में शरीक हुए और रात्रि का भोजन जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ किया। 21 अक्टूबर, 1945 को वनस्थली में लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था से काफी प्रभावित हुए, उन्होंने कहा ''काश, मैं भी एक छोटी सी लड़की होता तो मुझे भी वनस्थली में शिक्षा पाने का अवसर मिलता''।

''राजस्थान एक मायने में भारत का हृदय है। राजस्थान के लोगों ने अब निश्चय किया है कि वे लोकतंत्र को उठायेंगे। यह बड़ा काम है। ऐतिहासिक काम है। पहले दो चीजें थीं राजा और प्रजा। अब वे दोनों चीजें नहीं रही क्योंकि राजा भी प्रजा हो गया और प्रजा भी राजा हो गई।''

सन् 1945 में ही राजस्थान यात्रा के दौरान अलवर में उन्हें एक हजार रुपये की थैली भेंट की गई। अपने भाषण में उन्होंने कहा ''राजपूताना और भारत अलग-अलग नहीं है। जो कुछ भारत में होगा, उसका प्रभाव राजपूताना पर भी पड़ेगा। हम स्वतंत्रता के मंदिर के बहुत निकट पहुंच गये हैं परंतु अभी हमें बहुत कुछ करना है''। इसी यात्रा के दौरान जोधपुर में भारत के भावी प्रधानमंत्री को मारवाड़ के शासक महाराजा उम्मेद सिंह ने कमला नेहरू कोष के लिए 25 हजार रूपये भेंट किये।

सन् 1960 में कोटा बेराज का उद्घाटन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ''इससे आपके बच्चें, बच्चों के बच्चें और उनके बाद भी लाभ उठाया जायेगा।''

सन् 1963 में जयपुर की सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा ''देश की उन्नति किसान तथा तकनीकी ज्ञान द्वारा ही संभव है। समाजवाद वैज्ञानिक तरीके से सीखने का लाजमी तरीका है। इसी प्रकार प्रजातंत्र का अर्थ भी राजनीतिक प्रजातंत्र तक ही सीमित न रहकर सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र भी है।''

27 मई, 1964 को प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के निधन पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था ''राजस्थान के निर्माण में श्री नेहरू हमारी प्रेरणा के स्त्रोत थे। आज का राजस्थान उनका सबसे बड़ा यादगार है।'' •

''देश की उन्नति किसान तथा तकनीकी ज्ञान द्वारा ही संभव है। समाजवाद वैज्ञानिक तरीके से सीखने का लाजमी तरीका है। इसी प्रकार प्रजातंत्र का अर्थ भी राजनीतिक प्रजातंत्र तक ही सीमित न रहकर सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र भी है''।

ओलम्पिक खेल और कोरोना

– एन. के. मिश्रा,
पूर्व उप निदेशक, जनसंपर्क

एक ओर प्रदेश के दिग्गज खिलाड़ी टोक्यो ओलम्पिक 2021 में जानदार–शानदार प्रदर्शन करने के लिए दिन–रात नियमित अभ्यास में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ इसी साल प्रस्तावित जुलाई–अगस्त में होने वाले इस भव्य प्रतिष्ठित विश्वस्तरीय स्पर्धा पर कोरोना महामारी के कारण घोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नियत कार्यक्रम गत वर्ष 2020 का था, जिसे टालकर उस समय 2021 का वक्त तय किया गया था पर महामारी संकट तो घटने के बजाय बढ़ रहा है। सन् 1896 से हर चार साल बाद होने वाली स्पर्धा में टोक्यो दोबारा संकट झेल रहा हैं। चूंकि 1940 में भी 'टोक्यो–हेल्सिंकी' में ओलम्पिक होने थे, पर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण प्रतियोगिता रद्द कर दी गई थी। बाद में 1952 में हेल्सिंकी और 1964 में टोक्यो में ओलम्पिक खेलों का आयोजन हुआ था।

विश्व खेलों के करीब सवा सौ सालों के इतिहास और बेहद कड़ी स्पर्धा में भारत ने अब तक 28 पदक जीते हैं। जिनमें हॉकी में 8 स्वर्ण, 1 रजत एवं दो कांस्य पदक सहित 11 मेडल है। कुश्ती में पहलवान श्री सुशील ने एक रजत और एक कांस्य तथा श्री के डी जाधव, श्री योगेश्वर और महिला पहलवान श्रीमती साक्षी मलिक ने भी कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में श्री अभिनव बिन्द्रा ने स्वर्ण एवं राजस्थानी खिलाड़ी श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रजत पदक तो श्री विजय ने भी रजत एवं श्री गगन नारंग ने कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में एग्लोइंडियन श्री नॉर्मन प्रिचार्ड ने दो रजत तथा बेडमिन्टन में पी वी सिंधु ने रजत पदक एवं सानिया ने कांस्य पदक जीता। मुक्केबाज श्री विजेन्द्र एवं श्रीमती मेरीकाम ने कांस्य पदक जीते। भारत्तोलक श्रीमती कर्णम मल्लेश्वरी ने तथा टेनिस खिलाड़ी श्री लियंडर पेस ने भी कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया।

खिलाड़ियों को अभिप्रेरित करने के लिए करीब एक दशक पहले 26 नवम्बर, 2012 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के ओलम्पिक पदक विजेताओं का मान–सम्मान समारोह आयोजित कर देश के सामने मिसाल पेश की थी। अब खेल विभाग श्री अशोक चांदना की कप्तानी में एक ओर खेल संघों को बढ़ावा देने के साथ खिलाड़ियों को अच्छी नौकरियां भी दे रहा हैं, वहीं खेल विश्वविद्यालय, स्कूल अकादमियां जीत पर जीत दर्ज कर रहे हैं। खेल महोत्सवों में राज्य के युवा खिलाड़ियों ने करिश्में दिखाए हैं। ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए मंच संरचना भी अब तैयार हो रही है।

ओलम्पिक आयोजन स्थल

1896 एथेन्स, 1900 पेरिस, 1904 सेंटलुइस, 1908 लंदन, 1912 स्टॉकहोम, 1916 बर्लिन (रद्द), 1920 एटवर्ण, 1924 पेरिस, 1928 एम्सटरडम, 1932 लॉस एंजिल्स, 1936 बर्लिन, 1940 टोक्यो–हेल्सिंकी (रद्द), 1944 लंदन (रद्द), 1948 लंदन, 1952 हेल्सिंकी, 1956 मेलबोर्न, 1960 रोम, 1964 टोक्यो, 1968 मेक्सिको, 1972 म्युनिख, 1976 मॉन्ट्रियल, 1980 मॉस्को, 1984 लॉस एंजिल्स, 1988 सियोल, 1992 बार्सिलोना, 1996 अटलांटा, 2000 सिडनी, 2004 एथेन्स, 2008 बीजिंग, 2012 लंदन, 2016 रियो, 2020–21 प्रस्तावित–टोक्यो–जापान। नियमानुसार ओलम्पिक का आयोजन शहर को दिया जाता है, देश को नहीं।

भारत को अभी तक के ओलम्पिक खेलों में 28 पदक मिले है। भारत को मिले पदकों की सूची–

स्वर्ण पदक

क्र.	वर्ष	खेल	नाम
1	1928	हॉकी	भारत
2	1932	हॉकी	भारत
3	1936	हॉकी	भारत
4	1948	हॉकी	भारत
5	1952	हॉकी	भारत
6	1956	हॉकी	भारत
7	1964	हॉकी	भारत
8	1980	हॉकी	भारत
9	2008	निशानेबाजी	अभिनव बिन्द्रा

रजत पदक

1	1900	एथलेटिक्स	नॉर्मन प्रिचार्ड
2	1900	एथलेटिक्स	नॉर्मन प्रिचार्ड
3	1960	हॉकी	भारत
4	2004	निशानेबाजी	राज्यवर्धन
5	2012	निशानेबाजी	विजय
6	2012	कुश्ती	सुशील
7	2016	बेडमिन्टन	पी वी सिंधु

कांस्य पदक

1	1952	कुश्ती	के डी जाधव
2	1968	हॉकी	भारत
3	1972	हॉकी	भारत
4	1996	टेनिस	लियंडर पेस
5	2000	भारत्तोलक	कर्णम मल्लेश्वरी
6	2008	कुश्ती	सुशील
7	2008	मुक्केबाजी	विजेन्द्र
8	2012	निशानेबाजी	गगन नारंग
9	2012	मुक्केबाजी	मेरीकॉम
10	2012	बेडमिंटन	सानिया
11	2012	कुश्ती	योगेश्वर
12	2016	कुश्ती	साक्षी मलिक

प्रदेश में गर्मियों में पेयजल प्रबंधन के सजग प्रयास

– मनमोहन हर्ष
उपनिदेशक, जनसम्पर्क

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गर्मियों के मौसम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जलदाय विभाग ने लगातार चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच प्रदेश में गर्मी के सीजन में पेयजल प्रबंधन की जिम्मेदारी का जवाबदेही के साथ लगातार निर्वहन किया है। राज्य सरकार के कार्यकाल के पहले साल में एक समय में मानसून की देरी के बीच लोगों को पेयजल की दृष्टि से किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए आवश्यकता वाले क्षेत्रों में रेल से जल परिवहन तक की व्यवस्था भी की गई। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के कारण लॉकडाउन, कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन जैसी परिस्थितियों के बीच, गर्मी के मौसम में जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला और विभागीय अधिकारियों की पूरी टीम ने प्रदेश में लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए सतर्कता से कार्य करते हुए लोगों को पूरी राहत प्रदान की। इस बार फिर कोरोना की दूसरी लहर से उपजे हालात के बीच राज्य के सभी हिस्सों में लोगों की मांग और आवश्यकता के अनुरूप पेयजल आपूर्ति के लिए जलदाय विभाग की टीम पूरी शिद्दत के साथ जुटी हुई है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशन में जलदाय विभाग द्वारा गर्मियों की शुरूआत के बहुत पहले से ही व्यापक स्तर पर तैयारियां आरम्भ कर दी गईं। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की तत्परता और विभागीय अधिकारियों की कार्यकुशलता के चलते हर जिले में कंटीजेंसी प्लान, आवश्यकता वाले क्षेत्रों एवं आबादियों के लिए जल परिवहन व्यवस्था, लोगों की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और अतिरिक्त संसाधनों और मानव श्रम को नियोजित करने की स्वीकृतियां गत फरवरी-मार्च माह में ही जारी कर दी गई थीं। इसी कारण मौजूदा समय में पूरे प्रदेश में सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिए सजगता से कार्य किया जा रहा है।

जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत द्वारा सभी जिलों में सुचारू पेयजल आपूर्ति की नियमित समीक्षा की जा रही है। सभी जिला कलक्टर्स से कहा गया है कि वे अपने जिलों में समस्त गांवों के स्तर पर गर्मियों के दिनों में संवेदनशीलता के साथ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पर पूरी नजर बनाए रखें। विभागीय अधिकारियों को 'कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर' का पालन करते हुए पेयजल व्यवस्था की राऊंड द क्लॉक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जलदाय विभाग ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत नहरबंदी से प्रभावित जिलों बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चुरू, नागौर, झुंझुनूं और सीकर जिलों में में भी लोगों को आवश्यकता अनुसार समयबद्ध आपूर्ति के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। जलदाय विभाग की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लिए अग्रिम तैयारी करते हुए कई खास व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी जिलों में आकस्मिक कार्यों के लिए जिला कलक्टर्स को 50-50 लाख रुपये की राशि के कंटीनजेंसी कार्य की स्वीकृति के लिए अधिकृत किया गया हैं। जिलों में कंटीनजेंसी प्लान के तहत इस राशि से कराए जा रहे कार्यों के अतिरिक्त भी किसी जिले में पेयजल व्यवस्था की दृष्टि से और अधिक राशि की जरूरत होने पर जिलाधिकारियों द्वारा प्रस्ताव तैयार कर जलदाय विभाग को भिजवाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिनके आधार पर आवश्यक स्वीकृतियां जारी की जाएंगी।

जलदाय विभाग द्वारा प्रदेश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों का आंकलन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जल परिवहन व्यवस्था के लिए 4180.25 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इसमें बीकानेर, झालावाड़, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और प्रतापगढ़ में अकाल से प्रभावित आबादी में जल परिवहन व्यवस्था के लिए 426.38 लाख रुपये की स्वीकृति भी शामिल है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 119 कस्बों में जल परिवहन व्यवस्था के लिए 2776.70 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी दी गई हैं। जिलों में टैंकरों से जल परिवहन व्यवस्था एवं दरों के निर्धारण के लिए जिला कलक्टर्स एवं उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समितियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया, इसके अनुरूप सभी जिलों में व्यवस्था की गई है। टैंकरों से जलापूर्ति में पारदर्शिता के लिए सभी जिलों में 3 कूपन सिस्टम की पालना तथा मॉनिटरिंग के लिए जीपीएस/ओटीपी व्यवस्था के बारे में भी जलदाय विभाग की ओर से सभी जिलों में निर्देश जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4937 हैंडपम्प एवं 2272 ट्यूबवैल की कमीशनिंग की गई थी। इस गर्मी के सीजन में भी प्रदेश में पेयजल की समस्या वाले गांव, कस्बों एवं आबादियों में नए ट्यूबवैल, हैंडपम्प आदि स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी चरणबद्ध तरीके से कमिश्निंग की जा रही हैं। इसके अलावा सभी जिलों में चीफ इंजीनियर एवं एडिशनल चीफ इंजीनियर स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों का प्रभारी बनाते हुए उनको पेयजल व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।•

कोरोनाकाल का रंगमंच - नेट थेट

– ईश्वर दत्त माथुर
पूर्व संयुक्त निदेशक, जनसंपर्क

रंग संवादों में अक्सर इस बात पर बहस होती रही है कि रंगमंच का विकास कैसे हो, दर्शक सांस्कृतिक गतिविधियों से अधिकाधिक कैसे जुड़े और क्या प्रेक्षागृह के इतर भी रंगकर्म संभव है? विद्वान अपनी बात को बल देने के लिए लोकनाट्य और लोककला शैलियों का उदाहरण देकर गोष्ठियों की इतिश्री कर लेते हैं ।

गत दो वर्ष से देश ही नहीं, अपितु दुनिया, एक ऐसे संकट के दौर से गुजर रही है जिसमें जीवन बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा। ऐसे में सांस्कृतिक गतिविधियों की चर्चा करना भी दुष्कर सी बात लगती है। प्रकृति का नियम है कि विकास चक्र हमेशा प्रवाहमान रहता है और बीज कभी मरता नहीं। सृजन प्रक्रिया की भी यही अवधारणा है।

जब लॉकडाउन में सब कुछ ठहर सा गया तो इस स्थिति में कलाकार अपनी भूमिका तलाशने लगे। बस एक ही चाहत रही कि दर्शक और रंगमंच का आकर्षण कभी कम ना हो। जयपुर के युवा रंगकर्मी और निर्देशक श्री अनिल मारवाड़ी ने एक ऐसे रंगमंच की परिकल्पना की जहां आकर कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें और शहर की सांस्कृतिक चुप्पी को तोड़ सकें। कलाकार सभागार के अवांछनीय बंधनों से परे रहकर खुलकर अपनी अभिव्यक्ति कर सकें तथा विषम परिस्थितियों में भी समाज व शहर को अपनी उपस्थिति और कला का भान कराएं। एक ऐसा रंगमंच जो कलाकार का हो । इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपने घर की छत पर नेट थेट (नेक्स्ट ऐरा थिएटर) की अवधारणा को साकार रूप दिया । इसके लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर नेट के जरिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जन-जन तक सांस्कृतिक गतिविधियों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इसका लाभ यह हुआ कि स्थानीय कलाकार का दायरा अब शहर के स्थान पर प्रदेश, देश और पूरी दुनिया हो गया। रंगकर्म के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित कलाकारों की एक छोटी सी टीम ने रंगमंच मे नवाचार , नेट थिएटर को मूर्त रूप दिया।

नेट थिएटर के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए रंग मंच के प्रसिद्ध बैक स्टेज के कलाकार और रंगकर्मी श्री राजेंद्र शर्मा राजू भी इस यज्ञ में अपनी आहुति देने लगे। घर की छत को थिएटर का स्वरूप दिया गया, जो तकनीकी दृष्टि से पूरी तरह खरा, व्यावहारिक तथा स्वाभाविक है। अल्प समय में नेट थिएटर को प्रसिद्धि मिलने लगी और कलाकारों ने निःशुल्क अपनी प्रस्तुतियां देकर सांस्कृतिक कर्म को बल दिया ।

नेट थेट पर अब तक 45 से अधिक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शित हो चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने भरपूर सराहा है। इनमें शास्त्रीय लोक गायन, लोक व शास्त्रीयनृत्य, नाटक, नुक्कड़ नाटक, भजन,कवि

सम्मेलन, मुशायरा, कव्वालियां और गजलों के कार्यक्रम प्रमुख हैं।

नेट थियेटर की सफलता इस बात से भी समझी जा सकती है कि इस के भावी स्वरूप को समझकर शहर के नामचीन कलाकारों ने इस थिएटर पर अपनी प्रस्तुतियां निःशुल्क दी हैं। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर लॉकडाउन में शहर को अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया । घर बैठे दर्शकों को मनोरंजन उपलब्ध कराया।

नेट थेट के माध्यम से कलाकारों को अपना रंगमंच मिला है, जिस पर किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। कलाकारों को यह मंच अब अपना मंच लगता है।

नेट थियेटर के सहज, सरल प्रबंधन का ही परिणाम है कि शहर के ख्यातनाम ग़ज़ल गायक उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन अब अपने निजी कार्यक्रमों के रिकॉर्डिंग किसी स्टूडियो में करने के बजाय इसी थियेटर पर करने की योजना बना रहे हैं। सारेगामापा के विजेता मोहम्मद वकील ने अपनी निजी रिकॉर्डिंग्स इसी रंगमंच पर शुरू कर दी है । नेट थियेटर पर प्रस्तुति देने वाले कलाकारों में ध्रुपद गायिका मधु भट्ट तैलंग, सितार वादक पंडित हरिहर शरण भट्ट, कथक गुरु श्रीमती रेखा ठाकुर,ज्योति भारती गोस्वामी, ख्यातनाम गजल गायक हुसैन बंधु, वकील मोहम्मद, प्रसिद्ध कव्वाल साबरी ब्रदर्स, युवा वायलिन वादक गुलजार हुसैन, सौरभ भट्ट, ख्यातनाम भवाई नृत्य श्री रूप सिंह शेखावत, लोक नृत्यांगना मधु शर्मा और पंडित आलोक भट्ट आदि कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को आनंदित किया है।

सीमित साधनों से शुरू किया गया नेट थियेटर अल्प समय में ही कलाकारों और दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया । नेट थिएटर के जरिए अब सांस्कृतिक गतिविधियां दर्शकों को मोबाइल के जरिए उनके सुविधा अनुसार सुलभ है । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेट थिएटर पर दीपक भारद्वाज के निर्देशन में मंचित संस्कृत नाटक, बलिदानम, को एक ही समय में लगभग 27000 से अधिक दर्शकों ने देखा।

रंगमंच पर दर्शक दीर्घा की एक सीमा है, वहीं नेट थिएटर का मंच सीमित दायरों के साथ भौगोलिक दायरों से भी मुक्त है। सरकार के परिवहन विभाग ने इस वर्ष सड़क सुरक्षा माह 2021 को प्रचारित करने के लिए नेट थेट को ही चुना और इसके माध्यम से नाट्य प्रस्तुतियां आयोजित की गईं।

अल्प समय में ही नेट थियेटर की सफलता और उसे प्रचार-प्रसार देने में मीडिया की भी अहम भूमिका रही है। लॉकडाउन के समय में शहर में हो रही इस महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रचारित कर कलाकारों की हौसला अफजाई की गई। नेट थियेटर के माध्यम से शहर में न केवल सांस्कृतिक वातावरण तैयार हो रहा है, बल्कि नव प्रतिभाओं को भी मंच उपलब्ध हो रहा है । यही नेट थिएटर का सामाजिक सरोकार भी है।

भविष्य में पर्यटकों के लिए नेट थिएटर एक ऐसा माध्यम बन सकेगा जहां पर्यटक हमारे सांस्कृतिक वैभव की झलक देख सकेगें तथा अपनी सहभागिता भी निभा सकेंगे। नेट थेट अब कलाकारों को समान अवसर प्रदान कर छोटे बड़े की खाई को भी पाट रहा है। अब तक के हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों से नेट थिएटर व कलाकारों को लाभ मिला है, यह उसका उजला पक्ष है।

इसके आवश्यक संसाधनों पर गौर करें तो प्रत्येक कार्यक्रम पर होने वाले आर्थिक व्यय भार को कैसे तर्कसंगत बनाया जाए, यह एक अहम प्रश्न है। इनमें लाइट, माइक, सेट आदि कार्य में जन सहभागिता, प्रायोजक और सरकारी मदद बड़ी भूमिका निभा सकती है। हालातों में नेट थिएटर कलाकारों का एक ऐसा मंच बन गया है जिससे दर्शकों का सीधा जुड़ाव है। यही रंगमंच आज के युग की मांग है।•

छोटे से गांव ''गादोला'' ने पेश की मिसाल

कोविड केयर सेंटर खुलने एवं सख्त पाबंदियों से गांव की बदली तस्वीर

कभी कोरोना के 86 मरीज़ थे, 17 लोगों की जान चली गई थी लेकिन आज एक भी एक्टिव केस नहीं

– प्रवेश परदेशी
जनसंपर्क अधिकारी

चित्तौड़गढ़ जिले का छोटा-सा गांव ''गादोला'' अब कोरोना रोकथाम को लेकर रोल मॉडल बन गया है। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आने के बाद इस गांव ने जो किया है वह अपने-आप में मिसाल बन गया है। अब इस मॉडल को न सिर्फ जिलेभर में बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी अपनाया जा रहा है। यह सब संभव हो सका है स्थानीय सरपंच श्रीमती रसाली देवी मीणा की सख्त पाबंदियों एवं जागरुकता अभियान तथा जिला कलक्टर श्री ताराचंद मीणा की दूरदर्शिता, त्वरित निर्णय व प्रशासनिक समझ से।

हर समय खुशहाल रहने वाले गांव ''गादोला'' में अचानक ही कोरोना का साया मंडराने लगा। इस महामारी की दूसरी लहर में देखते ही देखते पंचायत के 86 लोग चपेट में आ गए और 17 लोगों की जान चली गई। लोग डरे हुए थे और जिला प्रशासन भी इसे लेकर बेहद चिंतित था। जिला कलक्टर इन हालातों के बीच गांव पहुंचे और कोरोना से उपजे हालात पर लोगों से वार्ता की।

लेकिन परेशानी तब खड़ी हो गई जब गांव के लोगों ने कोरोना के सैम्पल देने और हॉस्पिटल आने से ही मना कर दिया। इन हालातों के बीच जिला प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई। ऐसे में जिला कलक्टर ने ग्रामीणों से पूछा ''अगर गांव में ही सर्व-सुविधायुक्त कोविड केयर सेंटर खोल दिया जाए, तो कैसा रहेगा?'' बस फिर क्या था...ग्रामीणों ने भी एक सुर में हां कर दी और कलक्टर ने भी त्वरित प्रयास शुरू कर दिए।

यहां बंद पड़े राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया। यहीं बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां, एम्बुलेंस, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ आदि उपलब्ध कराए गए। गांव के 58 पॉजिटिव मरीज़ यहां विश्वास के साथ भर्ती हुए और चिकित्सकों के परामर्श अनुसार ट्रीटमेंट लिया। गांव की कमान संभाल रही गादोला की महिला सरपंच ने हर संभव प्रयास किये। सरपंच ने गांव में स्वैच्छिक लॉकडाउन लगवाया, पनघट से पानी भरने पर पाबंदी लगाई, सरपंच ने घर-घर पानी की सप्लाई कराई, जरूरतमंद लोगों को घर पर ही राशन किट पहुंचाए, बाहर निकलने वालों को उनकी टीम ने टोका, सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिडकाव कराया, सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया और अन्य ज़िम्मेदारी बखूबी संभाली।

प्रशासन, चिकित्सकों की टीम, ग्राम पंचायत, अन्य जनप्रतिनिधि एवं आमजन के सामूहिक प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि आज गादोला में एक भी एक्टिव केस नहीं है। अंतत: अब कोविड केयर सेंटर पर ताला लटका दिया गया है क्योंकि गांव अब कोरोना से मुक्त है। इस सफलता से उत्साहित प्रशासन ने तो अब जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोविड केयर सेंटर खोलने की मुहिम छेड़ दी है। प्रत्येक पंचायत समिति को दस-दस लाख रुपये एवं प्रत्येक नगर निकाय को पांच-पांच लाख रुपये कोविड केयर सेंटर खोलने के लिए आंवटित किये गये हैं।

गादोला मॉडल के सफल होने के बाद जिले की कई पंचायतों में सुविधायुक्त कोविड केयर सेंटर खोले जा चुके हैं जहां लोग गांव में ही रह कर इलाज ले पा रहे हैं। इन प्रयासों से लोगों की जिला चिकित्सालय आने या अन्य सुदूर चिकित्सालयों तक जाने की झंझट दूर हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा लिए गए त्वरित निर्णयों जैसे जन अनुशासन पखवाडा, महामारी रेड अलर्ट एवं लॉकडाउन आदि से अब पूरे प्रदेश की तरह चित्तौड़गढ़ में भी कोरोना अब काबू में आ रहा है और लोग सरकार का धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं।•

मेडिकल कॉलेज झालावाड़

संजीवनी बूटी ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट

– हेमन्त सिंह
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

ऑक्सीजन केवल रंगहीन, स्वादहीन तथा गंध रहित गैस नहीं है बल्कि यह जीवों की प्राणवायु है। ऑक्सीजन वायुमण्डल में स्वतंत्र रूप में मिलती है। वायुमण्डल में इसकी मात्रा लगभग 21 प्रतिशत है। कुछ सैकण्ड के लिए अगर आप अपने नाक और मुंह को बंद रखें तो कुछ ही देर में आपका दम घुटने लगेगा, सांसें थमने लगेंगी, प्राण जाते दिखेंगे। तुरंत आपको अपने बंद मुंह व नाक खोलकर प्राणवायु ऑक्सीजन लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। जैसे ही ऑक्सीजन फेफड़ों में जाएगी वैसे ही आपको इस ऑक्सीजन गैस के प्राणवायु होने की सार्थकता का पता चलेगा।

कोविड-19 वायरस के संक्रमण के कारण सम्पूर्ण विश्व में इस महामारी से ग्रसित मरीजों को कृत्रिम चिकित्सकीय ऑक्सीजन गैस के माध्यम से उनके प्राणों की रक्षा की गई है। भारत में इस महामारी के दौर में सम्पूर्ण विश्व सहायता के लिए आगे आया है। विश्व के अनेक देशों से भारत को ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट, ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर, रेमडेसिविर इन्जेक्शन सहित अन्य चिकित्सकीय उपकरण एवं जीवन रक्षक दवाइयां सहायता के रूप में मिली हैं। भारत की मदद के लिए इंग्लैण्ड ने भी तीन पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट भेंट किए हैं। भारत सरकार ने यह तीन ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट्स जे एस बी सिविल हॉस्पिटल, काजल गांव, चिरांग, आसाम, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर तथा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज को आवंटित किये हैं।

नई दिल्ली से एनडीआरएफ टीम की सुरक्षा में 10 मई, 2021 को मेडिकल कॉलेज झालावाड़ पहुंचे पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट को जिला कलक्टर हरि मोहन मीना की अगुवाई में मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. शिव भगवान शर्मा एवं श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय अधीक्षक डॉ. संजय पोरवाल द्वारा ग्रहण किया गया। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मेडिकल कॉलेज झालावाड़ के लिए इस प्लान्ट का आना संजीवनी बूटी आने के समान है।

इंग्लैण्ड से भेंट में प्राप्त पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट वायुमण्डल से वायु लेकर पहले ऑक्सीजन कन्स्ट्रेटर में एकत्रित करता है। फिर विभिन्न फिजिकल, केमिकल एवं मैकेनिकल क्रियाओं के माध्यम से वायु में से नाइट्रोजन, कार्बनडाइआक्साइड एवं अन्य गैसों को अलग कर हमें 96 प्रतिशत शुद्ध ऑक्सीजन देता है। इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट की खासियत यह है कि इसमें किसी भी तरह के कच्चे माल या लिक्विड

ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। यह ऑक्सीजन जनरेट करने का सबसे अच्छा व सस्ता स्रोत है। यह बहुत उच्च क्वालिटी का ऑक्सीजन प्लान्ट है जो सामान्य से 20 प्रतिशत कम विद्युत खर्च पर ऑक्सीजन गैस पैदा करता है। यह जनरेशन प्लान्ट प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन तथा प्रतिदिन 100 बड़े ऑक्सीजन सिलेण्डर के बराबर कृत्रिम ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता रखता है। इस प्लान्ट के लगने से झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय में भर्ती 100-150 कोविड मरीजों को प्रतिदिन ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी। यह प्रेशर स्विंग एडजोरप्शन प्लान्ट है जो प्रेशर से ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स को पकड़-पकड़ कर अलग कर कृत्रिम शुद्ध ऑक्सीजन तैयार करता है।

ऑक्सीजन प्लान्ट प्रभारी डॉ. अकील हुसैन ने बताया कि जब मरीज के फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है तो वह कमजोर फेफड़ों के कारण वायुमण्डल में मिलने वाली वायु का शोधन करने में अक्षम होने के कारण ऑक्सीजन नहीं ले पाता है तो उसे प्लान्ट से तैयार की गई कृत्रिम शुद्ध ऑक्सीजन की सहायता देकर उसका इलाज किया जाता है। यह प्लान्ट अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों के लिए संजीवनी का काम करेगा। •

21वीं सदी के विद्यालय का सपना

बम्बोरा में हो रहा साकार

– हितेश भारद्वाज
पत्रकार

राज्य सरकार की पहल पर विद्यालय का कायाकल्प कर उसके रूप को निखारा जा रहा है। अलवर जिले का एक राजकीय विद्यालय राज्य ही नहीं देश में भी अपनी पहचान बना रहा है। अलवर जिले के किशनगढ़ उपखण्ड के छोटे से गांव बम्बोरा का राजकीय विद्यालय जर्जर अवस्था में था। विद्यालय के कायाकल्प के साथ 21वीं सदी का विद्यालय बनाने की संकल्पना को लेकर इसमें ऑडिटोरियम के साथ-साथ कॅरियर लैब और लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। कॅरियर लैब अपनी तरह की देश की पहली लैब होगी, जो किसी सरकारी विद्यालय के प्रांगण में बनने जा रही है।

यह प्रयास सफल हुआ अनुकम्पा नियुक्ति पाकर लिपिक के रूप में कार्य करने आये श्री अंकित भार्गव के सपने से। विद्यालय को 21वीं सदी का विद्यालय बनाने के इस कार्य को संस्था प्रधान श्रीमती वन्दना कुमारी, शिक्षक श्री सुशील शर्मा, ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष श्री हरचन्द गुप्ता और सचिव श्री फूल सिंह चौधरी सहित जिले के भामाशाहों और स्वयं सेवी संस्थाओं ने सजीव रूप दिया। इन सब के बलबूते एक छोटे से गांव में 21वीं सदी का विद्यालय बनाने का कार्य प्रगति की ओर अग्रसर है।

बम्बोरा की ग्राम विकास समिति ने गांव के विद्यालय में बन रही देश की पहली कॅरियर लैब के सपने के विचारों को साझा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से भेंट की। ग्रामीणों की इस पहल से प्रभावित मुख्यमंत्री अगले ही दिन अपने ट्वीट में सरकारी विद्यालय को 21वीं सदी के विद्यालय में तब्दील करने के प्रयास को सराहा और साथ ही साथ 5 लाख रुपये की राशि विद्यालय में बन रही कॅरियर लैब के लिए स्वीकृत की। वहीं कॅरियर लैब के उद्घाटन के लिए आने का निमंत्रण भी स्वीकार किया। इस लैब का शुभारम्भ 15 अक्टूबर, 2021 को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पर होगा, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सहित प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे।

युवाओं को सही दिशा प्रदान करेगी कॅरियर लैब–कॅरियर लैब व लाइब्रेरी का नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इस लैब को देखने के लिए देश के बुद्धिजीवी वर्गो के नामचीन लोग आ चुके हैं और इस प्रयास की सराहना कर चुके हैं। गांव की ग्रामीण विकास समिति इस निर्माण कार्य की देखरेख कर रही है। जनसहयोग से बन रही इस 3200 वर्ग फीट लैब में कॅरियर से सम्बन्धित गतिविधियां होंगी, वहीं एक पुस्तकालय होगा, जिसमें करीब 30 हजार पुस्तकों का संग्रह होगा। इस लैब और लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य विद्यालय को ज्ञान का ऐसा केन्द्र बनाना है, जो देश के युवाओं को सही दिशा की ओर अग्रसर कर सके। इस लैब में वर्तमान समय के ज्ञान और वैश्विक परिदृश्य को ध्यान

में रख कर कॅरियर की सम्भावनाओं को तलाशा व तराशा जायेगा।

वैज्ञानिक नजरिये से हो कॅरियर का चयन

डॉ. अब्दुल कलाम कॅरियर लैब और लाइब्रेरी जनसहयोग पर आधारित एक विचार है, जिसे बम्बोरा की ग्रामीण विकास समिति के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। देश के हर युवा और बच्चे को कॅरियर बनाना है। कॅरियर को थोपने की बजाय पहले रुचियों को पहचानना होगा और फिर बच्चे में वैज्ञानिक नजरिया विकसित करना होगा। युवाओं को गांवों में सुविधा नहीं मिल पाती है शुरूआत में ही भटकाव की स्थिति में आ जाते है, युवा जीवन प्रभावित हो जाता है। ऐसे में सरकारी विद्यालयों को ज्ञान केन्द्र बना कर राष्ट्र निर्माण में महत्ती भूमिका का निर्वहन किया जा सकता है।

सिरोही : कोरोना से निजात के नए प्रयास

– हेमलता सिसोदिया
जनसम्पर्क अधिकारी

कोरोना महामारी के दौर में जिला अस्पताल सिरोही व मानसरोवर अस्पताल आबूरोड में भर्ती मरीजों के उपचार के लिए नवाचार किये गए है। प्रत्येक भर्ती मरीज के बेड के साथ एक राइटिंग पेड रखवाने की व्यवस्था को शुरू किया गया है। राइटिंग पेड पर भर्ती मरीज के सामान्य पैरामीटर्स का दिन में चार बार अंकन किया जाकर ड्यूटी पर उपस्थित चिकित्सक एवं नर्सिंगकर्मी द्वारा नोट लिखकर हस्ताक्षर करवाए जा रहे है। लोगों की सहायता के लिए 24 घंटे संचालित कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कोविड-19 मरीज की काउंसिलिंग के लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सक लगाए जाने की व्यवस्था भी की गई।

जिला कलक्टर श्री भगवती प्रसाद द्वारा किए गए नवाचार में कोरोना के मरीज के पलंग पर एक राइटिंग पेड लगाया गया है, जिसमें मरीज का नाम, पता, उम्र और मरीज की भर्ती तिथि का अंकन किया गया है। चार्ट में पल्स, बीपी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, सीटी स्कोर इत्यादि को शामिल किया गया है, जिसे चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ द्वारा विजिट के समय प्रातः सायं एवं रात्रि में तीन वक्त भरा जा रहा है साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण के वक्त इस चार्ट का अवलोकन किया जा रहा है, जिससे कि मरीज की स्थिति का आंकलन किया जा सके।

लोगों की सहायता के लिए 24 घंटे संचालित कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कोविड-19 मरीज की काउंसिलिंग के लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सक लगाए जाने की व्यवस्था भी की गई है।

जिला कलक्टर की इस पहल से भर्ती मरीजों की समय पर बेहतर देखभाल के साथ उपचार हो रहा है। वार्ड में सकारात्मक माहौल उत्पन्न करने के लिए प्रात: काल योग प्रशिक्षक के माध्यम से कोविड से जुड़े हुए सकारात्मक संदेश का प्रसार करवाया जा रहा है।

कोविड-19 वार्ड में सीसीटीवी कैमरे और टीवी स्क्रीन के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है ताकि मरीजों के परिजनों व जनता में विश्वास एवं पारदर्शिता बनी रहे। इससे मरीजों की स्थिति की बेहतर मॉनिटरिंग आसानी से हो पा रही है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2021

प्रधानमंत्री ने राजस्थान की विभिन्न पंचायतों को किया पुरस्कृत

मुख्यमंत्री ने वर्चुअल समारोह में लिया भाग

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 अप्रेल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।

इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने वी.सी. के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत राजस्थान सहित आंध्रप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के 5002 सीमावर्ती गांवों के 4 लाख 9 हजार सम्पत्ति धारकों को ई-प्रोपर्टी कार्ड (पट्टे) वितरित किए। इस योजना के तहत ही राजस्थान के जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील के 51 राजस्व गांवों के 616 लोगों को पट्टे वितरित किए गए।

प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के तहत कोटा जिला परिषद को 50 लाख रुपये, पंचायत समिति कोटड़ा (उदयपुर) एवं पंचायत समिति चिड़ावा (झुंझुनूं) को 25-25 लाख रुपये और ग्राम पंचायत त्योंदया (झुंझुनूं), ग्राम पंचायत 4 एनएन चानना (श्रीगंगानगर), ग्राम पंचायत थूर (उदयपुर), ग्राम पंचायत निढारिया कलां (धौलपुर) तथा ग्राम पंचायत बर (पाली) को 10-10 लाख रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार राशि बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरित की गई।

साथ ही, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार के तहत झुन्झूनू जिले की भोजासर ग्राम पंचायत को भी 10 लाख रुपये, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार के तहत पंचायत समिति मूंडवा-नागौर की ग्राम पंचायत अरवर को 5 लाख रुपये तथा बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना के तहत पंचायत समिति नावां की ग्राम पंचायत मिण्डा को 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरित की गई।

दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के तहत कोटा जिला परिषद को 50 लाख रुपये, पंचायत समिति कोटड़ा (उदयपुर) एवं पंचायत समिति चिड़ावा (झुंझुनूं) को 25-25 लाख रुपये और ग्राम पंचायत त्योंदया (झुंझुनूं), ग्राम पंचायत 4 एनएन चानना (श्रीगंगानगर), ग्राम पंचायत थूर (उदयपुर), ग्राम पंचायत निढारिया कलां (धौलपुर) तथा ग्राम पंचायत बर (पाली) को 10-10 लाख रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया।

वर्चुअल समारोह में मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव राजस्व श्री आनंद कुमार, शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल, आयुक्त सेटलमेंट श्री महेन्द्र पारख सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रक्त और प्लाज्मा दान से बचेंगी जिंदगियां

कोरोना महामारी के दौर में स्वस्थ व्यक्तियों को रक्तदान और कोरोना को हराकर आए लोगों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए। ऐसा कर कई लोगों को जीवन दान दिया जा सकता है।

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा 3 मई को राजस्थान नर्सेज कौंसिल की ओर से आयोजित 13वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअल माध्यम से बोल रहे थे। रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन से पूर्व आरटी-पीसीआर टेस्ट अवश्य कराएं। कई शोधों में यह पाया गया है कि वैक्सीनेशन के 3 माह बाद तक रक्तदान नहीं किया जा सकता। ऐसे में युवा वैक्सीन लगवाने से पहले रक्तदान जरूर करें।

हेल्थ वर्कर्स का योगदान और प्रयास सराहनीय

डॉ. शर्मा ने कहा कि राजस्थान नर्सेज कौंसिल की ओर से बीते 13 वर्ष से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है जो कि सराहनीय है। उन्होंने हेल्थ वर्कर्स को सलाम करते हुए कहा कि रक्तदान शिविर का कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए आयोजन करना एक अभूतपूर्व प्रयास है। वर्तमान दौर में रक्तदान के साथ प्लाज्मा डोनेशन की भी आवश्यकता है जिससे कि अधिक से अधिक कोरोना संक्रमितों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सके। उन्होंने कहा कि पहली लहर में राजस्थान सरकार के प्रबंधन की देश दुनिया में चर्चा हुई। प्रदेश में बीते एक वर्ष के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत किया गया है। इसी का नतीजा है कोरोना महामारी की दूसरी लहर का राज्य मजबूती के साथ सामना कर पा रहा है।

अधिक ऑक्सीजन व अन्य संसाधनों के लिए प्रयास जारी

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभाग की ओर से सभी प्रकार के संसाधनों में वृद्धि की गई है। जिसमें मुख्य रूप से बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सम्मिलित है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है लेकिन इनकी सप्लाई केन्द्र सरकार की ओर से सुनिश्चित की जा रही है। इसलिए प्रदेश सरकार इनकी उपलब्धता के लिए काफी हद तक केन्द्र पर निर्भर है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में भी संक्रमित की जान मेडिकल या अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव में ना जाए।

चिकित्सा विभाग के प्रयास सराहनीय

स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में वर्चुअली सम्मिलित हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री वैभव गहलोत ने राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के इस प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमारे हेल्थ

सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा और राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष श्री वैभव गहलोत नर्सेज कौंसिल के रक्तदान कार्यक्रम में वर्चुअल चर्चा करते हुए

कर्मियों का यह प्रयास सभी को रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित करेगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए चिकित्सा विभाग पूर्ण रूप से प्रयासरत है। यह हम सभी का दायित्व है कि हम कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें और राज्य सरकार की ओर से लागू किए गए जन अनुशासन पखवाड़े में सहयोग करें। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में हम कोरोना की दूसरी लहर को जल्द ही हराने में कामयाब होंगे।

नर्सिंग सर्विस ने किया 'की फैक्टर' का काम

आरयूएचएस के वाइस चांसलर डॉ. राजाबाबू पंवार ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के नर्सिंग सर्विस ने ''की फैक्टर'' का काम किया है। रक्तदान जैसा पुनीत काम बड़ी सेवा में आते हैं।

50 नर्सिंगकर्मियों ने किया रक्तदान

राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से आयोजित 13 वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 50 से अधिक नर्सिंग कर्मियों ने रक्तदान किया।•

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

– हरि शंकर आचार्य
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

कोविड संक्रमण की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद बीकानेर का स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, कृषि एवं कृषक कल्याण के अपने पुनीत संकल्प को लगातार आगे बढ़ा रहा है। तीन दशक से भी अधिक समय से अनेक उतार-चढ़ाव के बावजूद अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका यह विश्वविद्यालय पिछले एक साल में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर न केवल सौ से अधिक कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, बैठकें आयोजित करवा चुका है, बल्कि राजस्थान का पहला वर्चुअल दीक्षांत समारोह और पहला वर्चुअल कृषि मेला आयोजित करते हुए अपनी पहचान को और अधिक सुदृढ़ किया है।

किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने की राज्य सरकार की संकल्पना पर खरा उतरते हुए इस विश्वविद्यालय ने कुलपति प्रो. आर. पी. सिंह के नेतृत्व में अनेक नवाचार किए गए। कोविड संक्रमण की परिस्थितियों में विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावित नहीं हुआ। किसानों को भी नियमित मार्गदर्शन मिलता रहा, जिससे 'धरतीपुत्रों' की राह भी आसान हुई। इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न कृषि सहायक प्रकाशनों के ई-संस्करण के रूप में किसानों और विद्यार्थियों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का 17वां तथा प्रदेश का पहला वर्चुअल दीक्षांत समारोह 28 अगस्त, 2020 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। समारोह के दौरान राज्यपाल श्री मिश्र ने 906 विद्यार्थियों को उपाधियां, छह विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक तथा दो विद्यार्थियों को चौधरी चरण सिंह स्मृति प्रतिभा पुरस्कार प्रदान किए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में बनने वाले संविधान पार्क का ई-शिलान्यास तथा दो पुस्तकों के ई-संस्करण का विमोचन किया। विश्वविद्यालय के इस प्रयास को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला।

इसी शृंखला में विश्वविद्यालय द्वारा वर्चुअल किसान मेला 22 और 23 दिसम्बर, 2020 को आयोजित किया गया। इस मेले में पांच राज्यों के किसानों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भागीदारी निभाई। राजस्थान के लिए यह पहला मौका था, जब किसी विश्वविद्यालय द्वारा वर्चुअल माध्यम पर किसानों को आमंत्रित करते हुए देश-विदेश के

विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया गया। इसी प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार प्रसार सलाहकार समिति तथा अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठकें वर्चुअल माध्यम पर 28 दिसम्बर, 2020 को आयोजित की गई।

विश्वविद्यालय द्वारा एक ओर नवाचार करते हुए कृषि महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय तथा कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों के स्नेह मिलन समारोह भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किए गए। इन समारोहों में देश और दुनिया में रहने वाले विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों ने शिरकत की। विश्वविद्यालय ने 14 से 20 सितम्बर 2020 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया।

ई-प्रकाशनों को प्रोत्साहित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कृषि महाविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका 'मरू कृषक', प्रसार शिक्षा निदेशालय की मासिक पत्रिका 'चोखी खेती', अनुसंधान निदेशालय की 'वन डिकेड ऑफ रिसर्च' के अलावा कृषि मार्गदर्शिका और मासिक ई-बुलेटिन के माध्यम से किसानों और कृषि विद्यार्थियों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत कृषि, गृह विज्ञान और कृषि व्यवसाय प्रबंधन के विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावित नहीं हो, इसके मद्देनजर ई-अध्ययन की रूपरेखा बनाई गई। प्रत्येक कक्षा के अनुसार सप्ताह भर का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा कृषि पंचांग का प्रकाशन किया गया। यह पंचांग वास्तव में कैलेण्डर के साथ, प्रति माह किए जाने वाले खेती योग्य कार्यों, विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों, महत्त्वपूर्ण दूरभाष नंबर एवं ई-मेल की जानकारी उपलब्ध करवाने वाला एक बहुआयामी संकलन है। कुलपति की पहल पर विश्वविद्यालय प्रभार वाले सभी छह जिलों की समस्त ग्राम पंचायतों तक यह 'कृषि पंचांग' पहुंचाए जा रहे हैं।

इस पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया, जिससे विद्यार्थियों को यह जानकारी रहे कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए तथा इनके माध्यम से किसानों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाई गई। इन सभी के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा किसानों के लिए नए मोबाइल एप भी विकसित किए गए। जिनके माध्यम से किसानों को खेती की नई-नई तकनीकों की जानकारी मिलने लगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का उपयोग भी सतत रूप से किया जा रहा है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, चुनौती भरे इस समय में भी सरकार की मंशा के अनुसार कार्य कर रहा है और किसानों एवं कृषि विद्यार्थियों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। विश्वविद्यालय का प्रयास है कि आगे भी इस दिशा में सकारात्मक प्रयास हो, इसके मद्देनजर कुलपति के नेतृत्व में भविष्य की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है।

सामाजिक सरोकारों में भी निभाई प्रभावी भूमिका

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना संक्रमण के इस दौर में सामाजिक सरोकारों पर खरा उतरने का भी पूर्ण प्रयास किया गया है। विश्वविद्यालय के सभी कार्मिक स्वस्थ रहें, इसके मद्देनजर कुलपति की पहल पर सबसे पहले विश्वविद्यालय में कोरोना जांच शिविर आयोजित किया गया। फिर सभी कार्मिकों को जिला प्रशासन एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं क सहयोग से मास्क, ग्लब्ज एवं सेनेटाइजर वितरित किए गए। आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। समूचे विश्वविद्यालय परिसर को कई बार सैनेटाइज किया गया। इसके बाद 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी कार्मिकों के लिए डेडिकेटेड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी सोशल रिसपोंसिबिलिटी के तहत गोद लिए गए गुसाईसर गांव में भी कोरोना के विरूद्ध जागरूकता की सतत गतिविधियां आयोजित की गई। मास्क, ग्लब्ज, सेनेटाइजर आदि भी वितरित किए जा रहे है। •

'पिछले तैतीस वर्षों से अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने कोरोना संक्रमण की बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सकारात्मक कार्य करने का प्रयास किया है। इस दौरान ऑनलाइन माध्यम को अपनाते हुए विश्वविद्यालय ने अनेक नवाचार किए। हालांकि इस दौरान अन्य गतिविधियां भी चलती रहीं। विश्वविद्यालय ने अनेक उच्चस्तरीय संस्थानों के साथ एमओयू किए। निकट भविष्य में इनका लाभ परिलक्षित होगा। विश्वविद्यालय के इन्हीं प्रयासों की बदौलत विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों को आइएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। हमारा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र के किसानों को अधिक से अधिक लाभ हों। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों का नियमित मार्गदर्शन किसानों को मिले ताकि वे सशक्त और समृद्ध हों।'

– प्रो. आर. पी. सिंह
कुलपति, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल

बदल रहे है प्रदेश में शिक्षा की तस्वीर

– अमनदीप
जनसम्पर्क अधिकारी

जहां एक समय पर राजकीय विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता के प्रति संशय व्यक्त किया जाता था वहीं आज इस धारणा में सकारात्मक परिवर्तन घटित होता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस परिवर्तन के मुख्य स्रोत बन कर उभरे हैं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। आधुनिक परिसर युक्त व शिक्षा संसाधन सम्पन्न स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल राज्य के 134 ब्लॉक में शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात, हाउस सिस्टम, आदर्श शैक्षिक वातावरण, प्रासंगिक व रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम, दिव्यागों के लिए समन्वित शिक्षा, बालिका शिक्षा, स्कूलों में आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) का उपयोग, मॉडल स्कूलों की मुख्य विशेषताएं हैं।

स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल आइसीटी लैब, वर्चुअल व स्मार्ट क्लासरूम, इंग्लिश लैब, के-यान प्रोजेक्टेर, डिजिटल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरा व सेन्ट्रलाइज्ड साउण्ड सिस्टम से युक्त है तथा गरीब परिवार से आने वाले विद्यार्थियों को निजी स्कूलों के समान शैक्षिक सुविधाएं सुलभ करा रहे हैं।

134 मॉडल स्कूलों में से 71 स्कूलों में विज्ञान क्लब व स्टार्ट अप बूस्ट क्लब का सचांलन किया जा रहा है जो एक भविष्योन्मुखी सोच का परिचायक है। अधिकांश मॉडल स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की गयी हैं जिनमें विद्यार्थी तकनीकी एवं वैज्ञानिक कौशल सीखते हैं। इन लैब्स में विद्यार्थियों को उन्नत यंत्रों व उपकरणों के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की अवधारणाओं को समझने का अवसर मिलता है। ये लैब्स - विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स से सम्बंधित उपकरणों, ओपन-सोर्स माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड, सेंसर और 3 डी प्रिंटर और कंप्यूटर से युक्त हैं।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु मॉडल स्कूलों में 55 प्रतिशत सीट बालिकाओं हेतु आरक्षित रखी गयी है तथा कक्षा 6 से 12 की छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा प्रदान की गयी है। छात्राओं हेतु सैनेटरी नैपकिन, डिस्पेंसर व इन्सीनरेटर भी उपलब्ध कराये जाते हैं। मॉडल स्कूल की 10वीं की छात्राओं को सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर विदेश में चार साल पढ़ने का मौका मिलता है जिसका सारा खर्चा सरकार वहन करती है।

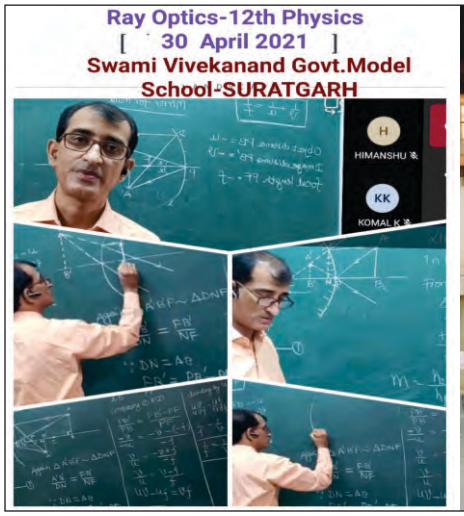

मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता हैं तथा प्रत्येक विद्यार्थी हेतु स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु मॉडल स्कूलों में विभिन्न पाठ्यतर गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। क्लस्टर एवं स्टेट लेवल पर मॉडल स्कूलों में आर्ट एण्ड क्राफ्ट प्रतियोगिता, सोशल साईंस एक्जीबिशन, साईंस फेयर, मेथ्स ऑलम्पियाड, इग्लिश एवं हिन्दी एक्सटेम्पोर तथा अंग्रेजी नाटक का आयोजन किया जाता है जिनमें भाग लेने से विद्यार्थियों में रचनात्मकता और आत्मविश्वास का विस्तार होता है।

निजी स्कूलों की तर्ज पर विद्यार्थियों को वर्ष में चार बार एक्सपोजर विजिट पर ले जाया जाता है तथा ग्रीष्मावकाश मे अभिरुचि कक्षाओं का संचालन होता है। इसके अलावा सभी मॉडल स्कूलों में स्कूल बैंड है तथा बैंड प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। प्रतिमाह मॉडल स्कूलों में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित की जाती है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के अनेक छात्र जेईई व नीट जैसी कठिन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके आईआईटी और एम्स जैसे देश के प्रतिष्ठित सस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं जो राज्य के लिये गौरव का विषय है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों का शत-प्रतिशत वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

विवेकानंद मॉडल स्कूल ने दी हिमांशु के सपनों को एक नई उडान

कहते हैं कि शिक्षा में किया गया निवेश सर्वाधिक लाभकारी प्रतिफल देता है। गंगानगर जिले के सूरतगढ़ ब्लॉक में स्थित राजकीय विवेकानंद मॉडल स्कूल वर्षो से इसी वाक्य को चरितार्थ कर रहा है। इसका एक उत्तम उदाहरण है जिले के छोटे से गांव जैतपुर से सम्बन्ध रखने वाले हिमांशु मक्कड जो शुरू से ही मेधावी छात्र थे। दसवीं कक्षा पास करने के बाद समान्य परिवार से आने वाले हिमांशु के सामने एक बडी दुविधा थी। एक तरफ निजी स्कूलों की भारी भरकम फीस थी, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा ना होने की प्रचलित छवि। परन्तु जब हिमांशु ने राजकीय विवेकानंद मॉडल स्कूल, सूरतगढ़ में प्रवेश लिया तो ना सिर्फ ये धारणा टूटी अपितु इस प्रतिभाशाली छात्र के जीवन में शैक्षिक एवं व्यक्तिगत प्रगति के एक नये अध्याय का सूत्रपात हुआ।

अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस विद्यालय ने हिमांशु के सपनों को एक नयी उड़ान दी। किसी भी निजी विद्यालय परिसर से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम राजकीय मॉडल स्कूल, सूरतगढ़ के भव्य परिसर में एक ओर हिमांशु को वर्तमान की पेशेवर आवश्यकताओं के अनुरूप अंग्रेजी व आईटी के विशिष्ट अध्ययन का अवसर मिला वहीं सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यतर गतिविधियों में भी भाग लेने का मौका मिला। बस फिर क्या था, शिक्षकों ने हिमांशु की प्रतिभा को परिलक्षित किया तथा संसाधनों की उपलब्धता ने मार्ग को सहज। वर्ष 2020 में टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज और कर्नाटक सरकार के आईटी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित नेशनल रूरल आई टी क्विज में हिमांशु ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल कर राजस्थान का नाम आईटी हब बेंगलुरु में रोशन किया। इस उपलक्ष्य में उन्हें 1 लाख रुपये की छात्रवृत्ति मिली। हिमांशु ने अपनी इस असाधारण उपलब्धि का श्रेय विद्यालय की आईसीटी लैब व अपने व्याख्याता श्री सुरेश राजपुरोहित को दिया। शिक्षकों की प्रेरणा से हिमांशु अब एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि शीघ्र ही वे एक सैन्य अधिकारी के रूप में देश की सेवा करते दिखाई दे।

ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले राजकीय विद्यालय के छात्र का नेशनल आईटी क्विज में प्रथम स्थान प्राप्त करना इस विद्यालय में शिक्षा के स्तर का एक जीवन्त उदाहरण है। यह विद्यालय गत वर्ष सोशल साइंस फेयर में राज्य भर में प्रथम रहा तथा इंटर स्कूल बैंड कम्पीटिशन इवेंट्स में विगत वर्ष फलोदी, जोधपुर में मॉडल स्कूल सूरतगढ़ की बालिका टीम राज्य स्तरीय विजेता रही।

यही नहीं माननीय प्रधानमंत्री से परीक्षा की चर्चा कार्यक्रम में प्रथम सवाल भी विद्यालय की छात्रा यशश्री ने ही पूछा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप के जरिए पिछले लॉकडाउन के समय से ही मॉडल स्कूल के शिक्षक राजेंद्र के नेतृत्व में पूरी टीम ऑनलाइन अध्यापन में समर्पित भाव से जुटी हुई है। विद्यालय में खेल प्रतिभाएं तराशने हेतु परिसर में रेतीले टीले के समतलीकरण के लिये प्रधानाचार्य श्री बजरंग लाल भादू ने 21000 रुपये ज्ञान संपर्क पोर्टल के द्वारा भेंट किए। भामाशाहों के सहयोग तथा विद्यालय प्रशासन के सघन प्रयासों से खेल मैदान एवं गार्डन विकसित करने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। •

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान

– प्रकाश चंद्र शर्मा
स्वतंत्र पत्रकार

राजस्थान के पूर्वांचल का सिंह द्वार भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के कारण विश्व पटल पर है। इस राष्ट्रीय अभयारण्य को विदेशी पक्षियों के प्रवास ने वर्ष 1981 में नेशनल पार्क का दर्जा दिलाया था। तब से लेकर आज तक इसे यूनेस्को की निरंतर आर्थिक सहायता मिल रही है।

वर्ष 1964 से साइबेरियन पक्षियों के लगभग 100 जोड़े हर वर्ष इस उद्यान में लंबा प्रवास कर अपना वंश बढ़ाते थे लेकिन पानी की भारी किल्लत के चलते इनकी इस पार्क से अब बेरुखी बढ़ी है।

राजस्थान सरकार ने इस राष्ट्रीय उद्यान के लिए चंबल नदी से 65 एमसीएफटी व गोवर्धन ड्रेन से 450 एमसीएफटी पानी उपलब्ध करवाकर इस उद्यान की जलापूर्ति को लगभग पूरा कर दिया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट सत्र में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए चंबल नदी से डेडिकेटेड पाइपलाइन डालने की भी घोषणा की है जो कि बहुत ही सराहनीय पहल है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की इस तरह की घोषणा निश्चय ही वन्य जीवों के लिए जीवनदान साबित होगी। इस योजना की डीपीआर बनाने के भी आदेश जारी हो चुके हैं। 29 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभयारण्य अपने आप में अनूठा है।

यूनेस्को की ओर से घोषित दुनिया के हेरिटेज क्षेत्रों में से यह एक है। यहां वृक्ष,झाड़ और घास के अलग-अलग क्षेत्र तो हैं ही,एक साथ भी हैं। इसके अलावा दलदली इलाके भी हैं। सारसों के लिहाज से तो यह दुनिया का सबसे समृद्ध पक्षी उद्यान है।

साइबेरिया से सारसों के झुंड 6 हजार किलोमीटर से ज्यादा का

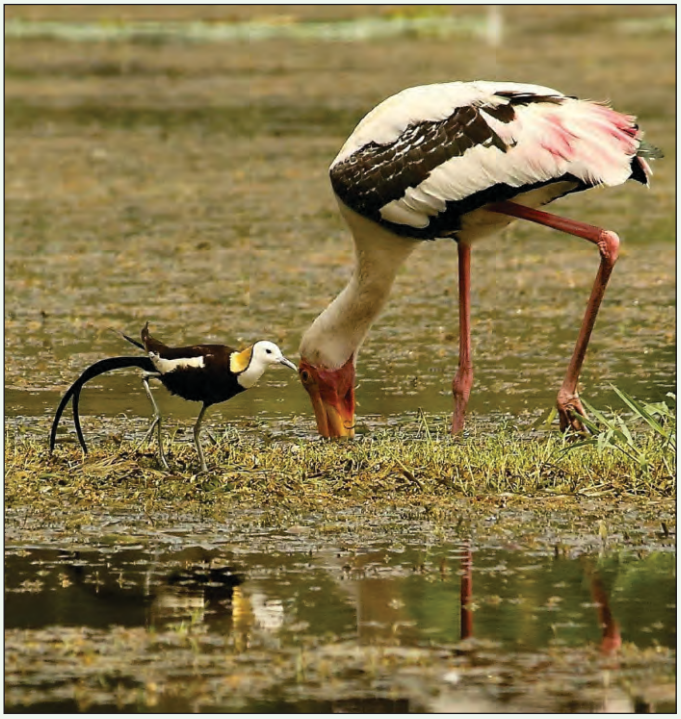

सफर तय करके ईरान के अलावा यही आते रहे हैं। हम कई वर्षों के आंकड़ों के साथ ताजा हालातों पर गौर करें तो देशी-विदेशी कुल परिंदों की तादात यहां एक लाख के करीब मानी जाती रही है। जबकि जंगली जीव जंतुओं की गिनती अलग है। मसलन करीब 3000 चीतल,800 सियार,300 जंगली सूअर, इतने ही अजगर आदि हैं।

पहले इन सबके लिए पानी का संकट रोड़ा बना हुआ था। लेकिन राज्य सरकार के प्रयास से अब पानी का संकट दूर हो गया है। पार्क के बजूद को बचाए रखने के लिए जो दिक्कत पानी की आ रही थी वो अब दूर होने लगी है। कई बुजुर्ग लोगों का कहना है कि करौली जिले में पांचना बांध बनने से पूर्व केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कभी प्यासा नहीं रहा। उस वक्त इसकी सारी झीलें जल प्लावित रहती थी। लेकिन बांध बनने के बाद केवलादेव में दिक्कत आ गई थी।

अब राज्य सरकार ने इस दिक्कत को दूर कर दिया है। गर्मियों के समय में पक्षी अपने वतन को लौट जाते हैं। सितम्बर-अक्टूबर में घना प्रवास पर पक्षी आ जाते हैं। लेकिन गत वर्ष से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण पक्षियों की भांति टूरिस्ट भी घट गए हैं। वहीं कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर ने तो अब मानो इस अभयारण्य के गेट पर ताला ही जड़ दिया हो।

कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान केवलादेव घना अभयारण्य में देशी-विदेशी पर्यटकों व स्थानीय लोगों का आवागमन बंद है। इससे पार्क का राजस्व घट गया है। पिछले साल यहां हजारों की संख्या में पक्षी आए थे लेकिन कोरोना वायरस के कारण यहां कुछ ही विदेशी पर्यटक आए। वही देशी पर्यटकों का सिलसिला भी कुछ खास नहीं रहा। यह बात जरूर है कि सरकार की ओर से जैसे ही पाबंदियां हटाई गई उसके उपरांत पर्यटकों का आगमन शुरू हुआ था।

पार्क में पर्यटकों की घटती संख्या से रिक्शा चालक, नेचर गार्ड आदि का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। जबसे विदेशी पर्यटकों का आना बंद हुआ है तबसे विदेशी मुद्रा के साथ ही होटल-मोटेल्स की भी आमदनी पर असर पड़ा है।

इस पार्क में हिरन, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली बिल्ली आदि काफी संख्या में दिखाई देते हैं। अंतरराष्ट्रीय पटल पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपनी विशिष्ट पहचान रखता है।•

बांसवाड़ा के प्राकृतिक झरने

– कल्पना डिंडोर
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

राजस्थान के चेरापूंजी के नाम से विख्यात बांसवाड़ा जिला प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक, रमणीक, धार्मिक एवं कलात्मक दृष्टि से परिपूर्ण है। जंगल एवं पानी की प्रचुरता के कारण इसे राजस्थान का 'चेरापूंजी' कहा जाता है। वागड़ क्षेत्र को समृद्ध करने वाली 'वागड़-गंगा' जिसे माही सागर कहा गया है। माही बांध के कारण बने टापुओं को ''सिटी ऑफ हण्ड्रेड आईलैण्ड्स'' के नाम से जाना जाता है।

माही बांध वागड़ विकास की अविस्मरणीय सौगात है। बांसवाड़ा से 18 किमी. की दूरी पर संभाग का यह सबसे बड़ा बांध है। जिसमें 16 गेट हैं। बांध की कुल लम्बाई 3.10 किमी. है। वर्षाकाल में जब यह पूर्ण भर जाता है तब सभी गेट खोलने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका नजारा अनुपम और मनोहारी होता है। इसे देखने को पूरे वर्ष सैलानी इंतजार करते हैं।

बांसवाड़ा मानसून की मेहरबानी से वागड़ अंचल के कई इलाके हरे-भरे हो जाते हैं। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित बांसवाड़ा जिला किसी पर्यटन स्थल से कम नजर नहीं आता है। जिले में बारिश के समय जगह-जगह झरने बहने लग जाते हैं। चारों तरफ छाई हरियाली और उनके बीच बहते झरने बरबस मन को मोह लेते हैं।

जिले में अनगिनत झरने हैं जिनमें कडेलिया झरना, सिंगपुरा झरना, जुआफाल झरना, समाईमाता, झोल्लापाल झरना, भाटिया महादेव, उंडवेला झरना प्रमुख हैं।

झरने यूं तो सभी को आकर्षित करते हैं लेकिन यह ज्यादातर बारिश के दिनों में ही शुरु होते हैं। बांसवाड़ा में भी 15 से ज्यादा ऐसे झरने हैं जो सिर्फ बारिश में ही शुरु होते हैं लेकिन एक ऐसा झरना है जो बारिश के अलावा सर्दी और गर्मी के मौसम में चलता है। पांच स्टेप में बना यह झरना काफी आकर्षक है। शहर से महज 3 किमी. की दूरी पर बाई तालाब के पास बना यह प्राकृतिक झरना है। दरअसल झरना तब बनता है जब कागदी पिकअप को भरा जाता है। शहर का प्रमुख प्राकृतिक, रमणीक स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। यहां बच्चों के मनोरंजन हेतु पार्क, झूले, तरणताल, नौकायन की सुविधा उपलब्ध है।

महारावल जगमाल सिंह की रानी लांची बाई द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था। बाई तालाब के नाम से लोकप्रिय यह मीठे पानी की कृत्रिम झील है। यह झील बांसवाड़ा के पूर्वी भाग में स्थित है तथा यहां कल्प वृक्ष भी हैं। इसके करीब ही छतरियां व स्मारक भी बने हुए हैं।

बांसवाड़ा का 'जुआ फॉल्स' देखने के लिए सबसे अच्छा समय बारिश का मौसम है, तब यहां प्राकृतिक रूप से पहाड़ियों से निकलने वाले झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। शांत और निर्मल वातावरण में रोजाना की भाग-दौड़ भरे जीवन में कुछ पल सुकून के बिताने के लिए यहां आकर आपको आराम करने और घूमने का भरपूर मौका मिलता है। 'जुआ फॉल्स' को देखने और यहां के दृश्यावलोकन को यादगार बनाने के लिए यहां पर आना सार्थक रहता है।

'सिंगपुरा' बांसवाड़ा शहर से लगभग 10 किमी. दूर स्थित पहाड़ियों से घिरा यह स्थान हरियाली का मोर्चा लिए होता है। सिंगपुरा में एक सुन्दर झील है, छोटी पहाड़ियां हैं, जहां जंगल और चारों ओर हरियाली नजर आती है।

तलवाड़ा से 3 किमी. की दूरी पर प्राचीन तीर्थस्थल रामकुण्ड है। चट्टानों से बनी बड़ी गुफाओं में शिवलिंग एवं अन्य प्रतिमाएं हैं। गुफा के तल में जलकुण्ड है जिसे 'रामकुण्ड' कहा जाता है। ऊपर से देखने पर एक पहाड़ी है जहां बरसात में हरियाली एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से पूर्ण यह स्थल मनोहारी है। यहां एक बड़ी गुफा भी है। बरसात के मौसम में जलकुण्ड पूरा भर जाता है।

कई किलोमीटर तक अथाह जलराशि का नजारा यहां देखते ही बनता है। यहां कई मकान ऐसे हैं जो इस जलराशि के बीच टापुओं में हैं जिनका मुख्य सड़क तक आना-जाना नावों से होता है। यहां के बाशिन्दों का ''जल ही जीवन'' है। इसके अलावा जल भराव क्षेत्र बरसात के दिनों में टापू में तब्दील हो जाते हैं। क्षेत्र कई किलोमीटर में है। शहर से 3 किमी. की दूरी पर भण्डारिया हनुमानजी का प्रसिद्ध मंदिर है जो देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है। पहाड़ी की तलहटी में स्थित प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण शहर से दूर सुरम्य वातावरण में मन को शांति प्रदान करता है।

भण्डारिया हनुमानजी मंदिर के रास्ते पहाड़ी पर स्थित समाईमाता का प्रसिद्ध मंदिर है। जहां पर नवरात्रि में श्रद्धालु आते हैं तथा पहाड़ से शहर का नजारा देखते हैं। यह स्थल बारिश के मौसम में मनोहारी रूप धारण कर लेता है और सैलानी यहां आकर सुकून ही महसूस नहीं करते बल्कि शहर का विहंगम दृश्य देखकर प्रफुल्लित भी हो उठते हैं। अब समाईमाता मंदिर तक सड़क बन गई है जहां वाहनों से लोगों का पहुंचना आसान हो गया है।

कोरोना महामारी सहायता संबंधी
जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी एवं दूरभाष नम्बर
https://covidinfo.rajasthan.gov.in/

जिला	प्रभारी अधिकारी का नाम	पद	मोबाईल नं.	कन्ट्रोल/वॉर रूम (24X7)	कन्ट्रोल रूम (मेडिकल)(24X7)
अजमेर	कैलाश चंद्र शर्मा	एडीएम (प्रशा.)	9414036291	0145-2422517	0145-2631111
अलवर	रामचरण शर्मा	एडीएम (प्रथम)	9414017788	0144-2338000	0144-2340145
बांसवाड़ा	नरेश बुनकर	एडीएम	9460581403	02962-248420	7742120333 02962-251303
बारां	मो. अबू बकर	एडीएम	9414345764	07453-237081	07453-230451
बाड़मेर	ओमप्रकाश बिश्नोई	एडीएम	9799409229	02982-222226	02982-230462
भरतपुर	बीना महावर	एडीएम (प्रशा.)	9875073829	05644-220388	05644-223660
भीलवाड़ा	वन्दना खोरवाल	एडीएम (सिटी)	9587278104	01482-233032 01482-233035	01482-232643
बीकानेर	बलदेव राम धोजक	एडीएम (प्रशा.)	9414402735	0151-2226031	0151-2204989
बूंदी	श्याम सुन्दर व्यास	एडी (सांख्यिकी)	9413860624	0747-2442305	0747-2442895
चित्तौड़गढ़	रतन कुमार स्वामी	एडीएम (प्रशा.)	9521140050	01472-294411	01472-240088
चूरू	पारस राम मीना	एडीएम (प्रशा.)	9829345921	01562-251322	01562-294082
दौसा	लोकेश मीना	एडीएम	9680024241	01427-224903	7891510014
धौलपुर	नरेन्द्र कुमार वर्मा	एडीएम	9680697887	05642-220033	05642-220733
डूंगरपुर	कृष्णपाल सिंह चौहान	एडीएम	9460077701	02964-232262	02964-232486
हनुमानगढ़	अशोक आसीजा	एडीएम	9413381666	01552-260299	01552-261190
जयपुर	इकबाल खान	एडीएम	9829871144	0141-2204475	0141-2605858 0141-2603426
जैसलमेर	हरि सिंह मीना	एडीएम	9414056825	02992-250082	02992-294116
जालौर	छगन लाल गोयल	एडीएम	9414349119	02973-222216	02973-222246
झालावाड़	दाताराम	एडीएम	9414219570	07432-230645 07432-230646	07432-233279 07432-230009
झुंझुनूं	जगदीश प्रसाद गौड़	एडीएम	9414302990	01592-232237	01592-232415
जोधपुर	नकत दान बारहठ	आर.ए.ए.	9414493111	0291-2555560	0291-2511085
करौली	सुदर्शन सिंह तोमर	एडीएम	9828410620	07464-251335	07464-297031 9414779899
कोटा	आर. डी. मीना	एडीएम	9414284703	0744-2323557	0744-2450260 0744-2329259
नागौर	मनोज कुमार	एडीएम	9928876968	01582-241057	01582-240844
पाली	चन्द्रभान सिंह भाटी	एडीएम	9414493101	02932-252804 02932-225380	02932-257555
प्रतापगढ़	गोपाल लाल स्वर्णकार	एडीएम	8769042373	01478-222333	01478-222564
राजसमन्द	कुशल कुमार कोठारी	एडीएम	9460803322	02952-222585	02952-221716
सवाई माधोपुर	डॉ. सुरज सिंह नेगी	एडीएम	9660119122	07462-220602	07462-235011
सीकर	धारासिंह मीणा	एडीएम	9785420044	01572-251008	01572-248211
सिरोही	गितेश श्रीमालवीय	एडीएम	9462020670	02972-225327 02972-221240	02972-222259
श्रीगंगानगर	भवानी सिंह पंवार	एडीएम (ए)	9610723623	0154-2440988	0154-2445071
टोंक	एम.एल. शर्मा	एडीएम	9461321000	01432-247478	01432-244099
उदयपुर	ओ पी बुनकर	एडीएम (प्रशा.)	9414254639	0294-2414620	6367304312

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

महामारी रेड अलर्ट - जन अनुशासन

लॉकडाउन अपील

"प्रिय प्रदेशवासियों,

मुझे खुशी है कि आपने लॉकडाउन की पालना शुरु कर दी है। आशा है इसे आप निरंतर जारी रखेंगे।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण का संकट निरंतर गहराता जा रहा है। शहरों के साथ-साथ गांवों और युवाओं में भी तेजी से फैल रहा है। पहली लहर के मुकाबले इस दूसरी घातक लहर में मौतें भी ज्यादा हो रही हैं। संक्रमण के बाद शहर तक इलाज के लिए पहुंचते-पहुंचते लोगों की मौत हो रही है।

राज्य सरकार प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए वित्तीय संसाधनों की भी कोई कमी नहीं रखी जा रही है, लेकिन कोरोना का संक्रमण जिस गति से फैल रहा है, उसे देखते हुए यह बेहद जरूरी है कि जनता इसके प्रसार को रोकने के लिए स्व अनुशासन में रहे और महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन की पूरी तरह पालना करे, अन्यथा हम कितने ही संसाधन जुटा लें, हमारे सभी प्रयास कम पड़ते चले जाएंगे।

संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ही हमने प्रदेशभर में 3 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के दौरान विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं दी गई है। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए विवाह समारोह को 31 मई, 2021 तक स्थगित किए जाने की सलाह दी गई है। अति आवश्यक होने पर विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेबपोर्टल covidinfo.rajasthan.gov.in पर देनी होगी।

विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि बड़ी संख्या में लोगों ने स्व विवेक से निर्णय कर शादियां स्थगित की हैं, मेरी आपसे विनम्र अपील है कि अन्य लोग भी इस पहल में भागीदार बनकर कोविड की चुनौती से लड़ने में राज्य सरकार का सहयोग करें।

मेरा आप सबसे यह भी आग्रह है कि कोविड के इस दौर में सभी धर्म के लोग धार्मिक रीति-रिवाजों, त्योहार, उत्सव आदि के कार्यक्रमों को घर पर ही रहकर मनाएं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थलों पर नहीं जाए, घर से ही पूजा, इबादत एवं प्रार्थना करें ताकि संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके।

हमारे समन्वित प्रयासों से ही हम कोरोना की इस कठिन जंग को जीतने में कामयाब हो सकेंगे।

आपके सहयोग और विश्वास की अपेक्षा के साथ"

'निज पर शासन, फिर अनुशासन'

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री

महामारी रेड अलर्ट – जन अनुशासन लॉकडाउन की गाइडलाइंस की पालना करें

सभी जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक 'नो मास्क-नो मूवमेंट' की सख्ती से पालना सुनिश्चित करेंगे।

18 वर्ष व उससे अधिक आयु वाले वैक्सीन जरूर लगवाएं • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं

टोल फ्री 104/108 | पहनिए मास्क | धोइए हाथ | रखिए दो गज दूरी | कोरोना वॉर रूम 181

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

धरोहर

बाला किला

– कृष्णकान्ता शर्मा
उप निदेशक, पुरातत्त्व एवं संग्रहालय

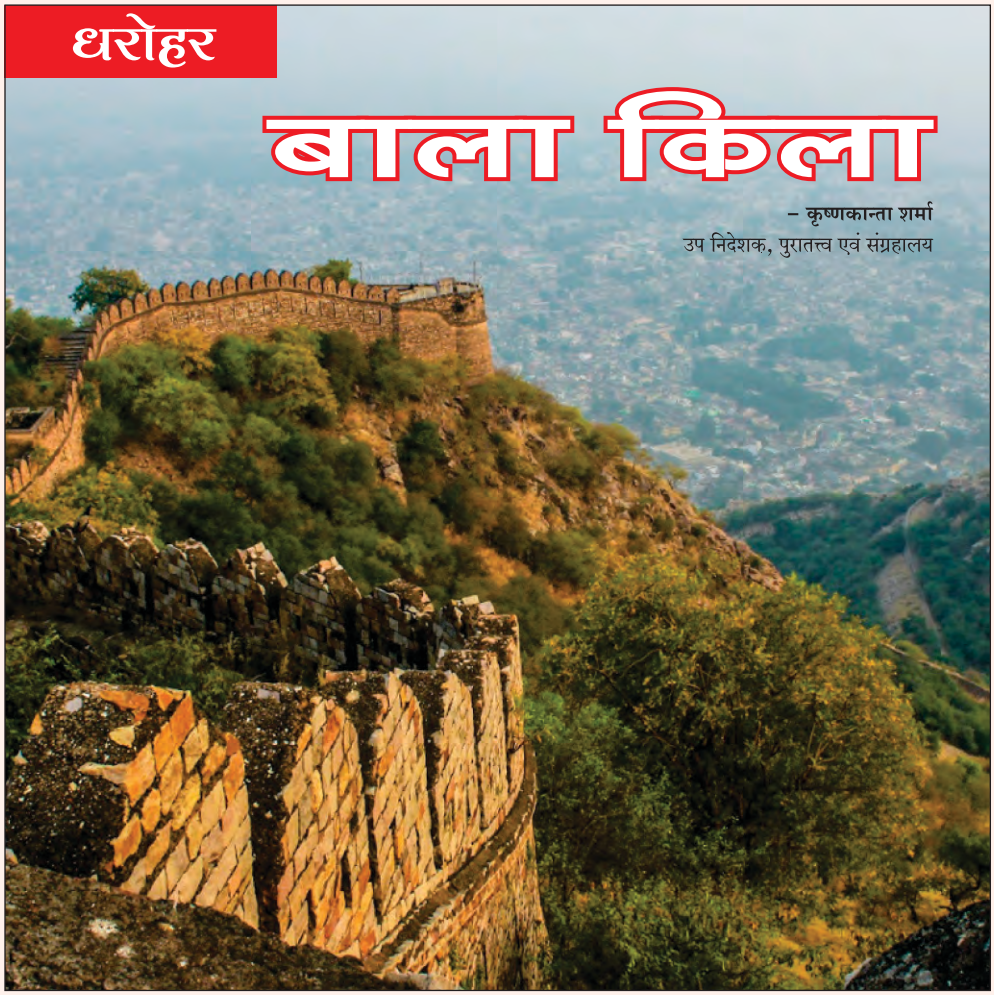

अरावली पर्वतश्रृंखला की ऊंची पहाड़ी पर स्थित अलवर का ''बाला किला'' ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण दुर्ग है।

बाला किला पहाड़ी पर स्थित है। समुद्र तल से 1960 फीट और समतल भूमि से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस दुर्ग की लम्बाई उत्तर से दक्षिण 3 मील और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 1 मील है । यह किला पन्द्रह बड़ी और बावन छोटी बुर्जो को माला की तरह पिरोती सात मील की कंगूरेदार प्राचीर से घिरा हुआ है। बुर्ज और प्राचीर में कुल तीन हजार तीन सौ उनसठ कंगूरे हैं, जिनमें प्रत्येक में दो छिद्र हैं। किले के मुख्य महल में अलवर शैली के भित्तिचित्रों की छटा दर्शनीय है। जनाना महल का स्थापत्य भी आकर्षक है। महल के सामने पूर्व की ओर बनी बुर्ज पर खड़े होकर जब हम किले की तलहटी में दूर तक फैले पसरे अलवर शहर को देखते हैं तो मन रोमांच से भर उठता है।•

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक–सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित सम्पादक– डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा • मैसर्स प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस, 12, मित्र नगर, हवा सड़क, रामनगर, सोडाला, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'–पृष्ठ संख्या 60, मूल्य 20 रुपये/ 60,000 प्रतियां